



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 2]

नई दिल्ली, जनवरी 7—जनवरी 13, 2018, शनिवार/ पौष 17—पौष 23, 1939

No. 2]

NEW DELHI, JANUARY 7—JANUARY 13, 2018, SATURDAY/PAUSHA 17—PAUSHA 23, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India  
(Other than the Ministry of Defence)

विदेश मंत्रालय

(सी.पी.वी. प्रभाग)

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2018

**का.आ. 30.**—राजनयिक और कौंसुलीय अधिकारी (शपथ एवं फीस) के अधिनियम, 1948 (1948 का 41) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में वैधानिक आदेश।

एतद्वारा केंद्र सरकार भारत के दूतावास, बैरूत में श्री दिलीप कौल, सहायक अनुभाग अधिकारी को दिनांक 3 जनवरी, 2018 से सहायक कौंसुलर अधिकारी के तौर पर कौंसुलर सेवाओं के निर्वहन के लिए प्राधिकृत करती है।

[सं. टी-4330/01/2016]

प्रकाश चन्द, निदेशक (कौंसुलर)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(C.P.V. DIVISION)

New Delhi, the 3rd January, 2018

**S.O. 30.**—In pursuance of the clause (a) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby appoints Shri Dileep Koul, Assistant Section Officer as

Assistant Consular Officer in Embassy of India, Beirut to perform the Consular services as with effect from 3rd January, 2018.

[No. T-4330/01/2016]

PRAKASH CHAND, Director (Consular)

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2018

**का.आ. 31.**—राजनयिक और कौंसुलीय अधिकारी (शपथ एवं फीस) के अधिनियम, 1948 (1948 का 41) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में वैधानिक आदेश। एतद्वारा केंद्र सरकार भारत के प्रधान कौंसलावास, जेद्दाह में श्री सुनील श्री कर्ण, निजी सहायक को दिनांक 8 जनवरी, 2018 से सहायक कौंसुलर अधिकारी के तौर पर कौंसुलर सेवाओं के निर्वहन के लिए प्राधिकृत करती है।

[सं. टी-4330/01/2015]

प्रकाश चन्द, निदेशक (कौंसुलर)

New Delhi, the 8th January, 2018

**S.O. 31.**—In pursuance of the clause (a) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby appoints Shri SUNIL S. KARN, Personal Assistant as Assistant Consular Officer in Consulate General of India, Jeddah to perform the Consular services as with effect from 8th January, 2018.

[No. T-4330/01/2015]

PRAKASH CHAND, Director (Consular)

### वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2017

**का.आ. 32.**—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1980 के खंड (9) के उप-खंड (2) की मद (ख) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री शैलेश रामजी घेदिया (जन्म तिथि: 25.04.1957) को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पंजाब एंड सिंध बैंक के निदेशक मण्डल में सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट) श्रेणी के अंतर्गत अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा.सं. 6/1/2015-बीओ-I]

ज्ञानोत्तोष राय, अवर सचिव

### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

New Delhi, the 27th December, 2017

**S.O. 32.**—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980) read with item (b) of sub-clause (2) of clause (9) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, the Central Government, hereby nominates Shri Shailesh Ramji Ghedia (DoB: 25.4.1957) as Part-time Non-official Director under Chartered Accountant category on the Board of Directors of Punjab & Sind Bank for a period of three years, from the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/1/2015-BO-I]

JNANATOSH ROY, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2017

**का.आ. 33.**—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1980 के खंड (9) के उप-खंड (2) की मद (ख) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री बालगोपाल महापात्रा (जन्म तिथि: 12.07.1959) को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, आन्ध्रा बैंक के निदेशक मण्डल में सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट) श्रेणी के अंतर्गत अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा.सं. 6/1/2015-बीओ-1]

ज्ञानतोष राय, अवर सचिव

New Delhi, the 27th December, 2017

**S.O. 33.**—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980) read with item (b) of sub-clause (2) of clause (9) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, the Central Government, hereby nominates Shri Balgopal Mahapatra (DoB: 12.7.1959) as Part-time Non-official Director under Chartered Accountant category on the Board of Directors of Andhra Bank for a period of three years, from the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/1/2015-BO-I]

JNANATOSH ROY, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2017

**का.आ. 34.**—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1980 के खंड (9) के उप-खंड (2) की मद (ख) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री के. श्रीनिवास मूर्ति (जन्म तिथि: 19.11.1964) को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, कापॉरेशन बैंक के निदेशक मण्डल में सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट) श्रेणी के अंतर्गत अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा.सं. 6/1/2015-बीओ-1]

ज्ञानतोष राय, अवर सचिव

New Delhi, the 27th December, 2017

**S.O. 34.**—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980) read with item (b) of sub-clause (2) of clause (9) of The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, the Central Government, hereby nominates Shri K. Srinivasa Murthy (DoB: 19.11.1964) as Part-time Non-official Director under Chartered Accountant category on the Board of Directors of Corporation Bank for a period of three years, from the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/1/2015-BO-I]

JNANATOSH ROY, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2017

**का.आ. 35.**—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खंड (9) के उप-खंड (2) की मद (ख) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री दिनेश सिंह (जन्म तिथि: 22.10.1969) को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, युनाइटेड बैंक आफ इंडिया के निदेशक मण्डल में सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट) श्रेणी के अंतर्गत अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा.सं. 6/1/2015-बीओ-1]

ज्ञानतोष राय, अवर सचिव

New Delhi, the 27th December, 2017

**S.O. 35.**—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with item (b) of sub-clause (2) of clause (9) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, hereby nominates Shri Denesh Singh (DoB: 22.10.1969) as Part-time Non-official Director under Chartered Accountant category on the Board of Directors of United Bank of India for a period of three years, from the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/1/2015-BO-I]

JNANATOSH ROY, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2017

**का.आ. 36.**—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1980 के खंड (9) के उप-खंड (2) की मद (ख) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री विवेक सोनी (जन्म तिथि: 24.07.1962) को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, विजया बैंक के निदेशक मण्डल में सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट) श्रेणी के अंतर्गत अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा.सं. 6/1/2015-बीओ-I]

ज्ञानतोष राय, अवर सचिव

New Delhi, the 27th December, 2017

**S.O. 36.**—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980) read with item (b) of sub-clause (2) of clause (9) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, the Central Government, hereby nominates Shri Vivek Soni (DoB: 24.7.1962) as Part-time Non-official Director under Chartered Accountant category on the Board of Directors of Vijaya Bank for a period of three years, from the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/1/2015-BO-I]

JNANATOSH ROY, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2017

**का.आ. 37.**—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1980 के खंड (3) के उप-खंड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और उप-धारा (3-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री मधु सूदन दादु (जन्म तिथि: 05.06.1963) को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पंजाब एंड सिंध बैंक के निदेशक मण्डल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा.सं. 6/1/2015-बीओ-I]

ज्ञानतोष राय, अवर सचिव

New Delhi, the 27th December, 2017

**S.O. 37.**—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3-A) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, the Central Government hereby nominates Shri Madhu Sudan Dadu (DoB: 5.6.1963) as Part-time Non-official Director on the Board of Directors of Punjab & Sind Bank for a period of three years, from the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/1/2015-BO-I]

JNANATOSH ROY, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2017

**का.आ. 38.**—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खंड (3) के उप-खंड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और उप-धारा (3-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री आशीष साहा (जन्म तिथि: 08.10.1954) को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, यूको बैंक के निदेशक मण्डल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा.सं. 6/1/2015-बीओ-1]

ज्ञानोत्तोष राय, अवर सचिव

New Delhi, the 27th December, 2017

**S.O. 38.**—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3-A) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby nominates Shri Asish Saha (DoB: 8.10.1954) as Part-time Non-official Director on the Board of Directors of UCO Bank for a period of three years, from the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/1/2015-BO-I]

JNANATOSH ROY, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2017

**का.आ. 39.**—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खंड (3) के उप-खंड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और उप-धारा (3-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, सुश्री मधुर स्वामीनाथन (जन्म तिथि: 23.02.1961) को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, यूनियन बैंक आफ इंडिया के निदेशक मण्डल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा.सं. 6/1/2015-बीओ-1]

ज्ञानोत्तोष राय, अवर सचिव

New Delhi, the 27th December, 2017

**S.O. 39.**—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3-A) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby nominates Ms. Madhura Swaminathan (DoB: 23.2.1961) as Part-time Non-official Director on the Board of Directors of Union Bank of India for a period of three years, from the date of notification of her appointment or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/1/2015-BO-I]

JNANATOSH ROY, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2017

**का.आ. 40.**—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1980 के खंड (3) के उप-खंड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और उप-धारा (3-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री शिवरमन अनंत नारायण (जन्म तिथि: 29.09.1950) को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, इण्डियन ओवरसीज बैंक के निदेशक मण्डल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा.सं. 6/1/2015-बीओ-1]

ज्ञानोत्तोष राय, अवर सचिव

New Delhi, the 27th December, 2017

**S.O. 40.**—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3-A) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, the Central Government hereby nominates Shri Sivaraman Anant Narayan (DoB: 29.9.1950) as Part-time Non-official Director on the Board of Directors of Indian Overseas Bank for a period of three years, from the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/1/2015-BO-I]

JNANATOSH ROY, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2017

**का.आ. 41.**—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खंड (3) के उप-खंड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और उप-धारा (3-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री सिद्धार्थ प्रधान (जन्म तिथि: 12.06.1952) को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, युनाइटेड बैंक आफ इंडिया के निदेशक मण्डल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा.सं. 6/1/2015-बीओ-I]

ज्ञानतोष राय, अवर सचिव

New Delhi, the 27th December, 2017

**S.O. 41.**—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3-A) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby nominates Shri Sidhartha Pradhan (DoB: 12.6.1952) as Part-time Non-official Director on the Board of Directors of United Bank of India for a period of three years, from the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/1/2015-BO-I]

JNANATOSH ROY, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2017

**का.आ. 42.**—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खंड (3) के उप-खंड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और उप-धारा (3-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, डॉ. आत्मानंद (जन्म तिथि: 30.06.1959) को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के निदेशक मण्डल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा.सं. 6/1/2015-बीओ-I]

ज्ञानतोष राय, अवर सचिव

New Delhi, the 27th December, 2017

**S.O. 42.**—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3-A) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby nominates Dr Atmanand (DoB: 30.6.1959) as Part-time Non-official Director on the Board of Directors of Central Bank of India for a period of three years, from the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/1/2015-BO-I]

JNANATOSH ROY, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2017

**का.आ.43 .—**राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खंड (3) के उप-खंड (1) के साथ पठित बैंकारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और उप-धारा (3-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री सलिल कुमार झा (जन्म तिथि: 18.07.1953) को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, इंडियन बैंक के निदेशक मण्डल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा.सं. 6/1/2015-बीओ-I]

ज्ञानतोष राय, अवर सचिव

New Delhi, the 27th December, 2017

**S.O. 43.—**In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3-A) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby nominates Shri Salil Kumar Jha (DoB: 18.7.1953) as Part-time Non-official Director on the Board of Directors of Indian Bank for a period of three years, from the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/1/2015-BO-I]

JNANATOSH ROY, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2018

**का.आ. 44.—**भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39) की धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी के स्थान पर श्री राम मोहन मिश्रा, अपर सचिव एवं विकास आयुक्त, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय को तत्काल प्रभाव से अगले आदेशों तक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के निदेशक मंडल में सरकारी नामिती निदेशक नियुक्त करती है।

[फा.सं. 17/15/2017-आईएफ-II]

सौम्यजित घोष, अवर सचिव

New Delhi, the 1st January, 2018

**S.O. 44.—**In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of Section (6) of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (39 of 1989), the Central Government hereby appoints Shri Ram Mohan Mishra, Additional Secretary & Development Commissioner, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, as Central Government nominee Director on the Board of Directors of Small Industries Development Bank of India (SIDBI) with immediate effect vice Shri Surendra Nath Tripathi, until further orders.

[F. No. 17/15/2017-IF-II]

SOUMYAJIT GHOSH, Under Secy.

### स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2018

**का.आ. 45.—**जबकि, भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2013 की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 05 नवम्बर, 2013 को, भारतीय चिकित्सा परिषद् का पुनर्गठन किया गया था;

और जबकि भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उप-धारा (1) (ख) के प्रावधान के अनुसरण में, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद का प्रतिनिधित्व कर रहे डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा को 27.03.2014 से भारतीय चिकित्सा परिषद् के सदस्य के रूप में चुना गया था;

और जबकि भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में तथा संबंधित राज्य सरकार के साथ परामर्श करके केन्द्रीय सरकार ने डॉ. किशोर बी. ताओरी का देहान्त होने के कारण रिक्त हुए आकस्मिक पद पर इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से डॉ. किशोर बी. ताओरी की शेष अवधि अर्थात् 04.11.2018 तक के लिए डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा को भारतीय चिकित्सा परिषद् का सदस्य मनोनीत किया है।

और जबकि, डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने आईएमसी अधिनियम, 1956 की धारा 3(1)(क) के तहत राज्य का प्रतिनिधित्व करने हेतु एमसीआई का सदस्य बनने के लिए अपनी सहमति दे दी है और आईएमसी अधिनियम, 1956 की धारा 5(2) के अनुसार, कोई व्यक्ति एक ही समय पर सदस्य के रूप में एक से अधिक पदों पर नहीं रह सकता। अतः आईएमसी अधिनियम, 1956 की धारा 7(3) में निहित प्रावधानों के अनुसरण में आईएमसी अधिनियम, 1956 की धारा 3(1)(ख) के तहत तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद का प्रतिनिधित्व कर रहे डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा को भारतीय चिकित्सा परिषद् की सदस्यता समाप्त हो गई है।

अतः अब तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद का प्रतिनिधित्व कर रहे डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा की भारतीय चिकित्सा परिषद् की सदस्यता समाप्त मानी जाएगी।

और, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के प्रावधान के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्रालय की दिनांक 9 जनवरी, 1960 की सां.आ. 138 में भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सं. सां.आ. 3323 (ई) दिनांक 06 नवम्बर, 2013 में भारत सरकार की अधिसूचना तथा उसमें किए गए संशोधनों, अंतिम प्रविष्टि के पश्चात तथा उससे संबंधित प्रविष्टि में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, नामतः:

क्र.सं.	राज्य सरकार का नाम	नामित सदस्य का ब्यौरा
14	महाराष्ट्र	डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा

[सं. वी-11013/01/2016-एमईपी]

डी. बी. के. राव, अवर सचिव

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

New Delhi, the 5th January, 2018

**S.O. 45.**—Whereas on 5<sup>th</sup> November, 2013, the Medical Council of India was re-constituted in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the Indian Medical Council (Amendment) Ordinance, 2013;

And whereas in pursuance of the provision of sub-section (1)(b) of Section 3 of the Indian Medical Act, 1956 (102 of 1956), Dr. Ved Prakash Mishra was elected as a member of the Medical Council of India representing Teerthanker Mahaveer University, Moradabad with effect from 27.03.2014;

And whereas the Central Government, in pursuance of clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and in consultation with the respective State Government has nominated Dr. Ved Prakash Mishra to be a member of the Medical Council of India against the casual vacancy formed due to demise of Dr. Kishor B. Taori for the remainder of the term of Dr. Kishor B. Taori i.e. upto 04.11.2018 with effect from the date of issue of this notification.

And whereas Dr. Ved Prakash Mishra has given his consent to be a member of MCI representing the State under Section 3(1)(a) of IMC Act, 1956 and as per Section 5(2) of IMC Act, 1956, any person at the same time may not serve as a member in more than one capacity. Therefore, Dr. Ved Prakash Mishra has ceased to be a member of



Medical Council of India representing Teerthanker Mahaveer University, Moradabad under section 3(1)(b) of IMC Act, 1956 in accordance with the provisions contained in Section 7(3) of IMC Act, 1956.

Now, therefore, Dr. Ved Prakash Mishra shall be deemed to have ceased to be a member of the Medical Council of India representing Teerthanker Mahaveer University, Moradabad with effect from 04.01.2018.

And, therefore, in pursuance of the provision of sub section (1) of Section 3 of the said Act the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the then Ministry of Health number S.O. 138 dated the 9<sup>th</sup> January, 1960, namely;

In the notification of the Government of India in the Ministry of Health & Family Welfare number S.O. 3323(E) dated 06<sup>th</sup> November, 2013 and amendments thereto, after the last entry and entry relating thereto, the following shall be inserted, namely:

S. No.	Name of the State Government	Details of the Nominated Member
14.	Maharashtra	Dr. Ved Prakash Mishra

[No. V-11013/01/2016-MEP]

D. V. K. RAO, Under Secy.

### उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

(भारतीय मानक ब्यूरो)

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2017

**का.आ. 46.—** भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम 1988 के विनियम (4) के उपविनियम (5) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन लाइसेंसों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, वे स्वीकृत कर दिए गए हैं:-

#### अनुसूची

क्रम संख्या	लाइसेंस संख्या	स्वीकृत करने की तिथि	लाइसेंसधारी का नाम व पत्ता	भारतीय मानक का शीर्षक	भा मा	भाग	अनु	वर्ष
1.	एल-9512387222	03.08.2017	मै0 हिना इण्डस्ट्रीस (प्रा०) लि०, प्लॉट नं० 45, सैक्टर - 27ए, जिला फरीदाबाद - 121003, हरियाणा	खिजाब, तरल, जैल और क्रीम	8481	-	-	2001
2.	एल-9512386523	08.08.2017	मै0 आत्मा सो परमात्मा ट्रेडिंग, लोहारू रोड, सिवानी मण्डी, सिवानी, जिला भिवानी, हरियाणा	खडंजे के लिए पूर्व दलित कंक्रीट ब्लॉक	15658	-	-	2006

3.	एल- 9512386725	08.08.2017	मै0 इएयू बाथिंग सोलूशनस प्रा० लि० , बिनोला इण्डस्ट्रीयल एरिया भौरा कलां, फरुक नगर, जिला गुडगाँव - 122413, हरियाणा	जल कार्यों के लिए तांबा मिश्रधातु सजावटी एक टोंटी, संयोजित टोंटी समुच्चय और रोक वाल्ब	8931	-	-	1993
4.	एल- 9590001818	08.08.2017	मै0 नीरज ज्वैलर्स, 7271, गुड बाजार, जिला रेवाड़ी - 123401, हरियाणा	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्रधातु आभूषण/शिल्प वस्तुएँ - महीनता एवं मुहरांकन	1417	-	-	2016
5.	एल- 9590001919	08.08.2017	मै0 बाबू लाल राजेश कुमार सोनी, बूरा बाजार, जिला रेवाड़ी, हरियाणा	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्रधातु आभूषण/शिल्प वस्तुएँ - महीनता एवं मुहरांकन	1417	-	-	2016
6.	एल- 9590002020	08.08.2017	मै0 बाबू लाल राजेश कुमार सोनी, बूरा बाजार, जिला रेवाड़ी, हरियाणा	चौंटी एवं चौंटी मिश्रधातु आभूषण/शिल्प वस्तुएँ - महीनता एवं मुहरांकन	2112	-	-	2014
7.	एल- 9590002121	08.08.2017	मै0 दलीप ज्वैलर्स, वार्ड नं० 3, टोडापुर रोड, हेली मण्डी, जिला गुडगाँव, हरियाणा	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्रधातु आभूषण/शिल्प वस्तुएँ - महीनता एवं मुहरांकन	1417	-	-	2016
8.	एल- 9590002222	08.08.2017	मै0 दीप ज्वैलर्स, गुड बाजार, जिला रेवाड़ी - 123401, हरियाणा	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्रधातु आभूषण/शिल्प वस्तुएँ - महीनता एवं मुहरांकन	1417	-	-	2016
9.	एल- 9590002323	08.08.2017	मै0 दीप ज्वैलर्स, गुड बाजार, जिला रेवाड़ी - 123401, हरियाणा	चौंटी एवं चौंटी मिश्रधातु आभूषण/शिल्प वस्तुएँ - महीनता एवं मुहरांकन	2112	-	-	2014
10.	एल- 9590002424	08.08.2017	मै0 दलीप ज्वैलर्स, वार्ड नं० 3, टोडापुर रोड, हेली मण्डी, जिला गुडगाँव, हरियाणा	चौंटी एवं चौंटी मिश्रधातु आभूषण/शिल्प वस्तुएँ - महीनता एवं मुहरांकन	2112	-	-	2014

11.	एल- 9590002517	16.08.2017	मै0 श्री जी ज्वैलर्स, शॉप-1, बेसमेंट, लाला मनीराम मार्किट 2nd, मेन बाज़ार, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी - 123106, हरियाणा	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्रधातु आभूषण/शिल्प वस्तुएँ - महीनता एवं मुहरांकन	1417	-	-	2116
12.	एल- 9512386919	17.08.2017	मै0 अरावली को-ऑपरेटिव लेबर एण्ड कंस्ट्रक्शन लि०, गाँव व डाकघर पाली, एन. आई. टी., जिला फरीदाबाद - 121004, हरियाणा	खड्डे के लिए पूर्व ढलित कंक्रीट ब्लॉक	15658	-	-	2006
13.	एल- 9512387020	21.08.2017	मै0 जे. एम. टाइल्स, गाँव करनेरा, समयपुर सोहना रोड, सैक्टर - 56 के नज़दीक, जिला फरीदाबाद - 121004, हरियाणा	खड्डे के लिए पूर्व ढलित कंक्रीट ब्लॉक	15658	-	-	2006
14.	एल- 9590002618	23.08.2017	मै0 ज़ेवर पैलेस, शॉप नं० 4ए, एनएच-2, 1-2 चौक, एन. आई. टी., जिला फरीदाबाद, हरियाणा	चौदी एवं चौदी मिश्रधातु आभूषण/शिल्प वस्तुएँ - महीनता एवं मुहरांकन	2112	-	-	2014
15.	एल- 9512387121	24.08.2017	मै0 गौरव इन्टरप्राइसिस, 44 केएम स्टोन, एनएच-2, बराज़र फार्म हाउस के पीछे, गाँव सीकरी, बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद, हरियाणा	खड्डे के लिए पूर्व ढलित कंक्रीट ब्लॉक	15658	-	-	2006
16.	एल- 9512387820	24.08.2017	मै0 अतुल पाइप कॉरपोरेशन, रेलवे क्रासिंग के नज़दीक, मेन रोहतक रोड,, चरखी दादरी, जिला भिवानी - 127306, हरियाणा	पूर्वढलित कंक्रीट पाइप (प्रबलन सहित और रहित)	458	-	-	2003
17.	एल- 9590002719	24.08.2017	मै0 ओम शिवशंकर ज्वैलर्स, शॉप नं० 549, सारन स्कूल रोड, बिष्ट स्कूल के नज़दीक, पर्वतिया कालोनी, जिला फरीदाबाद - 121005, हरियाणा	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्रधातु आभूषण/शिल्प वस्तुएँ - महीनता एवं मुहरांकन	1417	-	-	2016

18.	एल- 9512387424	25.08.2017	मै0 श्री राजनाथ कंक्रीट उद्योग, सिवानी राजगढ़ रोड, गौशाला के नज़दीक, सिवानी, जिला भिवानी - 127046, हरियाणा	खड्गे के लिए पूर्व ढलित कंक्रीट ब्लॉक	15658	-	-	2006
-----	-------------------	------------	--	--	-------	---	---	------

[सं. सीएमडी/13 : 11]

एस. के. वर्मा, वैज्ञानिक ई एवं प्रमुख

**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION****(Department of Consumer Affairs)****(BUREAU OF INDIAN STANDARDS)**

New Delhi, the 22nd December, 2017

**S.O. 46.**—In pursuance of sub-regulation (5) of the regulation 4 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulation 1988, of the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the grant of licence particulars of which are given in the following schedule:

**SCHEDULE**

Sl. No.	Licences No. CM/L-	Grant Date	Name & Address of the Licensee	Title of the Standard	IS No.	Part	Sec.	Year
1.	L-9512387222	03.08.2017	M/s.. Henna Industries (P) Ltd., Plot No. 45, Sector – 27A, Distt. Faridabad - 121003, Haryana	Oxidation Hair Dyes, Liquid, Gel and Cream	8481	-	-	2001
2.	L-9512386523	08.08.2017	M/s. Atma So Parmatma Trading, Loharu Road, Siwani Mandi, Siwani, Distt. Bhiwani, Haryana	Precast Concrete Blocks for Paving	15658	-	-	2006
3.	L-9512386725	08.08.2017	M/s. EAU Bathing Solutions Pvt. Ltd., Binola Industrial Area, Bhora Kalan, Faruk Nagar, Distt. Gurgaon - 122413, Haryana	Copper Alloy Fancy Single Taps, Combination tap assembly and stop valve for water services	8931	-	-	1993
4.	L-9590001818	08.08.2017	M/s. Neeraj Jewelers, 7271, Gur Bazar, Distt. Rewari - 123401, Haryana	Gold and Gold Alloys Jewellery/Artefacts - Fineness and Marking	1417	-	-	2016
5.	L-9590001919	08.08.2017	M/s. Babu Lal Rajesh Kumar Soni, Bura Bazar, Distt. Rewari, Haryana	Gold and Gold Alloys Jewellery/Artefacts - Fineness and Marking	1417	-	-	2016
6.	L-9590002020	08.08.2017	M/s. Babu Lal Rajesh Kumar Soni, Bura Bazar, Distt. Rewari, Haryana	Silver and Silver Alloys Jewellery/Artefacts - Fineness and Marking	2112	-	-	2014

7.	L-9590002121	08.08.2017	M/s. Dalip Jewellers, Ward No.3, Todapur Road, Haily Mandi, Distt. Gurgaon, Haryana	Gold and Gold Alloys Jewellery/Artefacts - Fineness and Marking	1417	-	-	2016
8.	L-9590002222	08.08.2017	M/s. Deep Jewellers, Gur Bazar, Distt. Rewari - 123401, Haryana	Gold and Gold Alloys Jewellery/Artefacts - Fineness and Marking	1417	-	-	2016
9.	L-9590002323	08.08.2017	M/s. Deep Jewellers, Gur Bazar, Distt. Rewari - 123401, Haryana	Silver and Silver Alloys Jewellery/Artefacts - Fineness and Marking	2112	-	-	2014
10.	L-9590002424	08.08.2017	M/s. Dalip Jewellers, Ward No.3, Todapur Road, Haily Mandi, Distt. Gurgaon, Haryana	Silver and Silver Alloys Jewellery/Artefacts - Fineness and Marking	2112	-	-	2014
11.	L-9590002517	16.08.2017	M/s. Shri Ji Jewellers, Shop No.H-1, Basement, Lala Maniram Market 2 <sup>nd</sup> , Main Bazar, Dharuhera, Distt. Rewari - 123106, Haryana	Gold and Gold Alloys Jewellery/Artefacts - Fineness and Marking	1417	-	-	2116
12.	L-9512386919	17.08.2017	M/s. Aravali Co-Operative Labour Construction Society Ltd., Village & P.O. Pali, N.I.T., Distt. Faridabad - 121004, Haryana	Precast Concrete Blocks for Paving	15658	-	-	2006
13.	L-9512387020	21.08.2017	M/s. J.M. Tiles, Karnera, Samaypur Sohna Road, Near Sector - 56, Distt. Faridabad - 121004, Haryana	Precast Concrete Blocks for Paving	15658	-	-	2006
14.	L-9590002618	23.08.2017	M/s. Zever Palace, Shop No.4A, NH-2, 1-2 Chowk, N.I.T., Distt. Faridabad, Haryana	Silver and Silver Alloys Jewellery/Artefacts - Fineness and Marking	2112	-	-	2014
15.	L-9512387121	24.08.2017	M/s. Gaurav Enterprises, 44 KM Stone, Behind Brazar Farm House, Village Seekri, Distt. Faridabad, Haryana	Precast Concrete Blocks for Paving	15658	-	-	2006
16.	L-9512387820	24.08.2017	M/s. Atul Pipe Corporation, Near Railway Crossing, Main Rohtak Road, Charkhi Dadri, Distt. Bhiwani - 127306, Haryana	Precast Concrete Pipe (With and Without Reinforcement)	458	-	-	2003

17.	L-9590002719	24.08.2017	M/s. Om Shivshanker Jewellers, Shop No.549, Saran School Road, Near Bisht School, Parvatiya Colony, Distt. Faridabad - 121005, Haryana	Gold and Gold Alloys Jewellery/Artefacts - Fineness and Marking	1417	-	-	2016
18.	L-9512387424	25.08.2017	M/s. Shree Rajnath Concrete Udyog, Siwani Rajgarh Road, Near Goshala, Siwani, Distt. Bhiwani - 127046, Haryana	Precast Concrete Blocks for Paving	15658	-	-	2006

[No. CMD/13:11]

S. K. VERMA, Scientist E &amp; Head

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2017

**का.आ. 47.—** भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम 1988 के विनियम (4) के उपविनियम (5) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन लाइसेंसों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, वे स्वीकृत कर दिए गए हैं:-

**अनुसूची**

क्रम संख्या	लाइसेंस संख्या	स्वीकृत करने की तिथि	लाइसेंसधारी का नाम व पता	भारतीय मानक का शीर्षक	भा मा	भाग	अनु	वर्ष
1.	एल-9512384721	04.07.2017	मै0 एशियन सीमेंट वर्क्स, गाँव मेघपुर, पलवल सोहना रोड, जिला पलवल - 121102, हरियाणा	खड़जे के लिए पूर्व ढलित कंक्रीट ब्लॉक	15658	-	-	2006
2.	एल-9590001018	04.07.2017	मै0 ओमेज़ ज्वैलरी प्राइवेट लिमिटेड, 1269, सैक्टर-4, जिला गुडगाँव - 122001, हरियाणा	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्रधातु आभूषण/शिल्प वस्तुएँ - महीनता एवं मुहरांकन	1417	-	-	2016
3.	एल-9590001119	04.07.2017	मै0 शुभम ज्वैलर्स, गांधी चौक, सदर बाज़ार, जिला गुडगाँव - 122001, हरियाणा	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्रधातु आभूषण/शिल्प वस्तुएँ - महीनता एवं मुहरांकन	1417	-	-	2016
4.	एल-9590001220	04.07.2017	मै0 शुभम ज्वैलर्स, गांधी चौक, सदर बाज़ार, जिला गुडगाँव - 122001, हरियाणा	चाँदी एवं चाँदी मिश्रधातु आभूषण/शिल्प वस्तुएँ - महीनता एवं मुहरांकन	2112	-	-	2014
5.	एल-9590001321	04.07.2017	मै0 शगुन ज्वैलर्स, रेलवे रोड,	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्रधातु आभूषण/शिल्प	1417	-	-	2016

			जिला रोहतक - 124001, हरियाणा	वस्तुएँ - महीनता एवं मुहरांकन				
6.	एल- 9512384822	10.07.2017	मै0 खतरी इन्टरलॉकिंग टाइल्स, वीपीओ खरक जटान, महम मीनार के नज़दीक, बैसी, मेहम, जिला रोहतक - 124514, हरियाणा	खड़जे के लिए पूर्व ढलित कंक्रीट ब्लॉक	15658	-	-	2006
7.	एल- 9512384923	10.07.2017	मै0 राणा एण्ड कौशिक ग्रुप, किला नं0 20/2, मुस्तकिल नं0 47, गाँव हरचन्द पुर, सोहना, जिला गुडगाँव, हरियाणा	पैकेजबन्द पेय जल (पैकेजबन्द प्राकृतिक मिनरल जल के अलावा)	14543	-	-	2004
8.	एल- 9512385622	10.07.2017	मै0 जे. के. सीमेंट वर्क्स, झाड़ली मोहनबारी रोड, झाड़ली, माटनहेल, झाड़ली, जिला झज्जर - 124106, हरियाणा	साधारण पोर्टलैंड सीमेंट	269	-	-	2015
9.	एल- 9512385723	10.07.2017	मै0 श्री जी प्रीकास्ट, गाँव व डाकघर सिदीपुरा लोवा, बहादुरगढ़, जिला झज्जर -- 124507, हरियाणा	पूर्व ढलित कंक्रीट मेनहोल के ढक्कन व फ्रेम	12592	-	-	2002
10.	एल- 9512385024	11.07.2017	मै0 श्री श्याम इन्टरप्राइसिस, एनएच-2, राजस्थान मोटल के सामने, होडल, जिला पलवल - 121106, हरियाणा	खड़जे के लिए पूर्व ढलित कंक्रीट ब्लॉक	15658	-	-	2006
11.	एल- 9512385117	13.07.2017	मै0 श्री बालाजी इन्टरलॉकिंग टाइल्स, वी. पी. ओ. भलोद, जिला रोहतक, हरियाणा	खड़जे के लिए पूर्व ढलित कंक्रीट ब्लॉक	15658	-	-	2006
12.	एल- 9590001422	13.07.2017	मै0 सतगुरु ज्वैलर्स, ओल्ड अनाज मण्डी, मेहम, जिला भिवानी -	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्रधातु आभूषण/शिल्प	1417	-	-	2016

			124112, हरियाणा	वस्तुएँ – महीनता एवं मुहरांकन				
13.	एल- 9512385218	14.07.2017	मै0 श्री ओम इन्टरप्राइसिस, गाँव कान्हावास, पी ओ संगवारी, जिला रेवाड़ी - 123401, हरियाणा	खड़जे के लिए पूर्व ढलित कंक्रीट ब्लॉक	15658	-	-	2006
14.	एल- 9512385319	14.07.2017	मै0 यादव लोकिंग टाइल्स एण्ड बिल्डिंग मैटीरियल सपलायर, गाँव सादत नगर, तहसील कोसली, जिला रेवाड़ी - 123302, हरियाणा	खड़जे के लिए पूर्व ढलित कंक्रीट ब्लॉक	15658	-	-	2006
15.	एल- 9512385420	14.07.2017	मै0 जय दुर्गे कंक्रीट उद्योग, गाँव घरौट, तहसील हथीन, जिला पलवल - 121103, हरियाणा	खड़जे के लिए पूर्व ढलित कंक्रीट ब्लॉक	15658	-	-	2006
16.	एल- 9512385521	17.07.2017	मै0 हरियाणा इलैक्ट्रीकल इक्वूपमेंट, खसरा नं० 104/55, किला नं० 9/3/1, गाँव- ढोरका, वज़ीरपुर, जिला गुड़गाँव - 123505, हरियाणा	बाह्य रंग तेल इम्मेर्सड वितरण ट्रांसफार्मर भाग 1 मिनरल तेल निमिज्जित	1180	01	-	2014
17.	एल- 9512385925	17.07.2017	मै0 टी.एम.एस. इन्टरप्राइसिस, वीपीओ-लुहारी, जिला झज्जर - 124108, हरियाणा	खड़जे के लिए पूर्व ढलित कंक्रीट ब्लॉक	15658	-	-	2006
18.	एल- 9512386624	17.07.2017	मै0 बीकेडी बैवरेजिस, गाँव धनकोट, झज्जर रोड, जिला गुड़गाँव - 122505, हरियाणा	पैकेजबन्द प्रय जल (पैकेजबन्द प्राकृतिक मिनरल जल के अलावा)	14543	-	-	2004
19.	एल- 9590001523	17.07.2017	मै0 एम. एल. ज्वैलर्स, शॉप नं० एमसीएफ-3712, 33 फुट रोड, संजय कलोनी, सैक्टर-23, जिला फरीदाबाद - 121005, हरियाणा	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्रधातु आभूषण/शिल्प वस्तुएँ – महीनता एवं मुहरांकन	1417	-	-	2016



20.	एल- 9590001624	17.07.2017	मै0 एम. एल. ज्वैलर्स , शॉप नं0 एमसीएफ-3712, 33 फुट रोड, संजय कलोनी, सैक्टर-23, जिला फरीदाबाद - 121005, हरियाणा	चौंटी एवं चौंटी मिश्रधातु आभूषण/शिल्प वस्तुएँ - महीनता एवं मुहरांकन	2112	-	-	2014
21.	एल- 9512385824	24.07.2017	मै0 अल्ट्राकोन इन्फ्राकेम (प्रा0) लि0, प्लॉट नं0 5ए, सैक्टर - 79, गाँव नौरंगपुर, जिला गुड़गाँव - 122050, हरियाणा	कंक्रीट एडमिक्स्चर	9103	-	-	1999
22.	एल- 9512386119	25.07.2017	मै0 यूनीक टाइल्स इण्डस्ट्रीस, गाँव गरही बोहार, पी.ओ. अस्थल बोहार, जिला रोहतक - 124521, हरियाणा	खड्गों के लिए पूर्व ढलित कंक्रीट ब्लॉक	15658	-	-	2006
23.	एल- 9512386321	25.07.2017	मै0 पूजा टाइल्स, गाँव नसीबपुर, बरखोदा, तहसील नारनौल, जिला महेंद्रगढ़ - 123001, हरियाणा	खड्गों के लिए पूर्व ढलित कंक्रीट ब्लॉक	15658	-	-	2006
24	एल- 9512386018	26.07.2017	मै0 इण्डो सियाम सेफटी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नं0 149, दूसरा तल, सैक्टर-7, आईएमटी मानेसर, जिला गुड़गाँव - 122050, हरियाणा	दुपहिया वाहन चालकों के लिए संरक्षी हेलमेट	4151	-	-	1993
25.	एल- 9512386220	26.07.2017	मै0 श्री श्याम टाइल्स एण्ड मैटीरियल सपलायर, खाता नं0 421/457, नन्दरामपुर बास, सलारपुर मोड़, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी - 123106, हरियाणा	खड्गों के लिए पूर्व ढलित कंक्रीट ब्लॉक	15658	-	-	2006

26.	एल- 9512386422	27.07.2017	मै0 जिन्दल सैनीटेरीवेयर प्रा0 लि0, 3 केएम माडल स्टोन, वीपीओ रोहद, जिला झज्जर - 124501, हरियाणा	कंक्रीट एडमिक्स्चर - सुपर प्लास्टीसाइजिंग मिश्रण (कंक्रीट मिश्रण के लिए पानी कम) - सामान्य प्रकार	7834	01	-	1987
27.	एल- 9512386826	27.07.2017	मै0 जय बाबा ट्रेडिंग कं0, चरखी दादरी लाहारू रोड, गाँव हरोदा कलां, तहसील चरखी दादरी, जिला भिवानी - 127308, हरियाणा	खड्गे के लिए पूर्व ढलित कंक्रीट ब्लॉक	15658	-	-	2006
28.	एल- 9590001717	27.07.2017	मै0 राजदीप ज्वैलर्स, न्यू सराफर बाज़ार, बारा हज़ारी रोड, जिला रेवाड़ी - 123401, हरियाणा	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्रधातु आभूषण/शिल्प वस्तुएँ - महीनता एवं मुहरांकन	1417	-	-	2016

[सं. सीएमडी/13 : 11]

एस. के. वर्मा, वैज्ञानिक ई एवं प्रमुख

New Delhi, the 22nd December, 2017

**S.O. 47.**—In pursuance of sub-regulation (5) of the regulation 4 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulation 1988, of the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the grant of licence particulars of which are given in the following schedule:

**SCHEDULE**

Sl. No.	Licences No. CM/L-	Grant Date	Name & Address of the Licensee	Title of the Standard	IS No.	Part	Sec.	Year
1.	L- 9512384721	04.07.2017	M/s Asian Cement Works, Village Meghpur, Palwal Sohna Road, Distt. Palwal - 121102, Haryana	Precast Concrete Blocks for Paving	15658	-	-	2006
2.	L- 9590001018	04.07.2017	M/s Ornaz Jewellery Private Limited, 1269, Sector-4, Distt. Gurgaon - 122001, Haryana	Gold and Gold Alloys Jewellery/Artefacts - Fineness and Marking	1417	-	-	2016
3.	L- 9590001119	04.07.2017	M/s Shubham Jewellers, Gandhi Chowk, Sadar Bazar, Distt. Gurgaon - 122001, Haryana	Gold and Gold Alloys Jewellery/Artefacts - Fineness and Marking	1417	-	-	2016
4.	L- 9590001220	04.07.2017	M/s Shubham Jewellers, Gandhi Chowk, Sadar Bazar, Distt. Gurgaon - 122001,	Silver and Silver Alloys Jewellery/Artefacts - Fineness and Marking	2112	-	-	2014

			Haryana					
5.	L-9590001321	04.07.2017	M/s Shagun Jewellers, Railway Road, Distt. Rohtak - 124001, Haryana	Gold and Gold Alloys Jewellery/Artefacts - Fineness and Marking	1417	-	-	2016
6.	L-9512384822	10.07.2017	M/s Khatri Interlocking Tiles, VPO Kharak Jatan, Near Mahan Miner, Bainsi, Meham, Kharak, Distt. Bhiwani - 124514, Haryana	Precast Concrete Blocks for Paving	15658	-	-	2006
7.	L-9512384923	10.07.2017	M/s Rana & Kaushik Group, Kila No. 20/2, Mustkil No. 47, Village Harchand Pur, Sohna, Distt. Gurgaon, Haryana	Packaged Drinking Water (Other Than Packaged Natural Mineral Water)	14543	-	-	2004
8.	L-9512385622	10.07.2017	M/s J.K. Cement Works, Jharli Mohanbari Road, Jharli, Matanhail, Jharli, Distt. Jhajjar - 124106, Haryana	Ordinary Portland Cement	269	-	-	2015
9.	L-9512385723	10.07.2017	M/s Shree Jee Precast, V & P.O. Siddipura Lowa, Bahadurgarh, Distt. Jhajjar -- 124507, Haryana	Precast Manhole Cover and Frame	12592	-	-	2002
10.	L-9512385024	11.07.2017	M/s Shree Shyam Enterprises, NH-2, Opp. Rajasthan Motel, Hodal, Distt. Palwal - 121106, Haryana	Precast Concrete Blocks for Paving	15658	-	-	2006
11.	L-9512385117	13.07.2017	M/s Shree Balaji Interlocking Tiles, V P O-Bhalot, Bhalot, Distt. Palwal, Haryana	Precast Concrete Blocks for Paving	15658	-	-	2006
12.	L-9590001422	13.07.2017	M/s Satguru Jewellers, Old Anaj Mandi, Meham, Distt. Bhiwani - 124112, Haryana	Gold and Gold Alloys Jewellery/Artefacts - Fineness and Marking	1417	-	-	2016
13.	L-9512385218	14.07.2017	M/s Shree Om Enterprises, Village Kanhawas, P.O. Sangwari, Distt. Rewari – 123401, Haryana	Precast Concrete Blocks for Paving	15658	-	-	2006
14.	L-9512385319	14.07.2017	M/s Yadav Locking Tiles & Building Material Supplier, Village Sadat Nagar, Tehsil	Precast Concrete Blocks for Paving	15658	-	-	2006

			Kosli, Kosli, Distt. Rewari - 123302, Haryana					
15.	L- 9512385420	14.07.2017	M/s Jai Durge Concrete Udyog, Village Gharrot, Tehsil Hathine, Hathine, Distt. Palwal - 121103, Haryana	Precast Concrete Blocks for Paving	15658	-	-	2006
16.	L- 9512385521	17.07.2017	M/s Haryana Electrical Equipment, Khasra No. 104/55, Kila No. 9/3/1, Village Dhorka, Wazipur, Distt. Gurgaon - 123505, Haryana	Outdoor Type Oil Immersed Distribution Transformers, Part 1: Minerals Oil Immersed	1180	01	-	2014
17.	L- 9512385925	17.07.2017	M/s T.M.S. Enterprises, VPO-Luhari, Distt. Jhajjar - 124108, Haryana	Precast Concrete Blocks for Paving	15658	-	-	2006
18.	L- 9512386624	17.07.2017	M/s BKD Beverages, Village Dhankot, Jhajjar Road, Distt. Gurgaon - 122505, Haryana	Packaged Drinking Water (Other Than Packaged Natural Mineral Water)	14543	-	-	2004
19.	L- 9590001523	17.07.2017	M/s M.L. Jewellers, Shop No.MCF-3712, 33 ft Road, Sanjay Colony, Sector-23, Distt. Faridabad - 121005, Haryana	Gold and Gold Alloys Jewellery/Artefacts - Fineness and Marking	1417	-	-	2016
20.	L- 9590001624	17.07.2017	M/s M.L. Jewellers, Shop No.MCF-3712, 33 ft Road, Sanjay Colony, Sector-23, Distt. Faridabad - 121005, Haryana	Silver and Silver Alloys Jewellery/Artefacts - Fineness and Marking	2112	-	-	2014
21.	L- 9512385824	24.07.2017	M/s Ultracon Infrachem (P) Limited, 422/38, Rajiv Colony, Opp. Hotel Melfort, N.H.8, Distt. Gurgaon - 122001, Haryana	Concrete Admixtures	9103	-	-	1999
22.	L- 9512386119	25.07.2017	M/s Unique Tiles Industries, Village Garhi Bohar, P.O. Asthal Bohar, Distt. Rohtak, - 124521, Haryana	Precast Concrete Blocks for Paving	15658	-	-	2006
23.	L- 9512386321	25.07.2017	M/s Pooja Tiles, Village Nasibpur, Barkhoda, Tehsil Narnaul, Distt. Mahendergarh - 123001, Haryana	Precast Concrete Blocks for Paving	15658	-	-	2006

24.	L-9512386018	26.07.2017	M/s Indo Siam Safety Products Private Limited, Plot No. 149, 2nd Floor, Sector-7, IMT Manesar, Distt. Gurgaon - 122050, Haryana	Protective Helmets for Two Wheeler Riders	4151	-	-	1993
25.	L-9512386220	26.07.2017	M/s Shree Shyam Tile & Material Supplier, Khata No. 421/457, Nandrapur Bas, Salarpur Mod, Dharuhera, Distt. Rewari - 123106, Haryana	Precast Concrete Blocks for Paving	15658	-	-	2006
26.	L-9512386422	27.07.2017	M/s Jindal Sanitaryware Pvt. Ltd., 3 KM Mile Stone, VPO Rohad, Rohad, Distt. Jhajjar - 124501, Haryana	Injection Moulded PVC Socket Fittings with Solvent Cement Joints for Water Supplies	7834	01	-	1987
27.	L-9512386826	27.07.2017	M/s Jai Balaji Trading Co., Charkhi Dadri Loharu Road, Vill. Haroda Kalan, Teh. Charkhi Dadri, Charkhi Dadri, Distt. Bhiwani - 127308, Haryana	Precast Concrete Blocks for Paving	15658	-	-	2006
28.	L-9590001717	27.07.2017	M/s Rajdeep Jewellers, New Sarafa Bazar, Bara Hazari Road, Distt. Rewari - 123401, Haryana	Gold and Gold Alloys Jewellery/Artefacts - Fineness and Marking	1417	-	-	2016

[No. CMD/13:11]

S. K. VERMA, Scientist E &amp; Head

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2017

**का.आ. 48.—** भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988 के विनियम (5) के उपविनियम (6) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि निम्न विवरण वाले लाइसेंसों को उनके आगे दर्शायी गई तारीख से रद्द/स्थगित कर दिया गया है :-

**अनुसूची**

क्रम संख्या	लाइसेंस संख्या सीएम/एल	लाइसेंसधारी का नाम व पता	लाइसेंस के अन्तर्गत वस्तु/प्रक्रम सम्बद्ध भारतीय मानक का शीर्षक	रद्द करने की तिथि
01	एल-9951304	मै0 मंगला पोलीमर्स, रसूलपुर, रेलवे क्रॉसिंग के नज़दीक, जिला पलवल - 121102, हरियाणा	कन्ड्यूटस फॉर इलैक्ट्रीकल इन्स्टालेशनस भाग 3- रिजिड प्लेन कन्ड्यूटस ऑफ दन्सूलेटिंग मैटीरियलस आई एस 9537(भाग 3):1983	25.07.2017

[सं. सीएमडी/13:13]

एस. के. वर्मा, वैज्ञानिक ई एवं प्रमुख

New Delhi, the 22nd December, 2017

**S.O. 48.**—In pursuance of sub-regulation (6) of the regulation 5 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations 1988, of the Bureau of Indian Standards, hereby notifies that the licences particulars of which are given below have been cancelled/suspended with effect from the date indicated against each:

**SCHEDULE**

Sl. No.	Licences No. CM/L-	Name & Address of the Licensee	Article/Process with relevant Indian Standards covered by the licence Cancelled/suspension	Date of Cancellation
01	L-9951304	M/s Mangla Polymers, Rasulpur, Near Railway Crossing, Distt. Palwal - 121102, Haryana	Conduits for Electrical Installation Part 3: Rigid Plain Conduits of Insulating Materials IS 9537(Pt. 3):1983	25.07.2017

[No. CMD/13:13]

S. K. VERMA, Scientist E &amp; Head

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2017

**का.आ. 49.**— भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988 के विनियम (5) के उपविनियम (6) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि निम्न विवरण वाले लाइसेंसों को उनके आगे दर्शायी गई तारीख से रद्द /स्थगित कर दिया गया है :-

**अनुसूची**

क्र. सं.	लाइसेंस सं. सी एम/ एल-	लाइसेंसधारी का नाम व पता	लाइसेंस के अंतर्गत वस्तु/ प्रक्रम सम्बद्ध भारतीय मानक का शीर्षक	रद्द होने की तिथि
शून्य				

[सं. सीएमडी/13:13]

एस. के. वर्मा, वैज्ञानिक ई एवं प्रमुख

New Delhi, the 22nd December, 2017

**S.O. 49.**—In pursuance of sub-regulation (6) of the regulation 5 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations 1988, of the Bureau of Indian Standards, hereby notifies that the licences particulars of which are given below have been cancelled/suspended with effect from the date indicated against each:

**SCHEDULE**

Sl. No.	Licence No. CM/L-	Name & Address of the Licensee	Article/ Process with relevant Indian Standard covered by the licence cancelled/suspension	Date of Cancellation
NIL				

[No. CMD/13:13]

S. K. VERMA, Scientist E &amp; Head

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2018

**का.आ. 50.—** केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 उप धारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र संख्या 35 दिनांक 02.09.2017 का.आ संख्या 2016 दिनांक 23.08.2017, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (II) में किया गया है। इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट पंजाब राज्य की तहसील नवांशहर, जिला शहीद भगत सिंह नगर तथा तहसील गढ़शंकर, जिला होशियारपुर की भूमि में, पंजाब राज्य के गाँव : झुगियां : जिला शहीद भगत सिंह नगर से हिमाचल प्रदेश के गाँव : पेखुबेला, जिला उना तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पीएजेपीएल - उना ब्रांच पाइपलाइन परियोजना के सम्बंध में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचनाओं की प्रतियाँ जनता को तारीख 23.11.2017 तक उपलब्ध करा दी गई थी।

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामलों पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

**अनुसूची**

राज्य : पंजाब								
क्रं. सं.	जिला	तहसील	गाँव का नाम	हदबस्त नं	मुरब्बा // किला तथा खसरा सं.	क्षेत्रफल		
						हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	एस. बी. एस. नगर	नवांशहर	झुगियां	285	12 // 1	00	03	18
					6 // 25/2	00	00	20
					5 // 21	00	08	79
					5 // 22	00	13	17
					5 // 23	00	04	55
					5 // 19/2	00	00	20
					5 // 18/2	00	08	30
					5 // 17/1	00	01	76

					5 // 17/2	00	11	23
					5 // 16	00	08	79
					5 // 15	00	03	55
					4 // 20	00	00	28
					4 // 11	00	12	93
					4 // 12	00	12	08
					4 // 13	00	03	01
					4 // 9/1	00	00	26
					4 // 8	00	09	82
					4 // 7	00	06	65
					38 रास्ता	00	02	46
2	एस. बी. एस. नगर	नवांशहर	जुलाह माजरा	286	54 // 8	00	00	20
					79/1 रास्ता	00	00	32
					54 // 7	00	07	76
					54 // 4	00	00	81
					54 // 6	00	01	69
					54 // 5/2	00	12	50
					53 //1	00	00	83
3	एस. बी. एस. नगर	नवांशहर	खोजा	284	22 // 6	00	00	20
					21 // 1	00	11	55
					21 // 2	00	01	60
					9 // 21	00	01	13
					9 // 22	00	11	27
					9 // 23	00	12	69
					9 // 24	00	07	50
					9 // 17	00	05	80
					9 // 16	00	13	26
					10 // 20	00	11	79
					10 // 11	00	00	61



					10 // 12	00	10	33
					10 // 19	00	02	30
					10 // 13	00	13	01
					10 // 14	00	07	84
					10 // 15	00	00	20
					10 // 7	00	05	05
					10 // 6	00	12	59
					11 // 10	00	12	44
					11 // 9	00	03	23
					11 // 1	00	00	26
					11 // 2	00	09	88
					11 // 3	00	12	46
					11 // 4	00	09	31
					11 // 5	00	00	20
					7 // 24	00	03	91
					7 // 25	00	13	31
					6 // 21	00	11	13
					6 // 22	00	00	79
					6 // 20	00	01	70
					6 // 19	00	11	60
					6 // 18	00	12	86
					6 // 17	00	06	48
					6 // 14	00	06	35
					6 // 15	00	12	99
					5 // 11/1	00	08	72
					5 // 11/2	00	00	64
					5 // 11/3	00	02	53
					98 रास्ता	00	00	82
					5 // 28	00	01	64

					5 // 12/1	00	02	08
					5 // 12/2	00	00	98
					5 // 9/2	00	08	58
					62	00	01	55
					5 // 8	00	09	64
					5 // 7	00	12	28
					5 // 6	00	11	14
					4 // 10/2/1	00	05	80
					4 // 10/2/2	00	03	89
					4 // 10/1	00	02	71
					4 // 9	00	06	63
4	एस. बी. एस. नगर	नवांशहर	ताजपुर	283	27 // 2	00	00	20
					27 // 9	00	02	43
					27 // 3	00	02	73
					27 // 4	00	07	68
					27 // 5	00	11	55
					27 // 8	00	09	51
					27 // 7	00	04	82
					27 // 6	00	00	78
					26 // 1	00	12	76
					26 // 2/1	00	06	07
					46 रास्ता	00	00	20
					45 रास्ता	00	02	47
					26 // 2/3	00	03	96
					26 // 3	00	07	55
5	एस. बी. एस. नगर	नवांशहर	लालेवाल	282	6 // 3	00	04	53
					6 // 4	00	12	31
					6 // 5	00	07	27
					1 // 25	00	06	01

					2 // 21	00	08	86
6	एस. बी. एस. नगर	नवांशहर	गडी भारती	218	55 // 6	00	09	62
					85 रास्ता	00	01	21
					56 // 10	00	13	76
7	एस. बी. एस. नगर	नवांशहर	भारटा कलां	219	53 // 9	00	09	98
					53 // 8	00	12	19
					53 // 7	00	12	09
					53 // 4	00	00	20
					53 // 5	00	02	02
					53 // 6	00	10	30
					52 // 1	00	06	84
					52 // 10	00	05	29
					52 // 2	00	11	40
					52 // 9	00	00	53
					52 // 3	00	12	14
					52 // 4/2	00	12	23
					52 // 5/1	00	05	73
					52 // 5/2	00	03	41
					52 // 5/3	00	03	16
					51 // 1/1	00	01	41
					51 // 1/2	00	09	00
					51 // 2/1	00	09	81
					51 // 2/2	00	02	32
					51 // 3/1	00	11	95
					51 // 4	00	08	00
					51 // 5	00	01	12
					46 // 23	00	00	39
					46 // 24	00	06	06
					46 // 25	00	11	51

					47 // 21	00	11	40
					रास्ता	00	01	06
					47 // 22	00	12	37
					47 // 23	00	11	73
					47 // 18	00	00	20
					47 // 17	00	03	90
					47 // 24	00	08	52
					47 // 25	00	02	12
					47 // 16	00	10	27
					48 // 20	00	11	91
					48 // 19/2	00	11	82
					48 // 18	00	11	39
8	एस. बी. एस. नगर	नवांशहर	दरीयापुर	278	15 // 18	00	00	68
					15 // 17	00	11	27
					15 // 14	00	01	17
					15 // 15	00	07	20
					15 // 16	00	05	60
					14 // 20/2	00	00	51
					14 // 11/1	00	03	50
					33 रास्ता	00	01	48
					14 // 11/2	00	06	93
					14 // 20/1/1	00	00	20
					14 // 12	00	12	59
					14 // 26	00	00	95
					14 // 13/1	00	01	10
					14 // 13/2	00	10	71
					14 // 14	00	12	14
					14 // 15	00	12	05
					13 // 11/1	00	03	85

					13 // 10/2	00	00	20
					43 रास्ता	00	07	12
					13 // 10/1	00	00	20
					13 // 11/2	00	05	86
					13 // 12	00	05	59
					13 // 13/1	00	00	68
					13 // 9/1	00	03	78
					13 // 8/1	00	09	50
					13 // 7/1	00	12	47
					13 // 6/1	00	12	46
					12 // 26	00	03	35
					12 // 10/1	00	08	90
					12 // 9/1	00	12	88
					12 // 8/1	00	10	63
					12 // 3	00	01	60
					12 // 4	00	07	66
					12 // 5	00	04	26
					12 // 6	00	00	22
					12 // 7/1	00	04	99
9	एस. बी. एस. नगर	नवांशहर	काहलों	222	69 // 5	00	07	45
					69 // 6	00	00	27
					70 // 1/1	00	07	60
					70 // 1/2	00	04	42
					70 // 2	00	11	94
					70 // 3	00	10	70
					132 रास्ता	00	01	37
					70 // 4	00	11	85
					70 // 5	00	11	90
					67 // 25	00	00	21

					71 // 1	00	07	87
					71 // 2	00	01	98
					66 // 21	00	03	99
					66 // 22	00	10	54
					66 // 23/1	00	06	38
					66 // 23/2	00	06	09
					66 // 24	00	11	83
					66 // 25	00	11	73
					65 // 20	00	00	20
					65 // 21	00	10	10
					65 // 19	00	02	90
					65 // 22	00	08	67
					65 // 18	00	08	78
					65 // 23	00	03	01
					65 // 24	00	00	20
					65 // 17	00	12	14
					65 // 16	00	11	50
					124 रास्ता	00	01	51
					64 // 20	00	10	74
					64 // 19	00	12	13
					64 // 18	00	11	75
					64 // 13	00	00	20
					64 // 14	00	03	28
					64 // 17	00	08	77
					64 // 15	00	02	07
					64 // 16	00	01	27
10	एस. बी. एस. नगर	नवांशहर	गडी फ़तेह् खां	273	5 // 15	00	06	19
					5 // 6	00	01	79
					4 // 11/1	00	00	87

					4 // 10/2	00	12	26
					4 // 9	00	12	76
					4 // 2/3	00	00	20
					4 // 8/2	00	04	16
					4 // 8/3	00	00	20
					4 // 3/1	00	06	76
					4 // 3/2	00	01	13
					4 // 4	00	08	19
11	एस. बी. एस. नगर	नवांशहर	पलीयां खुर्द	225	37 // 24	00	03	41
					37 // 17	00	00	69
					37 // 16	00	00	82
12	एस. बी. एस. नगर	नवांशहर	पलीयाँ कलां	226	39 // 16/2	00	09	33
					39 // 16/1	00	00	91
					39 // 15	00	00	81
					38 // 20	00	00	81
					38 // 11	00	14	28
					38 // 10/2	00	00	55
					53/3 रास्ता	00	01	81
					38 // 12	00	00	22
					38 // 9	00	13	21
					38 // 2	00	00	50
					38 // 8	00	01	23
					38 // 3	00	14	62
					38 // 4	00	01	10
					35 // 23	00	00	62
					35 // 24	00	14	60
					35 // 25	00	00	65
					35 // 17	00	00	99
					35 // 16	00	13	27

					35 // 15/3	00	01	88
					36 // 20	00	00	20
					36 // 11/2	00	11	06
					36 // 10/1/2	00	00	72
					36 // 9/2	00	00	97
					36 // 9/1	00	06	81
					36 // 26	00	00	37
13	एस. बी. एस. नगर	नवांशहर	रामरायपुर	155	613	00	05	31
					674	00	06	10
					673	00	08	77
					676	00	05	75
					677	00	04	20
					678	00	04	19
					679	00	00	20
					683	00	05	27
					682	00	03	46
					681	00	01	00
					695	00	04	75
					692	00	04	26
					694	00	02	45
					693	00	06	64
					रास्ता	00	01	14
					774	00	03	59
					773	00	10	56
					772	00	09	05
					रास्ता	00	00	68
					756	00	09	31
					758	00	00	20
					755	00	06	42



					759	00	03	18
					754	00	02	22
					753	00	07	10
					740	00	00	20
					743	00	09	48
					742	00	08	40
					रास्ता	00	00	98
					425	00	09	80
					421	00	09	61
					422	00	00	20
					403	00	09	45
					367	00	08	03
					366	00	02	50
					365	00	00	20
14	एस. बी. एस. नगर	नवांशहर	सजावलपुर	154	591	00	00	97
					579	00	07	58
					578	00	08	85
					573	00	03	51
					574	00	04	92
					572	00	13	03
					558	00	07	56
					557	00	03	63
					778/556	00	02	93
					777/556	00	00	86
					535/1	00	01	94
					535	00	09	80
					534	00	08	64
					533	00	03	91
					530	00	01	00

					529	00	00	20
					525	00	00	20
					526	00	00	20
					524	00	00	20
15	एस. बी. एस. नगर	नवांशहर	सहिबाजपुर	227	2498 रास्ता	00	01	58
					2463	00	06	47
					2464	00	13	10
					2465	00	02	84
					2467	00	00	20
					2466	00	10	31
					2473 रास्ता	00	01	76
					2475	00	11	67
					2474	00	04	71
					2670/2479	00	01	44
					2669/2479	00	01	44
					2482	00	06	94
					2480	00	06	89
					2488	00	00	20
					2487	00	04	53
					रास्ता	00	00	24
					2486	00	00	20
					2333	00	00	85
					2324	00	11	79
					2325	00	06	03
					2323 रास्ता	00	01	08
					2319	00	06	40
					2320	00	12	25
					2314	00	01	50
					2321	00	00	36

					2313	00	13	91
					2312	00	08	99
					2309 रास्ता	00	04	83
					2298	00	01	24
					2297	00	07	97
					2296	00	06	30
					2295	00	08	16
					2294	00	08	35
					2289	00	06	48
					2290	00	07	49
					1856/508	00	01	32
					2245	00	09	40
					2165	00	11	82
					2164	00	10	45
					2163	00	13	86
					2162	00	05	67
					2140	00	09	01
					2145	00	00	25
					2144	00	08	07
					2143	00	04	70
					2142	00	00	33
					2098	00	00	79
					2105 रास्ता	00	01	31
					2125	00	10	28
					2120	00	00	20
					2124	00	02	25
					2121	00	12	52
					2118	00	02	14
					2122	00	00	20

					2117	00	14	84
16	होशियारपुर	गढ़शंकर	धमाई	163	2375/1978	00	13	66
					2374/1978	00	01	79
					1977	00	04	43
					1976	00	00	61
					1973	00	00	20
					1975	00	03	87
					1935	00	27	76
					1936	00	01	54
					1937/2368	00	04	42
					1938	00	04	25
					1947	00	01	59
					2368/1943	00	07	34
					1939	00	00	20
					1940	00	03	75
17	होशियारपुर	गढ़शंकर	रामगड	162	371	00	06	85
					370	00	00	41
					689/373	00	00	80
					690/373	00	04	23
					682/368	00	01	40
					683/368	00	06	50
					375	00	06	11
					376	00	01	11
					366	00	06	79
					365	00	07	49
					364	00	00	75
					363	00	05	67
					379	00	06	80
					रास्ता	00	01	17

					401	00	04	37
					400	00	11	44
					399	00	02	19
					389	00	11	91
					388	00	00	20
					रास्ता	00	01	55
					391	00	00	20
					510	00	00	57
					508	00	00	69
					509	00	12	23
					571/515	00	03	77
					516	00	08	07
					575/517	00	01	88
					522	00	02	05
					518	00	10	74
					519	00	01	24
					520	00	02	88
					506	00	00	48
18	होशियारपुर	गढ़शंकर	मौजूपुर	250	237	00	08	46
					236	00	10	69
					235	00	11	58
					150	00	03	15
					487/151	00	08	70
					488/151	00	01	09
					489/152	00	00	41
					490/152	00	05	41
					153	00	02	00
					441/439	00	00	20
					442/439	00	00	20

19	होशियारपुर	गढ़शंकर	कुनैल	364	426	00	09	04
					380	00	13	09
					425	00	02	52
					423	00	09	20
					417	00	00	20
					418	00	03	87
					419	00	03	24
					422/2	00	06	78
					420	00	01	71
					422/1	00	16	11
					399	00	03	13
					398	00	02	44
					397	00	00	78
					396	00	05	33
					395	00	01	59
					400	00	03	58
					401/2	00	05	64
					394	00	00	25
					393/2	00	00	20
					401/1	00	06	07
					339/2	00	05	56
					339/1	00	16	49
					335	00	00	28
					336	00	07	76
20	होशियारपुर	गढ़शंकर	बारापुर	361	86 रास्ता	00	01	42
					36 // 11	00	03	78
					37 // 15/2	00	03	43
					37 // 15/1	00	01	32
					37 // 6	00	12	93

					37 // 7/1	00	00	20
					37 // 5/2	00	00	22
					37 // 5/1	00	01	99
					37 // 4	00	10	77
					30 // 24/2	00	05	72
					30 // 23/3	00	00	20
					318 रास्ता	00	01	71
					30 // 24/1	00	01	83
					30 // 23/2	00	04	11
					30 // 18/2	00	03	52
					30 // 18/1	00	06	81
					315 रास्ता	00	01	80
					30 // 13/2	00	00	20
					30 // 13/1	00	03	07
					30 // 12/3	00	06	78
					30 // 12/2	00	04	56
					30 // 9/2	00	00	20
					30 // 9/3	00	03	83
					30 // 9/5	00	00	28
					30 // 9/1	00	02	89
					रास्ता	00	02	22
					30 // 9/4	00	01	87
					30 // 2/3	00	00	58
					रास्ता	00	00	20
					30 // 2/2	00	00	20
					30 // 2/1	00	09	90
					30 // 1	00	00	21
					19 // 22/3	00	02	73
					19 // 21/2	00	02	39

					19 // 22/1	00	00	38
					19 // 21/1	00	06	18
					19 // 20	00	11	90
					19 // 11	00	10	95
					19 // 10	00	02	23
					रास्ता	00	00	20
					20 // 15	00	00	20
					342 रास्ता	00	02	74
					20 // 6	00	07	24
					20 // 5/2	00	06	01
					20 // 5/1	00	05	55
					12 // 25/2	00	06	10
					12 // 25/1	00	05	65
					12 // 28	00	00	65
					12 // 24	00	00	20
					12 // 16/2	00	00	26
					12 // 16/3	00	02	95
					12 // 17	00	07	38
					12 // 14/2	00	10	22
					89 रास्ता	00	01	77
					12 // 7	00	11	44
					283 रास्ता	00	00	20
					12 // 4/3	00	02	19
					12 // 4/2	00	10	89
					12 // 5	00	00	20
					6 // 24	00	02	95
					6 // 25/1	00	09	24
					6 // 16/2	00	01	97
					6 // 16/1	00	10	16



					6 // 15	00	06	24
					5 // 11	00	04	44
					6 // 6	00	00	20
					5 // 10	00	06	80
21	होशियारपुर	गढ़शंकर	गदीवाल	483	5 // 4	00	04	52
					1 // 24/4	00	03	38
					1 // 24/3	00	06	39
					1 // 25/1	00	01	44
					1 // 17/1	00	00	93
					1 // 16/2	00	05	61
					110 रास्ता	00	00	90
					1 // 16/1/2	00	01	89
					1 // 16/1/1	00	02	27
					1 // 15/3	00	02	73
					1 // 15/2	00	09	05
					2 // 11	00	00	24

[फा. सं. आर-11025(11)/1/2018-ओआर-1/ई-21789]

पवन कुमार, अवर सचिव

**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**

New Delhi, the 4th January, 2018

**S.O. 50.**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, published in the Gazette No. 35 dated 02.09.2017, S.O. No. 16 dated 23.08.2017 Part-II, section 3, sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land situated in Tehsil – Nawanshahr of District Shahid Bhagat Singh Nagar and Tehsil – Garhshankar of District Hoshiarpur in Punjab State, specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of petroleum product from village Jhungian in the State of Punjab, District Shahid Bhagat Singh Nagar to village Pexhubela in the State of Himachal Pradesh, District Una by the Indian Oil Corporation Limited for implementing the "PAJPL - Una Branch pipeline project".

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public on 23.11.2017

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, has submitted his report of Central Government.

And whereas, the Central Government after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of the user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user of the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of the declaration, in India Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

India Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to pipeline.

#### SCHEDULE

State : Punjab								
Sr. No.	Name of District	Name of Tehsil	Name of Village	Hadbast No.	Murabba // Killa OR Khasara No.	Area		
						Hectare	Are	Sq. mtr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	S.B.S. Nagar	Nawanshahr	Jhungian	285	12 // 1	00	03	18
					6 // 25/2	00	00	20
					5 // 21	00	08	79
					5 // 22	00	13	17
					5 // 23	00	04	55
					5 // 19/2	00	00	20
					5 // 18/2	00	08	30
					5 // 17/1	00	01	76
					5 // 17/2	00	11	23
					5 // 16	00	08	79
					5 // 15	00	03	55
					4 // 20	00	00	28
					4 // 11	00	12	93
					4 // 12	00	12	08
					4 // 13	00	03	01
					4 // 9/1	00	00	26
					4 // 8	00	09	82
					4 // 7	00	06	65
					38 Rasta	00	02	46
2	S.B.S. Nagar	Nawanshahr	Julah Majra	286	54 // 8	00	00	20
					79/1 Rasta	00	00	32
					54 // 7	00	07	76
					54 // 4	00	00	81

					54 // 6	00	01	69
					54 // 5/2	00	12	50
					53 // 1	00	00	83
3	S.B.S. Nagar	Nawanshahr	Khoja	284	22 // 6	00	00	20
					21 // 1	00	11	55
					21 // 2	00	01	60
					9 // 21	00	01	13
					9 // 22	00	11	27
					9 // 23	00	12	69
					9 // 24	00	07	50
					9 // 17	00	05	80
					9 // 16	00	13	26
					10 // 20	00	11	79
					10 // 11	00	00	61
					10 // 12	00	10	33
					10 // 19	00	02	30
					10 // 13	00	13	01
					10 // 14	00	07	84
					10 // 15	00	00	20
					10 // 7	00	05	05
					10 // 6	00	12	59
					11 // 10	00	12	44
					11 // 9	00	03	23
					11 // 1	00	00	26
					11 // 2	00	09	88
					11 // 3	00	12	46
					11 // 4	00	09	31
					11 // 5	00	00	20
					7 // 24	00	03	91
					7 // 25	00	13	31
					6 // 21	00	11	13
					6 // 22	00	00	79
					6 // 20	00	01	70
					6 // 19	00	11	60
					6 // 18	00	12	86

					6 // 17	00	06	48
					6 // 14	00	06	35
					6 // 15	00	12	99
					5 // 11/1	00	08	72
					5 // 11/2	00	00	64
					5 // 11/3	00	02	53
					98 Rasta	00	00	82
					5 // 28	00	01	64
					5 // 12/1	00	02	08
					5 // 12/2	00	00	98
					5 // 9/2	00	08	58
					62	00	01	55
					5 // 8	00	09	64
					5 // 7	00	12	28
					5 // 6	00	11	14
					4 // 10/2/1	00	05	80
					4 // 10/2/2	00	03	89
					4 // 10/1	00	02	71
					4 // 9	00	06	63
4	S.B.S. Nagar	Nawanshahr	Tajpur	283	27 // 2	00	00	20
					27 // 9	00	02	43
					27 // 3	00	02	73
					27 // 4	00	07	68
					27 // 5	00	11	55
					27 // 8	00	09	51
					27 // 7	00	04	82
					27 // 6	00	00	78
					26 // 1	00	12	76
					26 // 2/1	00	06	07
					46 Rasta	00	00	20
					45 Rasta	00	02	47
					26 // 2/3	00	03	96
					26 // 3	00	07	55
5	S.B.S. Nagar	Nawanshahr	Lalewal	282	6 // 3	00	04	53
					6 // 4	00	12	31

					6 // 5	00	07	27
					1 // 25	00	06	01
					2 // 21	00	08	86
6	S.B.S. Nagar	Nawanshahr	Garhi Bharti	218	55 // 6	00	09	62
					85 Rasta	00	01	21
					56 // 10	00	13	76
7	S.B.S. Nagar	Nawanshahr	Bharta Kalan	219	53 // 9	00	09	98
					53 // 8	00	12	19
					53 // 7	00	12	09
					53 // 4	00	00	20
					53 // 5	00	02	02
					53 // 6	00	10	30
					52 // 1	00	06	84
					52 // 10	00	05	29
					52 // 2	00	11	40
					52 // 9	00	00	53
					52 // 3	00	12	14
					52 // 4/2	00	12	23
					52 // 5/1	00	05	73
					52 // 5/2	00	03	41
					52 // 5/3	00	03	16
					51 // 1/1	00	01	41
					51 // 1/2	00	09	00
					51 // 2/1	00	09	81
					51 // 2/2	00	02	32
					51 // 3/1	00	11	95
					51 // 4	00	08	00
					51 // 5	00	01	12
					46 // 23	00	00	39
					46 // 24	00	06	06
					46 // 25	00	11	51
					47 // 21	00	11	40
					Rasta	00	01	06
					47 // 22	00	12	37
					47 // 23	00	11	73

					47 // 18	00	00	20
					47 // 17	00	03	90
					47 // 24	00	08	52
					47 // 25	00	02	12
					47 // 16	00	10	27
					48 // 20	00	11	91
					48 // 19/2	00	11	82
					48 // 18	00	11	39
8	S.B.S. Nagar	Nawanshahr	Dariyapur	278	15 // 18	00	00	68
					15 // 17	00	11	27
					15 // 14	00	01	17
					15 // 15	00	07	20
					15 // 16	00	05	60
					14 // 20/2	00	00	51
					14 // 11/1	00	03	50
					33 Rasta	00	01	48
					14 // 11/2	00	06	93
					14 // 20/1/1	00	00	20
					14 // 12	00	12	59
					14 // 26	00	00	95
					14 // 13/1	00	01	10
					14 // 13/2	00	10	71
					14 // 14	00	12	14
					14 // 15	00	12	05
					13 // 11/1	00	03	85
					13 // 10/2	00	00	20
					43 Rasta	00	07	12
					13 // 10/1	00	00	20
					13 // 11/2	00	05	86
					13 // 12	00	05	59
					13 // 13/1	00	00	68
					13 // 9/1	00	03	78
					13 // 8/1	00	09	50
					13 // 7/1	00	12	47
					13 // 6/1	00	12	46

					12 // 26	00	03	35
					12 // 10/1	00	08	90
					12 // 9/1	00	12	88
					12 // 8/1	00	10	63
					12 // 3	00	01	60
					12 // 4	00	07	66
					12 // 5	00	04	26
					12 // 6	00	00	22
					12 // 7/1	00	04	99
9	S.B.S. Nagar	Nawanshahr	Kahlon	222	69 // 5	00	07	45
					69 // 6	00	00	27
					70 // 1/1	00	07	60
					70 // 1/2	00	04	42
					70 // 2	00	11	94
					70 // 3	00	10	70
					132 Rasta	00	01	37
					70 // 4	00	11	85
					70 // 5	00	11	90
					67 // 25	00	00	21
					71 // 1	00	07	87
					71 // 2	00	01	98
					66 // 21	00	03	99
					66 // 22	00	10	54
					66 // 23/1	00	06	38
					66 // 23/2	00	06	09
					66 // 24	00	11	83
					66 // 25	00	11	73
					65 // 20	00	00	20
					65 // 21	00	10	10
					65 // 19	00	02	90
					65 // 22	00	08	67
					65 // 18	00	08	78
					65 // 23	00	03	01
					65 // 24	00	00	20
					65 // 17	00	12	14

					65 // 16	00	11	50
					124 Rasta	00	01	51
					64 // 20	00	10	74
					64 // 19	00	12	13
					64 // 18	00	11	75
					64 // 13	00	00	20
					64 // 14	00	03	28
					64 // 17	00	08	77
					64 // 15	00	02	07
					64 // 16	00	01	27
10	S.B.S. Nagar	Nawanshahr	Garhi Fateh Khan.	273	5 // 15	00	06	19
					5 // 6	00	01	79
					4 // 11/1	00	00	87
					4 //10/2	00	12	26
					4 // 9	00	12	76
					4 // 2/3	00	00	20
					4 // 8/2	00	04	16
					4 // 8/3	00	00	20
					4 // 3/1	00	06	76
					4 // 3/2	00	01	13
					4 // 4	00	08	19
11	S.B.S. Nagar	Nawanshahr	Pallian khurd	225	37 // 24	00	03	41
					37 // 17	00	00	69
					37 // 16	00	00	82
12	S.B.S. Nagar	Nawanshahr	Pallian Kalan	226	39 // 16/2	00	09	33
					39 // 16/1	00	00	91
					39 // 15	00	00	81
					38 // 20	00	00	81
					38 // 11	00	14	28
					38 // 10/2	00	00	55
					53/3 Rasta	00	01	81
					38 // 12	00	00	22
					38 // 9	00	13	21
					38 // 2	00	00	50
					38 // 8	00	01	23



					38 // 3	00	14	62
					38 // 4	00	01	10
					35 // 23	00	00	62
					35 // 24	00	14	60
					35 // 25	00	00	65
					35 // 17	00	00	99
					35 // 16	00	13	27
					35 // 15/3	00	01	88
					36 // 20	00	00	20
					36 // 11/2	00	11	06
					36 // 10/1/2	00	00	72
					36 // 9/2	00	00	97
					36 // 9/1	00	06	81
					36 // 26	00	00	37
13	S.B.S. Nagar	Nawanshahr	Ramraipur	155	613	00	05	31
					674	00	06	10
					673	00	08	77
					676	00	05	75
					677	00	04	20
					678	00	04	19
					679	00	00	20
					683	00	05	27
					682	00	03	46
					681	00	01	00
					695	00	04	75
					692	00	04	26
					694	00	02	45
					693	00	06	64
					Rasta	00	01	14
					774	00	03	59
					773	00	10	56
					772	00	09	05
					Rasta	00	00	68
					756	00	09	31
					758	00	00	20

					755	00	06	42
					759	00	03	18
					754	00	02	22
					753	00	07	10
					740	00	00	20
					743	00	09	48
					742	00	08	40
					Rasta	00	00	98
					425	00	09	80
					421	00	09	61
					422	00	00	20
					403	00	09	45
					367	00	08	03
					366	00	02	50
					365	00	00	20
14	S.B.S. Nagar	Nawanshahr	Sajawalpur	154	591	00	00	97
					579	00	07	58
					578	00	08	85
					573	00	03	51
					574	00	04	92
					572	00	13	03
					558	00	07	56
					557	00	03	63
					778/556	00	02	93
					777/556	00	00	86
					535/1	00	01	94
					535	00	09	80
					534	00	08	64
					533	00	03	91
					530	00	01	00
					529	00	00	20
					525	00	00	20
					526	00	00	20
					524	00	00	20
15	S.B.S. Nagar	Nawanshahr	Sahbajpur	227	2498 Rasta	00	01	58

					2463	00	06	47
					2464	00	13	10
					2465	00	02	84
					2467	00	00	20
					2466	00	10	31
					2473 Rasta	00	01	76
					2475	00	11	67
					2474	00	04	71
					2670/2479	00	01	44
					2669/2479	00	01	44
					2482	00	06	94
					2480	00	06	89
					2488	00	00	20
					2487	00	04	53
					Rasta	00	00	24
					2486	00	00	20
					2333	00	00	85
					2324	00	11	79
					2325	00	06	03
					2323 Rasta	00	01	08
					2319	00	06	40
					2320	00	12	25
					2314	00	01	50
					2321	00	00	36
					2313	00	13	91
					2312	00	08	99
					2309 Rasta	00	04	83
					2298	00	01	24
					2297	00	07	97
					2296	00	06	30
					2295	00	08	16
					2294	00	08	35
					2289	00	06	48
					2290	00	07	49
					1856/508	00	01	32

					2245	00	09	40
					2165	00	11	82
					2164	00	10	45
					2163	00	13	86
					2162	00	05	67
					2140	00	09	01
					2145	00	00	25
					2144	00	08	07
					2143	00	04	70
					2142	00	00	33
					2098	00	00	79
					2105 Rasta	00	01	31
					2125	00	10	28
					2120	00	00	20
					2124	00	02	25
					2121	00	12	52
					2118	00	02	14
					2122	00	00	20
					2117	00	14	84
16	Hoshiarpur	Garhshankar	Dhamai	163	2375/1978	00	13	66
					2374/1978	00	01	79
					1977	00	04	43
					1976	00	00	61
					1973	00	00	20
					1975	00	03	87
					1935	00	27	76
					1936	00	01	54
					1937/2368	00	04	42
					1938	00	04	25
					1947	00	01	59
					2368/1943	00	07	34
					1939	00	00	20
					1940	00	03	75
17	Hoshiarpur	Garhshankar	Ramgarh	162	371	00	06	85
					370	00	00	41

					689/373	00	00	80
					690/373	00	04	23
					682/368	00	01	40
					683/368	00	06	50
					375	00	06	11
					376	00	01	11
					366	00	06	79
					365	00	07	49
					364	00	00	75
					363	00	05	67
					379	00	06	80
					Rasta	00	01	17
					401	00	04	37
					400	00	11	44
					399	00	02	19
					389	00	11	91
					388	00	00	20
					Rasta	00	01	55
					391	00	00	20
					510	00	00	57
					508	00	00	69
					509	00	12	23
					571/515	00	03	77
					516	00	08	07
					575/517	00	01	88
					522	00	02	05
					518	00	10	74
					519	00	01	24
					520	00	02	88
					506	00	00	48
18	Hoshiarpur	Garhshankar	Maujupur	250	237	00	08	46
					236	00	10	69
					235	00	11	58
					150	00	03	15
					487/151	00	08	70

					488/151	00	01	09
					489/152	00	00	41
					490/152	00	05	41
					153	00	02	00
					441/439	00	00	20
					442/439	00	00	20
19	Hoshiarpur	Garhshankar	Kunail	364	426	00	09	04
					380	00	13	09
					425	00	02	52
					423	00	09	20
					417	00	00	20
					418	00	03	87
					419	00	03	24
					422/2	00	06	78
					420	00	01	71
					422/1	00	16	11
					399	00	03	13
					398	00	02	44
					397	00	00	78
					396	00	05	33
					395	00	01	59
					400	00	03	58
					401/2	00	05	64
					394	00	00	25
					393/2	00	00	20
					401/1	00	06	07
					339/2	00	05	56
					339/1	00	16	49
					335	00	00	28
					336	00	07	76
20	Hoshiarpur	Garhshankar	Barapur	361	86 Rasta	00	01	42
					36 // 11	00	03	78
					37 // 15/2	00	03	43
					37 // 15/1	00	01	32
					37 // 6	00	12	93

					37 // 7/1	00	00	20
					37 // 5/2	00	00	22
					37 // 5/1	00	01	99
					37 // 4	00	10	77
					30 // 24/2	00	05	72
					30 // 23/3	00	00	20
					318 Rasta	00	01	71
					30 // 24/1	00	01	83
					30 // 23/2	00	04	11
					30 // 18/2	00	03	52
					30 // 18/1	00	06	81
					315 Rasta	00	01	80
					30 // 13/2	00	00	20
					30 // 13/1	00	03	07
					30 // 12/3	00	06	78
					30 // 12/2	00	04	56
					30 // 9/2	00	00	20
					30 // 9/3	00	03	83
					30 // 9/5	00	00	28
					30 // 9/1	00	02	89
					Rasta	00	02	22
					30 // 9/4	00	01	87
					30 // 2/3	00	00	58
					Rasta	00	00	20
					30 // 2/2	00	00	20
					30 // 2/1	00	09	90
					30 // 1	00	00	21
					19 // 22/3	00	02	73
					19 // 21/2	00	02	39
					19 // 22/1	00	00	38
					19 // 21/1	00	06	18
					19 // 20	00	11	90
					19 // 11	00	10	95
					19 // 10	00	02	23
					Rasta	00	00	20

					20 // 15	00	00	20
					342 Rasta	00	02	74
					20 // 6	00	07	24
					20 // 5/2	00	06	01
					20 // 5/1	00	05	55
					12 // 25/2	00	06	10
					12 // 25/1	00	05	65
					12 // 28	00	00	65
					12 // 24	00	00	20
					12 // 16/2	00	00	26
					12 // 16/3	00	02	95
					12 // 17	00	07	38
					12 // 14/2	00	10	22
					89 Rasta	00	01	77
					12 // 7	00	11	44
					283 Rasta	00	00	20
					12 // 4/3	00	02	19
					12 // 4/2	00	10	89
					12 // 5	00	00	20
					6 // 24	00	02	95
					6 // 25/1	00	09	24
					6 // 16/2	00	01	97
					6 // 16/1	00	10	16
					6 // 15	00	06	24
					5 // 11	00	04	44
					6 // 6	00	00	20
					5 // 10	00	06	80
21	Hoshiarpur	Garhshankar	Gaddiwal	483	5 // 4	00	04	52
					1 // 24/4	00	03	38
					1 // 24/3	00	06	39
					1 // 25/1	00	01	44
					1 // 17/1	00	00	93
					1 // 16/2	00	05	61
					110 Rasta	00	00	90
					1 // 16/1/2	00	01	89



					1 // 16/1/1	00	02	27
					1 // 15/3	00	02	73
					1 // 15/2	00	09	05
					2 // 11	00	00	24

[F. No. R-11025(11)/1/2018-OR-I/E-21789]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2018

**का.आ. 51.—** केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पारादीप (ओडिशा) से हैदराबाद (तेलंगाना) तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा "पारादीप-हैदराबाद पाइपलाइन" बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उस में उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री दिल्लीप कुमार महांति, सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पारादीप-हैदराबाद पाइपलाइन परियोजना, तृतीय तल, आलोक भारती टावर, शहीद नगर, भुवनेश्वर -751007, ओडिशा को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

**अनुसूची**

तहसील - एरसमा	जिला - जगतसिंहपुर	राज्य - ओडिशा		
गाँव का नाम	प्लॉट नं.		क्षेत्रफल	
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
पाणिगडिआकन्धा	326	00	01	00
	327	00	00	45
	290	00	10	72
	291	00	01	92
	292/793	00	02	52
	293	00	02	56
	295	00	03	70
	296	00	01	85

	297	00	01	50
	298	00	02	88
	299	00	02	34
	257	00	02	52
	278	00	00	16
	276	00	02	52
	274	00	02	95
	273	00	00	55
	272	00	04	00
	269/777	00	03	28
	260	00	01	45
	266	00	00	74
	239/978	00	04	68
	239	00	03	39
	238	00	01	48
	238/945	00	04	52
	239/977	00	02	00
	234	00	13	30
	235/747	00	01	20
	235	00	03	90
	210	00	29	00
	267	00	00	28
	233/779	00	00	22
	238/946	00	00	56

[फा. सं. आर-11025(11)/236/2017-ओआर-I/ई-13717]

पवन कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 11th January, 2018

**S.O. 51.—** Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum products from Paradip (Odisha) to Hyderabad (Telangana), “Paradip-Hyderabad Pipeline” should be laid by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Sri Dillip Kumar Mohanty, Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Paradip-Hyderabad Pipeline Project, 3rd Floor, Alok Bharati Tower, Saheed Nagar, Bhubaneswar- 751007, (Odisha).

**SCHEDULE**

Tehsil : ERASAMA	District : JAGATSINGHPUR	State : ODISHA		
Name of the Village	Plot No.	Area		
		Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5
PANIGARIAKANDHA	326	00	01	00
	327	00	00	45
	290	00	10	72
	291	00	01	92
	292/793	00	02	52
	293	00	02	56
	295	00	03	70
	296	00	01	85
	297	00	01	50
	298	00	02	88
	299	00	02	34
	257	00	02	52
	278	00	00	16
	276	00	02	52
	274	00	02	95
	273	00	00	55
	272	00	04	00
	269/777	00	03	28
	260	00	01	45
	266	00	00	74
	239/978	00	04	68
	239	00	03	39

	238	00	01	48
	238/945	00	04	52
	239/977	00	02	00
	234	00	13	30
	235/747	00	01	20
	235	00	03	90
	210	00	29	00
	267	00	00	28
	233/779	00	00	22
	238/946	00	00	56

[F. No. R-11025(11)/236/2017-OR-I/E-13717]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2018

**का.आ. 52.**—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 उप धारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 1068(अ) तारीख 03.04.2017 जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र संख्या 947, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (II) तारीख 06.04.2017 में किया गया है। इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट आंध्रप्रदेश राज्य के मंडल : द्वारका तिरुमला जिला: वेस्ट गोदावरी की भूमि में, ओडीशा राज्य में पारादीप से तेलंगाना राज्य में हैदराबाद तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे “पारादीप-हैदराबाद पाइपलाइन परियोजना” के संबंध में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी:

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं। और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए:

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए सभी बिल्लिंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची					
जिला: वेस्ट गोदावरी			राज्य: आन्ध्र प्रदेश		
मंडल का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
द्वारका तिरुमला	जगन्नाथपुरम	4/3	00	00	03
		4/2A	00	14	81

		4/2B	00	07	71
		4/2C	00	08	51
		4/1	00	00	16
		10/1	00	55	51
		10/2	00	10	01
		3/6	00	03	98
		11/2	00	12	96
		11/1	00	16	71
		15/1	00	00	23
द्वारका तिरुमला	जी. कोत्तापल्ली	20/1	00	16	25
		11	00	23	56
		10/4	00	05	93
		10/2J	00	05	47
		10/2E	00	05	56
		10/2D	00	05	17
		10/1B/4	00	03	06
		10/1B/3-2	00	09	60
		8/1C	00	21	19
		8/1E	00	03	64
		1/6	00	10	59
		1/3	00	10	15
		1/5	00	08	64
		1/4	00	10	05
		2/2	00	00	42
		2/1	00	00	05
		3/1	00	18	97
द्वारका तिरुमला	कोडीगुडेम	280/1	00	11	55
		279	00	43	39
		281	00	23	13
		282/2	00	12	67
		282/1	00	00	25

		289/1	00	30	01
		288/5	00	09	78
		288/3	00	01	53
		288/4	00	16	82
		292/2	00	10	29
		292/1	00	15	39
		79/2	00	20	63
		78/1	00	33	04
		73	00	46	74
		77	00	02	41
		76	00	34	72
		66	00	02	13
		65	00	39	72
		63	00	19	91
		64	00	01	63
द्वारका तिरुमला	चेलिकनिवारी पोतेपल्ली	83/3	00	37	89
		82	00	46	60
		81/2	00	11	92
		81/1	00	02	91
		80/5	00	14	69
		80/3	00	09	56
		80/2	00	04	41
		80/1	00	15	00
		97/3	00	15	90
		97/2	00	10	41
		97/1	00	05	63
		98/4	00	00	32
		100/9	00	01	47
		100/8	00	09	98

		100/7	00	07	06
		100/11	00	10	08
		99/7	00	10	60
		99/6	00	09	62
		99/5	00	03	85
		100/6	00	17	63
		100/3	00	07	15
		100/1	00	01	42
		100/2	00	08	60
		101/1C	00	16	13
		45/4	00	36	21
		45/2	00	22	42
		44/5	00	02	73
		44/4	00	10	88
		44/6	00	05	53
		44/2	00	05	40
		44/1	00	06	30
		37/2F	00	11	98
		38/2	00	41	25

[फा. सं. आर-11025(11)/252/2017-ओआर-I/ई-21033]

पवन कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 11th January, 2018

**S.O. 52 .—** Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, published in the Gazette of India No. 947 Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated 06.04.2017 vide S.O. Number 1068 (E) dated 03.04.2017 issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land situated in Mandal Dwaraka Tirumala, District West Godavari in Andhra Pradesh State, specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of petroleum products from Paradip in the State of Odisha to Hyderabad in the State of Telangana by the Indian Oil Corporation Limited for implementing the "Paradip-Hyderabad Pipeline Project".

And whereas the copies of the Gazette were made available to the public. And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, has submitted his report of Central Government.

And whereas, the Central Government after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of the user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user of the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of the declaration, in India Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

### SCHEDULE

District : West Godavari			State : Andhra Pradesh		
Name of Mandal	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Dwaraka Tirumala	Jagannadhapuram	4/3	00	00	03
		4/2A	00	14	81
		4/2B	00	07	71
		4/2C	00	08	51
		4/1	00	00	16
		10/1	00	55	51
		10/2	00	10	01
		3/6	00	03	98
		11/2	00	12	96
		11/1	00	16	71
		15/1	00	00	23
Dwaraka Tirumala	G Kottapalli	20/1	00	16	25
		11	00	23	56
		10/4	00	05	93
		10/2J	00	05	47
		10/2E	00	05	56
		10/2D	00	05	17
		10/1B/4	00	03	06
		10/1B/3-2	00	09	60
		8/1C	00	21	19
		8/1E	00	03	64
		1/6	00	10	59
		1/3	00	10	15
		1/5	00	08	64
		1/4	00	10	05
		2/2	00	00	42
		2/1	00	00	05
		3/1	00	18	97
Dwaraka Tirumala	Kodigudem	280/1	00	11	55
		279	00	43	39
		281	00	23	13



		282/2	00	12	67
		282/1	00	00	25
		289/1	00	30	01
		288/5	00	09	78
		288/3	00	01	53
		288/4	00	16	82
		292/2	00	10	29
		292/1	00	15	39
		79/2	00	20	63
		78/1	00	33	04
		73	00	46	74
		77	00	02	41
		76	00	34	72
		66	00	02	13
		65	00	39	72
		63	00	19	91
		64	00	01	63
Dwaraka Tirumala	Chelikanivari Potepalli	83/3	00	37	89
		82	00	46	60
		81/2	00	11	92
		81/1	00	02	91
		80/5	00	14	69
		80/3	00	09	56
		80/2	00	04	41
		80/1	00	15	00
		97/3	00	15	90
		97/2	00	10	41
		97/1	00	05	63
		98/4	00	00	32
		100/9	00	01	47
		100/8	00	09	98
		100/7	00	07	06
		100/11	00	10	08
		99/7	00	10	60
		99/6	00	09	62
		99/5	00	03	85
		100/6	00	17	63
		100/3	00	07	15
		100/1	00	01	42
		100/2	00	08	60
		101/1C	00	16	13

		45/4	00	36	21
		45/2	00	22	42
		44/5	00	02	73
		44/4	00	10	88
		44/6	00	05	53
		44/2	00	05	40
		44/1	00	06	30
		37/2F	00	11	98
		38/2	00	41	25

[F. No. R-11025(11)/252/2017-OR-I/E-21033]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2018

**का.आ. 53.—** केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 उप धारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 1074(अ) तारीख 03.04.2017 जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र संख्या 948, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (II) तारीख 06.04.2017 में किया गया है। इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट आंध्रप्रदेश राज्य के मंडल : गोपालपुरम जिला: वेस्ट गोदावरी की भूमि में, ओडीशा राज्य में पारादीप से तेलंगाना राज्य में हैदराबाद तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे “पारादीप-हैदराबाद पाइपलाइन परियोजना” के संबंध में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी:

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं। और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए:

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए सभी बिल्लिंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

**अनुसूची**

जिला: वेस्ट गोदावरी			राज्य: आन्ध्रप्रदेश
मंडल का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे नम्बर	क्षेत्र फल

			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गोपालपुरम	भिमोलु	530/1	00	10	27
		529/2	00	05	15
		533/1	00	09	01
		529/1	00	23	22
		536/1	00	22	47
		520/2	00	13	96
		522	00	19	14
		521	01	13	60
गोपालपुरम	बेल्लार्चितलागुडेम	325	00	63	85
		601 & 602	02	62	97
		578	00	24	69
		584	00	38	46
		585/3	00	16	83
		585/1	00	03	80
		583/1	00	03	45
		590/2C	00	06	30
		590/1C	00	11	33
		557	00	14	74
		556/2	00	23	83
		550/1	00	24	52
		537	00	30	01
		538	00	28	10
		539	00	31	09
गोपालपुरम	गोपालपुरम	156/1	00	31	98
		155	00	62	15
		147	00	49	91
		127/2	00	17	62
		125	00	38	65
		124	00	21	86
		223/1A	00	19	49
		224	00	48	85
		232	00	18	34

		231	00	21	00
		226/3	00	22	98
		243	00	07	09
		242/2C	00	19	29
		242/2B	00	00	31
		242/2A	00	15	30
		242/1A	00	31	89
		250/3C	00	25	43
		250/3A	00	31	70
		249	00	38	79
		253/1A	00	02	21
		253/3A1	00	10	07
		254/8	00	18	35
		256/1A	00	02	43
		256/2A	00	00	60
गोपालपुरम	कोमटिकुंटा	58	00	31	20
		67/2	00	33	01
		67/3	00	09	72
		48/3A	00	13	97
		48/3B	00	01	02
		48/2	00	05	62
		48/1	00	10	25
		1	00	49	83
		45	00	36	16
		36	00	56	84
		35	00	21	72
		24	00	19	49
		32	00	45	51
		109	00	04	77

		111	00	58	44
		112/2	00	35	84
		121	00	18	13
		113	00	05	44
गोपालपुरम	वडलागुन्टा	35	00	31	11
		34	00	20	05
		33	00	30	99
		7	00	16	70
		8	00	29	57
		14	00	06	47

[फा. सं. आर-11025(11)/252/2017-ओआर-I/ई-21033]

पवन कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 11th January, 2018

**S.O. 53.**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, published in the Gazette of India No. 948 Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated 06.04.2017 vide S.O. Number 1074 (E) dated 03.04.2017 issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land situated in Mandal Gopalapuram, District West Godavari in Andhra Pradesh State, specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of petroleum products from Paradip in the State of Odisha to Hyderabad in the State of Telangana by the Indian Oil Corporation Limited for implementing the "Paradip-Hyderabad Pipeline Project".

And whereas the copies of the Gazette were made available to the public. And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, has submitted his report of Central Government.

And whereas, the Central Government after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of the user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user of the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

**SCHEDULE**

District : West Godavari			State : Andhra Pradesh		
Name of Mandal	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Gopalapuram	Bhimolu	530/1	00	10	27
		529/2	00	05	15
		533/1	00	09	01
		529/1	00	23	22
		536/1	00	22	47
		520/2	00	13	96
		522	00	19	14
		521	01	13	60
Gopalapuram	Vellachintalagudem	325	00	63	85
		601 & 602	02	62	97
		578	00	24	69
		584	00	38	46
		585/3	00	16	83
		585/1	00	03	80
		583/1	00	03	45
		590/2C	00	06	30
		590/1C	00	11	33
		557	00	14	74
		556/2	00	23	83
		550/1	00	24	52
		537	00	30	01
		538	00	28	10
		539	00	31	09
Gopalapuram	Gopalapuram	156/1	00	31	98
		155	00	62	15
		147	00	49	91
		127/2	00	17	62
		125	00	38	65
		124	00	21	86
		223/1A	00	19	49
		224	00	48	85
		232	00	18	34
		231	00	21	00
		226/3	00	22	98
		243	00	07	09
		242/2C	00	19	29
		242/2B	00	00	31
		242/2A	00	15	30
		242/1A	00	31	89
		250/3C	00	25	43
		250/3A	00	31	70
		249	00	38	79
		253/1A	00	02	21

		253/3A1	00	10	07
		254/8	00	18	35
		256/1A	00	02	43
		256/2A	00	00	60
Gopalapuram	Komatikunta	58	00	31	20
		67/2	00	33	01
		67/3	00	09	72
		48/3A	00	13	97
		48/3B	00	01	02
		48/2	00	05	62
		48/1	00	10	25
		1	00	49	83
		45	00	36	16
		36	00	56	84
		35	00	21	72
		24	00	19	49
		32	00	45	51
		109	00	04	77
		111	00	58	44
		112/2	00	35	84
		121	00	18	13
		113	00	05	44
Gopalapuram	Vadlagunta	35	00	31	11
		34	00	20	05
		33	00	30	99
		7	00	16	70
		8	00	29	57
		14	00	06	47

[F. No. R-11025(11)/252/2017-OR-I/E-21033]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2018

**का.आ. 54.—** केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 उप धारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 1073(अ) तारीख 03.04.2017 जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र संख्या 948, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (II) तारीख 06.04.2017 में किया गया है। इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट आंध्रप्रदेश राज्य के मंडल : ताल्लपुडी जिला: वेस्ट गोदावरी की भूमि में, ओडीशा राज्य में पारादीप से तेलंगाना राज्य में

हैदराबाद तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे “पारादीप-हैदराबाद पाइपलाइन परियोजना” के संबंध में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी:

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं। और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए सभी बिल्लिंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

### अनुसूची

जिला: वेस्ट गोदावरी			राज्य: आन्ध्रप्रदेश		
मंडल का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ताल्लपुडी	बय्यावरम	111/7	00	06	11
		111/6	00	00	59
		111/9	00	05	81
		79/3	00	01	18
		79/4	00	09	80
		78/1	00	00	14
		76/1	00	13	69
		76/2	00	15	00
		78/2	00	00	74
		76/3	00	28	25
ताल्लपुडी	रागोलापल्ली	261/1A	00	08	97
		260/5	00	17	95
		260/4	00	12	07
		254/2	00	31	35
		254/1	00	16	46
		251/2	00	02	38



		251/1	00	11	18
		250/4	00	00	08
		252/6	00	10	29
		250/2	00	09	22
		250/1	00	13	88
		249/4	00	17	86
ताल्लपुडी	तुपाकुलागुडेम	247	00	00	90
		241	00	26	64
		240	00	12	39
		232/3	00	04	90
		232/4	00	19	00
		234	00	10	62
		225/1	00	01	42
		225/3	00	16	20
		225/4	00	13	11
		142/2	00	18	33
		142/1	00	00	66
		142/3	00	15	64
		142/4	00	19	59
		145	00	44	18
		161/1	00	05	11
		161/2	00	10	71
		162/1	00	05	71
		162/4	00	01	28
		180	00	03	57
ताल्लपुडी	अन्नादेवरपेटा	216/1	00	17	84
		217	00	29	77
		214	00	27	12
		213	00	00	03

		221/1	00	19	63
		221/4	00	00	03
		221/3	00	09	06
		221/2	00	08	70
		228/3	00	12	87
		229	00	19	09
		281/1	00	12	56
		281/2	00	12	71
		279/1	00	00	0.19
		289	00	17	65
		290/2	00	17	42
		258/1	00	10	60
		273/2	00	09	01
		273/1	00	08	17
		272/3	00	07	20
		272/2	00	03	40
		260/1	00	04	04
		263/4B	00	02	97
		263/3	00	08	48
		263/2	00	07	52
		263/1	00	08	14
		270	00	16	34
		358	00	27	65
		347	00	00	24
		349	00	37	66
		348	00	02	02
		351/2	00	30	09
		352/3A	00	10	73

		352/1	00	08	84
		352/2	00	05	56
		341/3	00	09	55

[फा. सं. आर-11025(11)/252/2017-ओआर-I/ई-21033]

पवन कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 11th January, 2018

**S.O. 54.—** Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, published in the Gazette of India No. 948 Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated 06.04.2017 vide S.O. Number 1073 (E) dated 03.04.2017 issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land situated in Mandal Tallapudi, District West Godavari in Andhra Pradesh State, specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of petroleum products from Paradip in the State of Odisha to Hyderabad in the State of Telangana by the Indian Oil Corporation Limited for implementing the "Paradip-Hyderabad Pipeline Project".

And whereas the copies of the Gazette were made available to the public. And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, has submitted his report of Central Government.

And whereas, the Central Government after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of the user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user of the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

**SCHEDULE**

District : West Godavari

State : Andhra Pradesh

Name of Mandal	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tallapudi	Bayyavaram	111/7	00	06	11
		111/6	00	00	59
		111/9	00	05	81
		79/3	00	01	18
		79/4	00	09	80
		78/1	00	00	14
		76/1	00	13	69
		76/2	00	15	00
		78/2	00	00	74
		76/3	00	28	25
Tallapudi	Ragolapalli	261/1A	00	08	97
		260/5	00	17	95
		260/4	00	12	07
		254/2	00	31	35

		254/1	00	16	46
		251/2	00	02	38
		251/1	00	11	18
		250/4	00	00	08
		252/6	00	10	29
		250/2	00	09	22
		250/1	00	13	88
		249/4	00	17	86
Tallapudi	Tupakulagudem	247	00	00	90
		241	00	26	64
		240	00	12	39
		232/3	00	04	90
		232/4	00	19	00
		234	00	10	62
		225/1	00	01	42
		225/3	00	16	20
		225/4	00	13	11
		142/2	00	18	33
		142/1	00	00	66
		142/3	00	15	64
		142/4	00	19	59
		145	00	44	18
		161/1	00	05	11
		161/2	00	10	71
		162/1	00	05	71
		162/4	00	01	28
		180	00	03	57
Tallapudi	Annadevarapeta	216/1	00	17	84
		217	00	29	77
		214	00	27	12
		213	00	00	03
		221/1	00	19	63
		221/4	00	00	03
		221/3	00	09	06
		221/2	00	08	70
		228/3	00	12	87
		229	00	19	09
		281/1	00	12	56

		281/2	00	12	71
		279/1	00	00	0.19
		289	00	17	65
		290/2	00	17	42
		258/1	00	10	60
		273/2	00	09	01
		273/1	00	08	17
		272/3	00	07	20
		272/2	00	03	40
		260/1	00	04	04
		263/4B	00	02	97
		263/3	00	08	48
		263/2	00	07	52
		263/1	00	08	14
		270	00	16	34
		358	00	27	65
		347	00	00	24
		349	00	37	66
		348	00	02	02
		351/2	00	30	09
		352/3A	00	10	73
		352/1	00	08	84
		352/2	00	05	56
		341/3	00	09	55

[F. No. R-11025(11)/252/2017-OR-I/E-21033]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2018

**का.आ. 55.—** केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पारादीप (ओडिशा) से हैदराबाद (तेलंगाना) तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा "पारादीप-हैदराबाद पाइपलाइन" बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है और जिस में उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें

उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री दिल्लिप कुमार महांति, सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पारादीप-हैदराबाद पाइपलाइन परियोजना, तृतीय तल, आलोक भारती टावर, शहीद नगर, भुवनेश्वर -751007, ओडिशा को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

### अनुसूची

तहसील-जटणी	जिला - खोर्द्धा	राज्य-ओडिशा		
गाँव का नाम	प्लॉट नं.		क्षेत्रफल	
		हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
पाण्डिआबील	428	00	21	56
	434	00	01	09
	382	00	09	28
	381	00	04	99
	361	00	05	83
	360	00	11	02
	357	00	01	72
	359	00	00	69
	358	00	00	73
	354	00	00	15
	440	00	01	86
	441	00	00	55
	442	00	11	92
	427	00	01	53
	426	00	01	46
	348	00	02	43
	344	00	00	72
	345	00	00	10

[फा. सं. आर-11025(11)/236/2017-ओआर-I/ई-13717]

पवन कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 11th January, 2018

**S.O. 55.—** Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum products from Paradip (Odisha) to Hyderabad (Telangana), “Paradip-Hyderabad Pipeline” should be laid by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Sri Dillip Kumar Mohanty, Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Paradip-Hyderabad Pipeline Project, 3rd Floor, Alok Bharati Tower, Saheed Nagar, Bhubaneswar- 751007, (Odisha).

#### SCHEDULE

Tehsil : JATANI	District : KHORDHA	State : ODISHA		
Name of the Village	Plot No.	Area		
		Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5
PANDIABIL	428	00	21	56
	434	00	01	09
	382	00	09	28
	381	00	04	99
	361	00	05	83
	360	00	11	02
	357	00	01	72
	359	00	00	69
	358	00	00	73
	354	00	00	15
	440	00	01	86
	441	00	00	55
	442	00	11	92
	427	00	01	53
	426	00	01	46
	348	00	02	43
	344	00	00	72
	345	00	00	10

[F. No. R-11025(11)/236/2017-OR-I/E-13717]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2018

**का.आ. 56.—** केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि हल्दीया - बरौनी पाइपलाइन पारियोजना के अन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन हेतु पश्चिम बंगाल राज्य के हल्दीया रिफ़ाइनरी से बिहार राज्य के बरौनी रिफ़ाइनरी तक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसके भीतर उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 कि उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको, भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के अन्दर, भूमि के भीतर पाइपलाइन बिछाए जाने हेतु उपयोग के अधिकार के अर्जन के लिए, श्री भुवनेश्वर मिश्रा, से० नि० अपर सचिव बिहार सरकार व सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पाइपलाइंस डिविजन), बी० के० पी० एल० मुख्यालय परिसर, पो० बरौनी आयल रिफ़ाइनरी, जिला बेगूसराय, पिन- 851114 (बिहार) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा ।

### अनुसूची

जिला : पटना			राज्य : बिहार		
अंचल	मौज़ा का नाम	सर्वे / प्लॉट नम्बर	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मोकामा	जलाल पुर नौरंगा - 13	631	00	01	06
		630	00	12	71
		2677	00	09	93
		629	00	07	37
		628	00	06	54
		627	00	05	57
		626	00	06	52
		625	00	09	15
		624	00	02	76
		442	00	01	85
		443	00	02	84
		162	00	14	95
		161	00	03	75
		160	00	04	84
		134	00	09	01
		141	00	03	60
		139	00	04	12



		140	00	02	75
		138	00	01	81
		130	00	03	36
		143	00	13	77
		144	00	10	13
		145	00	00	59
		126	00	06	61
मोकामा	राम पुर डुमरा - 15	1423	00	00	62
		1422	00	17	59
		1421	00	18	47
		1377	00	18	47
		1378	00	01	75
		1356	00	13	02
		1311	00	01	18
		1312	00	08	00
		1313	00	07	46
		1314	00	00	52
		1286	00	10	43
		1277	00	09	48
		1278	00	09	05
		3928	00	15	02
		1145	00	20	88
		1150	00	03	20
		1148	00	10	08
		1147	00	14	98
		3707	00	00	20
मोकामा	मरांची - 19	1277	00	14	55
		1400	00	05	68
		1271	00	30	68

		1266	00	11	99
		1425	00	03	79
		1426	00	00	33
		1427	00	08	02
		1428	00	04	08
		1429	00	03	04
		1430	00	03	71
		1263	00	05	47
		1435	00	05	28
		1455	00	00	20
		1456	00	06	63
		1457	00	02	38
		8555	00	05	26
		1459	00	03	11
		1487	00	16	68
		1488	00	14	28
		8520	00	05	38
		1561	00	04	17
		1563	00	01	99
		1564	00	02	82
		1565	00	02	81
		1570	00	06	21
		1571	00	09	58
		1572	00	03	58
		1573	00	06	02
		1654	00	03	08
		1653	00	01	54
		1657	00	02	52
		8523	00	02	20

		1658	00	04	67
		1659	00	02	75
		1660	00	00	33
		1664	00	06	26
		1663	00	01	19
		1679	00	05	81
		1680	00	03	63
		8583	00	02	38
		1681	00	00	40
		8582	00	11	70
		8581	00	04	50
		8160	00	05	43
		8170	00	00	20
		8169	00	01	87
		8167	00	01	99
		8166	00	02	66
		8165	00	02	62
		8164	00	01	84
		8163	00	02	57
		8162	00	02	75
		8161	00	03	14
		521	00	03	07
		519	00	03	31
		520	00	07	10
		517	00	00	20
		8181	00	03	63
		8207	00	07	88
		8206	00	01	54
		356	00	03	18
		355	00	00	25
		354	00	26	08

		353	00	04	69
		305	00	00	99
		306	00	02	32
		8228	00	03	08
		303	00	05	28
		304	00	01	36
		301	00	06	32
		283	00	05	49
		280	00	12	35
		8241	00	03	89
		255	00	06	00
		253	00	05	12
		247	00	10	29
		241	00	03	80
		8274	00	02	98
		8273	00	04	50
		240	00	04	35
		8279	00	03	19
		8278	00	03	00
		191	00	07	86
		190	00	07	07
		189	00	07	73
		8136	00	04	54
		185	00	03	52
		168	00	02	14
		169	00	06	10
		164	00	05	45
		136	00	11	64
		135	00	03	10

		137	00	03	73
		117	00	03	07
		116	00	03	46
		97	00	31	36
		82	00	07	83
		70	00	10	73
		71	00	02	01
		65	00	07	60
		62	00	05	81
		61	00	07	90
		49	00	08	49
		8087	00	01	70
		8080	00	01	80
		8068	00	04	24
		8057	00	00	53
		8058	00	06	34
		41	00	13	15
		39	00	06	49
		38	00	32	45
		37	00	00	81
मोकामा	हथिदह खुरद - 21	564	00	00	20
		563	00	00	64
		562	00	03	62
		561	00	03	19
		560	00	01	65
		559	00	01	23
		558	00	00	77
		557	00	00	42
		555	00	02	86

		556	00	06	25
		514	00	06	15
		513	00	06	18
		512	00	11	71
		302	00	07	25
		507	00	12	55
		475	00	08	41
		476	00	09	73
		477	00	14	09
		474	00	00	20
		500	00	00	20
		478	00	00	24
		473	00	06	22
		464	00	04	34
		465	00	05	69
		408	00	02	82
		405	00	06	86
		404	00	04	39
		400	00	00	20
		402	00	17	57
		390	00	03	79
		389	00	01	28
		388	00	00	20
		508	00	10	61
		509	00	10	28
		520	00	11	36
		542	00	01	21
		521	00	00	27
		541	00	04	94

		540	00	10	85
		588	00	06	84
		589	00	01	64
		587	00	01	04
		590	00	03	40
		591	00	04	05
		586	00	00	20
		592	00	09	05
		593	00	01	39
		533	00	24	39
		607	00	00	20
		608	00	04	06
		609	00	01	25
		611	00	05	26
		612	00	01	42
		613	00	01	10
		614	00	02	01
		616	00	07	37
		617	00	15	33
		647	00	04	85
		648	00	05	30
		650	00	02	52
		653	00	01	46
		657	00	01	40
		658	00	02	50
		659	00	11	00
		660	00	03	01
		661	00	03	22
मोकामा	हथिदहबुजुरुग - 20	2421	00	22	30
		2419	00	03	01

		2416	00	03	90
		2448	00	02	73
		2408	00	00	96
		2409	00	10	92
		1099	00	03	40
		2403	00	00	56
		2402	00	09	27
		2399	00	03	33
		2386	00	03	44
		2384	00	01	14
		2380	00	01	52
		2373	00	01	74
		2368	00	01	15
		2369	00	00	29
		2363	00	01	84
		2362	00	01	29
		2360	00	00	98
		2359	00	01	47
		2354	00	01	41
		2353	00	02	17
		2352	00	02	41
		2209	00	02	28
		2211	00	02	94
		2213	00	01	35
		2214	00	01	94
		2215	00	04	13
		2218	00	01	78
		2219	00	01	62
		2222	00	00	20
		2224	00	02	90
		2225	00	03	44



		2228	00	02	99
		2230	00	00	20
		2229	00	03	70
		2155	00	02	02
		2156	00	00	86
		2180	00	00	57
		2257	00	02	50
		2153	00	00	49
		2158	00	01	35
		2152	00	00	47
		2159	00	03	87
		2145	00	03	96
		2140	00	02	15
		2139	00	02	01
		2134	00	01	68
		2138	00	00	26
		2135	00	00	87
		2122	00	08	02
		2121	00	08	72
		2136	00	00	75
		2115	00	05	09
		2114	00	03	41
		2059	00	07	31
		1149	00	03	76
		2029	00	02	85
		2030	00	01	60
		2031	00	02	68
		2028	00	00	41
		2032	00	02	03
		2017	00	03	34

		2013	00	02	18
		2008	00	03	16
		2007	00	00	39
		2006	00	00	26
		2002	00	10	59
		2009	00	00	44
		2010	00	01	19
		1653	00	04	73
		1595	00	00	20
		1651	00	03	94
		1652	00	02	41
		1654	00	00	29
		1614	00	05	82
		1650	00	02	01
		1647	00	00	94
		1617	00	00	66
		1618	00	01	01
		1616	00	05	91
		1615	00	04	17
		1631	00	07	29
		1630	00	02	45
		1632	00	00	20
		2833	00	04	85
		2834	00	00	20
		252	00	06	29
		251	00	00	20
		250	00	02	17
		231	00	01	06
		220	00	00	50

		221	00	24	97
		2847	00	07	80
मोकामा	कसया दियारामराची - 10	639	00	03	07
		640	00	01	49
		641	00	01	81
		644	00	04	96
		645	00	02	24
		646	00	01	16
		647	00	00	94
		648	00	02	41
		649	00	01	74
		652	00	02	20
		656	00	03	34
		655	00	00	20
		662	00	01	71

[फा. सं. आर-11025(11)/251/2017-ओआर-I/ई-20885]

पवन कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 11th January, 2018

**S.O. 56.—** Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Petroleum Products from Haldia Refinery in the state of West Bengal to Barauni Refinery in the State of Bihar a pipeline should be laid by Indian Oil Corporation Limited.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri. Bhubneshwar Mishra, Additional Secretary (Retd.), Govt. of Bihar & Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Pipeline Division, BKPL Head Quarter, Post- Barauni Oil Refinery, District – Begusarai, Bihar – 851114.

**SCHEDULE**

District : Patna			State : Bihar		
Anchal	Name of Mouza	Survey / Plot No.	Area		
			Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Mokama	Jalalpur Nauranga - 13	631	00	01	06
		630	00	12	71
		2677	00	09	93
		629	00	07	37
		628	00	06	54
		627	00	05	57
		626	00	06	52
		625	00	09	15
		624	00	02	76
		442	00	01	85
		443	00	02	84
		162	00	14	95
		161	00	03	75
		160	00	04	84
		134	00	09	01
		141	00	03	60
		139	00	04	12
		140	00	02	75
		138	00	01	81
		130	00	03	36
		143	00	13	77
		144	00	10	13
		145	00	00	59
		126	00	06	61
Mokama	Rampur Dumra - 15	1423	00	00	62
		1422	00	17	59
		1421	00	18	47
		1377	00	18	47
		1378	00	01	75
		1356	00	13	02
		1311	00	01	18
		1312	00	08	00
		1313	00	07	46
		1314	00	00	52
		1286	00	10	43
		1277	00	09	48
		1278	00	09	05
		3928	00	15	02
		1145	00	20	88

		1150	00	03	20
		1148	00	10	08
		1147	00	14	98
		3707	00	00	20
Mokama	Maranchi -19	1277	00	14	55
		1400	00	05	68
		1271	00	30	68
		1266	00	11	99
		1425	00	03	79
		1426	00	00	33
		1427	00	08	02
		1428	00	04	08
		1429	00	03	04
		1430	00	03	71
		1263	00	05	47
		1435	00	05	28
		1455	00	00	20
		1456	00	06	63
		1457	00	02	38
		8555	00	05	26
		1459	00	03	11
		1487	00	16	68
		1488	00	14	28
		8520	00	05	38
		1561	00	04	17
		1563	00	01	99
		1564	00	02	82
		1565	00	02	81
		1570	00	06	21
		1571	00	09	58
		1572	00	03	58
		1573	00	06	02
		1654	00	03	08
		1653	00	01	54
		1657	00	02	52
		8523	00	02	20
		1658	00	04	67
		1659	00	02	75
		1660	00	00	33

		1664	00	06	26
		1663	00	01	19
		1679	00	05	81
		1680	00	03	63
		8583	00	02	38
		1681	00	00	40
		8582	00	11	70
		8581	00	04	50
		8160	00	05	43
		8170	00	00	20
		8169	00	01	87
		8167	00	01	99
		8166	00	02	66
		8165	00	02	62
		8164	00	01	84
		8163	00	02	57
		8162	00	02	75
		8161	00	03	14
		521	00	03	07
		519	00	03	31
		520	00	07	10
		517	00	00	20
		8181	00	03	63
		8207	00	07	88
		8206	00	01	54
		356	00	03	18
		355	00	00	25
		354	00	26	08
		353	00	04	69
		305	00	00	99
		306	00	02	32
		8228	00	03	08
		303	00	05	28
		304	00	01	36
		301	00	06	32
		283	00	05	49
		280	00	12	35
		8241	00	03	89
		255	00	06	00
		253	00	05	12

		247	00	10	29
		241	00	03	80
		8274	00	02	98
		8273	00	04	50
		240	00	04	35
		8279	00	03	19
		8278	00	03	00
		191	00	07	86
		190	00	07	07
		189	00	07	73
		8136	00	04	54
		185	00	03	52
		168	00	02	14
		169	00	06	10
		164	00	05	45
		136	00	11	64
		135	00	03	10
		137	00	03	73
		117	00	03	07
		116	00	03	46
		97	00	31	36
		82	00	07	83
		70	00	10	73
		71	00	02	01
		65	00	07	60
		62	00	05	81
		61	00	07	90
		49	00	08	49
		8087	00	01	70
		8080	00	01	80
		8068	00	04	24
		8057	00	00	53
		8058	00	06	34
		41	00	13	15
		39	00	06	49
		38	00	32	45
		37	00	00	81
Mokama	Hathidhah Khurd - 21	564	00	00	20
		563	00	00	64
		562	00	03	62
		561	00	03	19

		560	00	01	65
		559	00	01	23
		558	00	00	77
		557	00	00	42
		555	00	02	86
		556	00	06	25
		514	00	06	15
		513	00	06	18
		512	00	11	71
		302	00	07	25
		507	00	12	55
		475	00	08	41
		476	00	09	73
		477	00	14	09
		474	00	00	20
		500	00	00	20
		478	00	00	24
		473	00	06	22
		464	00	04	34
		465	00	05	69
		408	00	02	82
		405	00	06	86
		404	00	04	39
		400	00	00	20
		402	00	17	57
		390	00	03	79
		389	00	01	28
		388	00	00	20
		508	00	10	61
		509	00	10	28
		520	00	11	36
		542	00	01	21
		521	00	00	27
		541	00	04	94
		540	00	10	85
		588	00	06	84
		589	00	01	64
		587	00	01	04
		590	00	03	40



		591	00	04	05
		586	00	00	20
		592	00	09	05
		593	00	01	39
		533	00	24	39
		607	00	00	20
		608	00	04	06
		609	00	01	25
		611	00	05	26
		612	00	01	42
		613	00	01	10
		614	00	02	01
		616	00	07	37
		617	00	15	33
		647	00	04	85
		648	00	05	30
		650	00	02	52
		653	00	01	46
		657	00	01	40
		658	00	02	50
		659	00	11	00
		660	00	03	01
		661	00	03	22
Mokama	Hathidah Buzurg - 20	2421	00	22	30
		2419	00	03	01
		2416	00	03	90
		2448	00	02	73
		2408	00	00	96
		2409	00	10	92
		1099	00	03	40
		2403	00	00	56
		2402	00	09	27
		2399	00	03	33
		2386	00	03	44
		2384	00	01	14
		2380	00	01	52
		2373	00	01	74
		2368	00	01	15
		2369	00	00	29

		2363	00	01	84
		2362	00	01	29
		2360	00	00	98
		2359	00	01	47
		2354	00	01	41
		2353	00	02	17
		2352	00	02	41
		2209	00	02	28
		2211	00	02	94
		2213	00	01	35
		2214	00	01	94
		2215	00	04	13
		2218	00	01	78
		2219	00	01	62
		2222	00	00	20
		2224	00	02	90
		2225	00	03	44
		2228	00	02	99
		2230	00	00	20
		2229	00	03	70
		2155	00	02	02
		2156	00	00	86
		2180	00	00	57
		2257	00	02	50
		2153	00	00	49
		2158	00	01	35
		2152	00	00	47
		2159	00	03	87
		2145	00	03	96
		2140	00	02	15
		2139	00	02	01
		2134	00	01	68
		2138	00	00	26
		2135	00	00	87
		2122	00	08	02
		2121	00	08	72
		2136	00	00	75

		2115	00	05	09
		2114	00	03	41
		2059	00	07	31
		1149	00	03	76
		2029	00	02	85
		2030	00	01	60
		2031	00	02	68
		2028	00	00	41
		2032	00	02	03
		2017	00	03	34
		2013	00	02	18
		2008	00	03	16
		2007	00	00	39
		2006	00	00	26
		2002	00	10	59
		2009	00	00	44
		2010	00	01	19
		1653	00	04	73
		1595	00	00	20
		1651	00	03	94
		1652	00	02	41
		1654	00	00	29
		1614	00	05	82
		1650	00	02	01
		1647	00	00	94
		1617	00	00	66
		1618	00	01	01
		1616	00	05	91
		1615	00	04	17
		1631	00	07	29
		1630	00	02	45
		1632	00	00	20
		2833	00	04	85
		2834	00	00	20
		252	00	06	29
		251	00	00	20
		250	00	02	17
		231	00	01	06
		220	00	00	50

		221	00	24	97
		2847	00	07	80
Mokama	Kasaya Diyara Maranchi - 10	639	00	03	07
		640	00	01	49
		641	00	01	81
		644	00	04	96
		645	00	02	24
		646	00	01	16
		647	00	00	94
		648	00	02	41
		649	00	01	74
		652	00	02	20
		656	00	03	34
		655	00	00	20
		662	00	01	71

[F. No. R-11025(11)/251/2017-OR-I/E-20885]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2018

**का.आ. 57.—** केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 उप धारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 1071(अ) तारीख 03.04.2017 जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र संख्या 948, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (II) तारीख 06.04.2017 में किया गया है। इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट आंध्रप्रदेश राज्य के मंडल : कोय्यालगुडेम जिला: वेस्ट गोदावरी की भूमि में, ओडीशा राज्य में पारादीप से तेलंगाना राज्य में हैदराबाद तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे “पारादीप-हैदराबाद पाइपलाइन परियोजना” के संबंध में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी:

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं। और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए:

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए सभी बिल्लिंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

**अनुसूची**

जिला: वेस्ट गोदावरी			राज्य: आन्ध्रप्रदेश
मंडल का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल

			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोय्यालागुडेम	कंकाद्रिपुरम	95	00	13	97
		98/1	00	00	35
		91	00	59	02
		88/2	00	05	78
		89	00	51	75
		68/4	00	04	25
		69/1	00	16	06
		69/2	00	16	13
		70/1	00	02	12
		65/3	00	38	19
		65/1	00	08	71
		64/2	00	19	90
		55/3	00	10	92
		55/1	00	16	13
		55/2	00	05	01
		59/9	00	05	40
		59/8	00	05	48
		59/7	00	06	35
		59/6	00	12	83
		59/4	00	05	75
		59/3	00	03	20
		59/1	00	03	18
कोय्यालागुडेम	येरम्पेटा	232/4	00	03	31
		233	00	31	73
		230/2	00	25	57
		229/1	00	08	81
		235/1	00	18	88
		228/3	00	17	01
		236	00	02	68

		237/1	00	22	93
		221/3	00	07	28
		220/3	00	14	44
		220/1	00	23	55
		220/2	00	06	68
		218	00	00	59
		198/2	00	00	0.19
		198/3	00	17	97
		199	00	00	81
		200/3	00	15	99
		200/4	00	21	18
		212/2	00	03	53
		212/1	00	05	05
		212/4	00	00	07
		200/5	00	04	11
		201/6	00	15	59
		201/5	00	03	81
		201/4	00	09	28
		201/3	00	02	81
		202/1	00	09	15
		183	00	42	53
कोय्यालागुडेम	राजवाराम	518	00	12	12
		516	00	22	11
		509/1	00	01	55
		509/2	00	16	88
		510	00	02	93
		508	00	27	81
		507	00	10	81
		495	00	05	84

		496/6	00	04	99
		496/5	00	03	70
		496/4	00	01	73
		496/3	00	00	06
		490/1	00	18	65
		490/2	00	16	88
		488/1	00	00	08
		488/2	00	01	90
		489/2	00	07	15
		486/2	00	21	19
		485	00	45	21
		484/1	00	01	09
		245/2	00	00	09
		248/3	00	07	36
		248/2	00	14	71
		248/1	00	03	24
		245/1	00	17	28
		246/2	00	03	95
		246/1	00	01	49
		239/1	00	13	31
		239/3	00	18	38
		239/2	00	07	35
		238/1	00	09	87
		225/1	00	06	01
		225/2	00	20	57
		225/3	00	06	04
		223/4	00	09	60
		223/3	00	08	57
		223/2	00	07	97
		223/1	00	01	35

		222/B	00	15	25
		222/A	00	11	85
		229	00	00	90
		220/3	00	13	21
		220/2	00	22	23
		220/1	00	01	86
		218	00	04	52
		219/1	00	10	90
		219/2	00	07	15
		219/3A	00	06	75
		212	00	00	14
		211/1	00	17	81
		210/2A	00	21	88
		210/1A	00	15	98
		210/3A	00	21	88
		209/2A	00	18	65
		209/1A	00	27	46

[फा. सं. आर-11025(11)/252/2017-ओआर-I/ई-21033]

पवन कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 11th January, 2018

**S.O. 57.—** Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, published in the Gazette of India No. 948 Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated 06.04.2017 vide S.O. Number 1071 (E) dated 03.04.2017 issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land situated in Mandal Koyyalagudem, District West Godavari in Andhra Pradesh State, specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of petroleum products from Paradip in the State of Odisha to Hyderabad in the State of Telangana by the Indian Oil Corporation Limited for implementing the "Paradip-Hyderabad Pipeline Project".

And whereas the copies of the Gazette were made available to the public. And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, has submitted his report of Central Government.

And whereas, the Central Government after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of the user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user of the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the



Central Government, vests on the date of publication of the declaration, in India Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

**SCHEDULE**

District : West Godavari			State : Andhra Pradesh		
Name of Mandal	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Koyyalagudem	Kankadripuram	95	00	13	97
		98/1	00	00	35
		91	00	59	02
		88/2	00	05	78
		89	00	51	75
		68/4	00	04	25
		69/1	00	16	06
		69/2	00	16	13
		70/1	00	02	12
		65/3	00	38	19
		65/1	00	08	71
		64/2	00	19	90
		55/3	00	10	92
		55/1	00	16	13
		55/2	00	05	01
		59/9	00	05	40
		59/8	00	05	48
		59/7	00	06	35
		59/6	00	12	83
		59/4	00	05	75
		59/3	00	03	20
		59/1	00	03	18
Koyyalagudem	Yerrampeta	232/4	00	03	31
		233	00	31	73
		230/2	00	25	57
		229/1	00	08	81
		235/1	00	18	88
		228/3	00	17	01
		236	00	02	68
		237/1	00	22	93
		221/3	00	07	28
		220/3	00	14	44
		220/1	00	23	55

		220/2	00	06	68
		218	00	00	59
		198/2	00	00	0.19
		198/3	00	17	97
		199	00	00	81
		200/3	00	15	99
		200/4	00	21	18
		212/2	00	03	53
		212/1	00	05	05
		212/4	00	00	07
		200/5	00	04	11
		201/6	00	15	59
		201/5	00	03	81
		201/4	00	09	28
		201/3	00	02	81
		202/1	00	09	15
		183	00	42	53
Koyyalagudem	Rajavaram	518	00	12	12
		516	00	22	11
		509/1	00	01	55
		509/2	00	16	88
		510	00	02	93
		508	00	27	81
		507	00	10	81
		495	00	05	84
		496/6	00	04	99
		496/5	00	03	70
		496/4	00	01	73
		496/3	00	00	06
		490/1	00	18	65
		490/2	00	16	88
		488/1	00	00	08
		488/2	00	01	90
		489/2	00	07	15
		486/2	00	21	19
		485	00	45	21
		484/1	00	01	09
		245/2	00	00	09
		248/3	00	07	36
		248/2	00	14	71

		248/1	00	03	24
		245/1	00	17	28
		246/2	00	03	95
		246/1	00	01	49
		239/1	00	13	31
		239/3	00	18	38
		239/2	00	07	35
		238/1	00	09	87
		225/1	00	06	01
		225/2	00	20	57
		225/3	00	06	04
		223/4	00	09	60
		223/3	00	08	57
		223/2	00	07	97
		223/1	00	01	35
		222/B	00	15	25
		222/A	00	11	85
		229	00	00	90
		220/3	00	13	21
		220/2	00	22	23
		220/1	00	01	86
		218	00	04	52
		219/1	00	10	90
		219/2	00	07	15
		219/3A	00	06	75
		212	00	00	14
		211/1	00	17	81
		210/2A	00	21	88
		210/1A	00	15	98
		210/3A	00	21	88
		209/2A	00	18	65
		209/1A	00	27	46

[F. No. R-11025(11)/252/2017-OR-I/E-21033]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2018

**का.आ. 58.—** केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 उप धारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 1072(अ) तारीख 03.04.2017 जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र संख्या 948, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (II) तारीख 06.04.2017 में किया गया है। इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में

विनिर्दिष्ट आंध्रप्रदेश राज्य के मंडल : पोलावरम जिला: पश्चिम गोदावरी की भूमि में, ओडीशा राज्य में पारादीप से तेलंगाना राज्य में हैदराबाद तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे "पारादीप-हैदराबाद पाइपलाइन परियोजना" के संबंध में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी:

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं। और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए:

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए सभी बिल्लिंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

### अनुसूची

जिला: वेस्ट गोदावरी			राज्य: आन्ध्रप्रदेश		
मंडल का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पोलावरम	गुटाला	833/3A	00	09	98
		833/2	00	03	93
		833/4	00	07	84
		831/2	00	02	46
		831/3	00	28	12
		832/1	00	07	86
		806/2	00	21	78
		806/1	00	01	96
		807	00	26	72
		797	00	01	18
		796/2	00	00	80
		789/3	00	36	11
		789/2	00	18	47
		790/1A	00	05	85
		790/3	00	15	14

		790/2	00	08	57
		791/2	00	01	07
		791/1	00	12	57
		774/1	00	04	54
		774/2	00	21	33
		773/1	00	11	88
		768/7	00	13	18
		769/4	00	15	80
		769/3	00	21	96
		769/2	00	04	51

[फा. सं. आर-11025(11)/252/2017-ओआर-I/ई-21033]

पवन कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 11th January, 2018

**S.O. 58.—** Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, published in the Gazette of India No. 948 Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated 06.04.2017 vide S.O. Number 1072 (E) dated 03.04.2017 issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land situated in Mandal polavaram, District West Godavari in Andhra Pradesh State, specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of petroleum products from Paradip in the State of Odisha to Hyderabad in the State of Telangana by the Indian Oil Corporation Limited for implementing the "Paradip-Hyderabad Pipeline Project".

And whereas the copies of the Gazette were made available to the public. And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, has submitted his report of Central Government.

And whereas, the Central Government after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of the user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user of the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of the declaration, in India Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

**SCHEDULE**

District : West Godavari			State : Andhra Pradesh		
Name of Mandal	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Polavaram	Gutala	833/3A	00	09	98

		833/2	00	03	93
		833/4	00	07	84
		831/2	00	02	46
		831/3	00	28	12
		832/1	00	07	86
		806/2	00	21	78
		806/1	00	01	96
		807	00	26	72
		797	00	01	18
		796/2	00	00	80
		789/3	00	36	11
		789/2	00	18	47
		790/1A	00	05	85
		790/3	00	15	14
		790/2	00	08	57
		791/2	00	01	07
		791/1	00	12	57
		774/1	00	04	54
		774/2	00	21	33
		773/1	00	11	88
		768/7	00	13	18
		769/4	00	15	80
		769/3	00	21	96
		769/2	00	04	51

[F. No. R-11025(11)/252/2017-OR-I/E-21033]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2018

**का.आ. 59.**—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 उप धारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 1070(अ) तारीख 03.04.2017 जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र संख्या 947, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (II) तारीख 06.04.2017 में किया गया है। इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट आंध्रप्रदेश राज्य के मंडल : जंगारेद्दीगूडेम जिला: पश्चिम गोदावरी की भूमि में, ओडीशा राज्य में पारादीप से तेलंगाना राज्य में हैदराबाद तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे “पारादीप-हैदराबाद पाइपलाइन परियोजना” के संबंध में पाइपलाइन विछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी:

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं। और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए:

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए सभी बिल्लिंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

### अनुसूची

जिला: वेस्ट गोदावरी			राज्य: आन्ध्रप्रदेश		
मंडल का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जंगारेड्डीगुडेम	निम्मालागुडेम	199	00	00	10
		198	00	31	14
		254	00	61	85

[फा. सं. आर-11025(11)/252/2017-ओआर-I/ई-21033]

पवन कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 11th January, 2018

**S.O. 59.**— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, published in the Gazette of India No. 947 Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated 06.04.2017 vide S.O. Number 1070 (E) dated 03.04.2017 issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land situated in Mandal Jangareddigudem, District West Godavari in Andhra Pradesh State, specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of petroleum products from Paradip in the State of Odisha to Hyderabad in the State of Telangana by the Indian Oil Corporation Limited for implementing the "Paradip-Hyderabad Pipeline Project".

And whereas the copies of the Gazette were made available to the public. And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, has submitted his report of Central Government.

And whereas, the Central Government after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of the user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user of the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the

Central Government, vests on the date of publication of the declaration, in India Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

### SCHEDULE

District : West Godavari			State : Andhra Pradesh		
Name of Mandal	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jangareddigudem	Nimmalagudem	199	00	00	10
		198	00	31	14
		254	00	61	85

[F. No. R-11025(11)/252/2017-OR-I/E-21033]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2018

**का.आ. 60.—** केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 उप धारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 1069(अ) तारीख 03.04.2017 जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र संख्या 947, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (II) तारीख 06.04.2017 में किया गया है। इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट आंध्र प्रदेश राज्य के मंडल: देवरापल्ली जिला: वेस्ट गोदावरी की भूमि में, ओडीशा राज्य में पारादीप से तेलंगाना राज्य में हैदराबाद तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे “पारादीप-हैदराबाद पाइपलाइन परियोजना” के संबंध में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी:

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं। और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए:

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए सभी बिल्लिंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

### अनुसूची

जिला: वेस्ट गोदावरी			राज्य: आन्ध्रप्रदेश		
मंडल का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
देवरापल्ली	यदाबोलु	153/1	00	02	84
		153/2	00	15	33



		156	00	34	71
		157	00	08	79
		184/4	00	01	39
		184/2	00	42	37
		173/2	00	45	57
		173/3	00	02	95
		174	00	17	64
		175/2	00	11	66
		178	00	06	84
		176/2	00	44	48
		177/1	00	27	51
		107	00	46	42
		109	00	01	70
		108	00	01	61
		119/3	00	02	23
		110/2	00	17	94
		110/3	00	05	90
		119/2	00	00	39
		119/1	00	07	02
		118/8	00	16	27
		118/5B	00	00	41
		118/7C	00	07	58
		255/2A	00	00	10
		255/1D	00	02	03
		255/1A	00	02	99
		259	00	34	09
		258	00	10	25
		263	00	28	82

		60	00	03	11
		59/1	00	18	63
		59/2	00	03	54
		59/3	00	03	43
		59/4	00	03	87
		59/5	00	10	47
		475/1	00	12	64
		475/3	00	00	34
		475/2	00	03	45
		476	00	06	78
		474/5	00	10	35
		474/2	00	03	40
		474/3	00	10	76
		473	00	10	63
		472/3	00	30	80
		472/2	00	00	42
		487/2	00	16	84
		488/1	00	06	08
		488/2	00	37	55
		489/5	00	18	80
		490	00	05	54
		717/5	00	00	38
		717/4	00	04	88
		717/3	00	17	30
		717/2	00	05	86
		716/1	00	14	29
		715	00	09	73
		711	00	09	82

		713	00	12	66
		712	00	29	98
		708	00	27	63
		707	00	12	01
		706	00	13	58
		513/6	00	07	43
		513/5	00	08	64
		513/4	00	04	53
		513/3	00	04	38
		513/2	00	08	70
		513/1	00	09	71
		514	00	00	38
		518	00	45	72
		519/1	00	18	13
		520/1	00	34	99
		532/1	00	16	70
		532/3	00	12	97
		585	00	22	83
		586/2	00	16	09
		586/1	00	15	12
		587/1	00	11	40
		587/2	00	16	61
		551	00	08	72
		555	00	34	66
		556/2B	00	03	96
		556/2C	00	11	74
		556/1	00	15	23
		557/3	00	09	90
		570	00	36	96
		569	00	32	24
		568	00	26	38

[फा. सं. आर-11025(11)/252/2017-ओआर-I/ई-21033]

पवन कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 11th January, 2018

**S.O. 60.**— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, published in the Gazette of India No. 947 Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated 06.04.2017 vide S.O. Number 1069 (E) dated 03.04.2017 issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land situated in Mandal Devarapalli, District West Godavari in Andhra Pradesh State, specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of petroleum products from Paradip in the State of Odisha to Hyderabad in the State of Telangana by the Indian Oil Corporation Limited for implementing the "Paradip-Hyderabad Pipeline Project".

And whereas the copies of the Gazette were made available to the public. And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, has submitted his report of Central Government.

And whereas, the Central Government after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of the user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user of the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of the declaration, in India Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

**SCHEDULE**

District: West Godavari			State : Andhra Pradesh		
Name of Mandal	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Devarapalli	Yadavolu	153/1	00	02	84
		153/2	00	15	33
		156	00	34	71

		157	00	08	79
		184/4	00	01	39
		184/2	00	42	37
		173/2	00	45	57
		173/3	00	02	95
		174	00	17	64
		175/2	00	11	66
		178	00	06	84
		176/2	00	44	48
		177/1	00	27	51
		107	00	46	42
		109	00	01	70
		108	00	01	61
		119/3	00	02	23
		110/2	00	17	94
		110/3	00	05	90
		119/2	00	00	39
		119/1	00	07	02
		118/8	00	16	27
		118/5B	00	00	41
		118/7C	00	07	58
		255/2A	00	00	10
		255/1D	00	02	03
		255/1A	00	02	99

		259	00	34	09
		258	00	10	25
		263	00	28	82
		60	00	03	11
		59/1	00	18	63
		59/2	00	03	54
		59/3	00	03	43
		59/4	00	03	87
		59/5	00	10	47
		475/1	00	12	64
		475/3	00	00	34
		475/2	00	03	45
		476	00	06	78
		474/5	00	10	35
		474/2	00	03	40
		474/3	00	10	76
		473	00	10	63
		472/3	00	30	80
		472/2	00	00	42
		487/2	00	16	84
		488/1	00	06	08
		488/2	00	37	55
		489/5	00	18	80
		490	00	05	54

		717/5	00	00	38
		717/4	00	04	88
		717/3	00	17	30
		717/2	00	05	86
		716/1	00	14	29
		715	00	09	73
		711	00	09	82
		713	00	12	66
		712	00	29	98
		708	00	27	63
		707	00	12	01
		706	00	13	58
		513/6	00	07	43
		513/5	00	08	64
		513/4	00	04	53
		513/3	00	04	38
		513/2	00	08	70
		513/1	00	09	71
		514	00	00	38
		518	00	45	72
		519/1	00	18	13
		520/1	00	34	99
		532/1	00	16	70
		532/3	00	12	97

		585	00	22	83
		586/2	00	16	09
		586/1	00	15	12
		587/1	00	11	40
		587/2	00	16	61
		551	00	08	72
		555	00	34	66
		556/2B	00	03	96
		556/2C	00	11	74
		556/1	00	15	23
		557/3	00	09	90
		570	00	36	96
		569	00	32	24
		568	00	26	38

[F. No. R-11025(11)/252/2017-OR-I/E-21033]

PAWAN KUMAR, Under Secy.



**श्रम एवं रोजगार मंत्रालय**

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2018

**का.आ. 61.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स ओ.एन.जी.सी. लिमिटेड एवं अन्य के प्रबंधन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, अहमदाबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 11/2016) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 19.12.2017 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-30011/39/2015-आईआर (एम)]

डी. के. हिमांशु, अवर सचिव

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**

New Delhi, the 1st January, 2018

**S.O. 61.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 11/2016) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Ahmedabad now as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. O.N.G.C. Limited and other and their workman, which was received by the Central Government on 19.12.2017.

[No. L-30011/39/2015-IR (M)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

**ANNEXURE****BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,  
AHMEDABAD****Present :**

Pramod Kumar Chaturvedi,  
Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court,  
Ahmedabad,  
Dated 21<sup>st</sup> November, 2017

**Reference: (CGITA) No. 11/2016**

1. The Executive Director – Asset Manager,  
ONGC Ltd., Avani Bhavan, 5<sup>th</sup> Floor, Chandkheda,  
Ahmedabad (Gujarat)
2. The Incharge (HR - IR),  
ONGC Ltd., Avani Bhavan, 5<sup>th</sup> Floor, Chandkheda,  
Ahmedabad (Gujarat)
3. The Dy. General Manager (P) ST,  
ONGC Ltd., Avani Bhavan, 5<sup>th</sup> Floor, Chandkheda,  
Sabarmati, Ahmedabad
4. M/s D.B. Enterprises,  
G-8, Sukan Mall, Behind Vishat Petrol Pump,  
Sabarmati, Ahmedabad (Gujarat)

...First Party

**V/s**

The President,  
Glorious Petroleum Mazdoor Sangh,  
A/3, PriyaDarshini Society, Near New Railway Colony,  
Ahmedabad (Gujarat) – 380019

...Second Party

For the First Party : Shri K.V. Gadhia

For the Second Party : Shri S.N. Gandhi

### AWARD

The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-30011/39/2015-IR(M) dated 07.01.2016 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:

### SCHEDULE

“Whether the action of the management of ONGC Ltd., Ahmedabad through its contractor M/s D.B. Enterprises, Ahmedabad in discontinuing/terminating the services of two workmen Shri Mangaji J. Yadav w.e.f. 28.04.2015 without following the procedure prescribed under Section 33 of the I.D. Act, 1947 during the pendency of his claim for regularization in services of ONGC Ltd., before CGIT, Ahmedabad and Shri Pradipkumar S. Nai without following the procedure prescribed under ‘Fair Wage Settlement’ is legal, proper and justified? If not, to what relief the concerned workmen S/Shri Mangaji J. Yadav and Pradipkumar S. Nai are entitled to and what directions are necessary in the matter?”

1. The reference dates back to 07.01.2016. The second party submitted the statement of claim Ex. 2 on 21.04.2016 alleging that the second party union Glorious Petroleum Mazdoor Sangh is a registered union under the trade union act and both the concerning workmen namely Mangaji J. Yadav and Pradipkumar S. Nai were the members of the aforesaid union who were working with the first party ONGC Ltd., hereinafter referred to as ONGC through their respective contractors since more than 25 years. During the tenure of their services, there was no complaint against them regarding their work and conduct. They have also worked for more than 240 days in each and every calendar year. It has been further alleged that at the time of impugned action, they were working with the first party No. 4 M/s D.B. Enterprises, hereinafter referred to as M/s D.B. Enterprises, a labour contractor. It has been further alleged that as per the policy of ONGC whenever there any contractor is changed, list of the contract workers engaged by the previous contractor has been provided to the new contractor so that the new contractor be mandated to continue with the contract workmen of the earlier contractor. It has been further alleged that both the workmen worked for more than 25 years as unskilled and skilled operator workers respectively and lastly they have been working with the contractor namely M/s D.B. Enterprises. It has been further alleged that a criminal complaint was registered against the aforesaid workmen by the first party under the wrong and false criminal complaint wherein they have been put under suspension for 1½ months, later it was revoked by an oral order and the workmen were reinstated in their service with continuity of service and worked for more than 2½ years till 27.04.2015. Thereafter, suddenly on 28.04.2015, both the concerned workmen received a letter from M/s D.B. Enterprises informing that they are debarred w.e.f. 28.04.2015 from performing any duty in ONGC till they are proved innocent by the competent court. The second party union submitted the copy of the aforesaid letters vide Ex. 11/1 and 11/2. It has been further alleged that on 28.04.2015, workmen were also terminated from the service without giving them any opportunity to defend themselves. No departmental inquiry was also conducted. It has been further alleged that the workman Mangaji J. Yadav was a protected workman and his case was pending for regularisation in CGIT-cum-Labour Court, Ahmedabad. The said contention was admitted by the first party in their letter dated 28.04.2015 Ex. 11/3 and 22.06.2015 Ex. 11/4 submitted before the Assistant Commissioner of Labour, Central, Ahmedabad. It has been further alleged that the workman Pradeepkumar Nai was covered under Fair Wage Settlement Scheme providing job security to the contract workmen as per the provisions of the aforesaid settlement scheme. It was the pre-condition in the aforesaid settlement scheme for the management to give full opportunity to defend him and to conduct departmental inquiry into the misconduct of the workman and his services cannot be terminated unless the misconduct is proved. The copy of the settlement scheme is submitted vide Ex. 15/4. It has been further alleged that no such opportunity of defending himself and conducting departmental inquiry was done in the matter. It has been further alleged that while terminating their services, the workmen were not paid any retrenchment compensation or legal dues. Thus the impugned action was violative of Section 25 F, G and H of the I.D. Act. It has been further alleged that the workmen were subjected to Criminal Trial vid Criminal Case No. 843/2009 before the Judicial Magistrate first class, Gandhinagar who acquitted them in the said case following the charge of theft vide judgement dated 10.08.2016. The copy of the judgement is at Ex. 12/1 and 12/2.

2. The first party ONGC filed their written statement Ex. 10 on 19.12.2016 submitted that both the concerned workmen were contract workmen and their services were terminated by their contractor w.e.f. 28.04.2015 in an alleged theft case with a condition that till they are not proved innocent by the competent Magistrate, they will not be re-engaged. Thus their services were not terminated by ONGC. Therefore, no relief can be granted against the ONGC.

3. The first party No. 4 M/s D.B. Enterprises were served vide notice date 28.09.2017 but M/s D.B. Enterprises did not prefer to appear and submit the written statement. Thus the case against M/s D.B. Enterprises proceed ex-parte vide order dated 28.09.2017. Therefore, the second party who earlier submitted their affidavit Ex. 13 and 14 were taken on record. ONGC cross-examined them wherein both the workmen admitted that they used to work under a contractor named M/s D.B. Enterprises and they were not given any appointment letter and were also not served with any termination letter by ONGC.

4. Thus it is a case wherein no relief can be granted to the workmen against the ONGC.
5. M/s D.B. Enterprises despite service of notice twice vide Ex. 8 on 18.09.2016, thereafter Ex. 16 on 28.09.2017, did not prefer to submit his written statement or submissions. The documents Ex. 12/1 and 12/2 clearly establishes that both the workmen were acquitted for the charge of theft and it is noteworthy that it was the preconditions of the termination letter Ex. 11/1 and 11/2 that the workmen will not be permitted to perform duties in ONGC unless proved innocent by the Competent Magistrate and as they have been acquitted by the Competent Magistrate and M/s D.B. Enterprises has refrained to challenge the reference by submitting written statement, thus this reference can be decided ex-parte against M/s D.B. Enterprises to engage the aforesaid workmen namely Mangaji J. Yadav and Pradipkumar S. Nai with immediate effect with all their seniority and other non-monetary benefits.
6. Thus the reference is disposed of accordingly and the first party no. 4 M/s D.B. Enterprises is directed to engage/employ the workmen namely Mangaji J. Yadav and Pradipkumar S. Nai immediately as and when they report to duty as per the terms and conditions said earlier.
7. The award is passed accordingly.

P. K. CHATURVEDI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2018

**का.आ. 62.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स ओ.एन. जी.सी. लिमिटेड एवं अन्य के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, अहमदाबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 50/2012) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 19.12.2017 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-30011/10/2011-आईआर (एम)]

डी. के. हिमांशु, अवर सचिव

New Delhi, the 1st January, 2018

**S.O. 62.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 50/2012) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Ahmedabad now as shown in the Annexure, in the industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. O.N.G.C. Limited and others and their workman, which was received by the Central Government on 19.12.2017.

[No. L-30011/10/2011-IR (M)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

#### ANNEXURE

#### BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, AHMEDABAD

##### Present :

Pramod Kumar Chaturvedi,  
Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court,  
Ahmedabad,  
Dated 06<sup>th</sup> Decemberr, 2017

##### Reference: (CGITA) No. 50/2012

1. The Executive Director,  
ONGC Limited,  
Ahmedabad Asset, Avani Bhawan,  
Chandkheda, Ahmedabad
2. The Incharge (Security)  
ONGC Limited, Avani Bhawan,  
Chandkheda, Ahmedabad
3. The General Manager,  
Trig Guard Force Ltd.,  
119, Sarjan Tower, Nr. C.G Road,  
Chandkheda, Ahmedabad

4. M/s. Max Vigil Security Pvt. Ltd.,  
42, Astha Avenue, Nr. R.T.O.,  
Subhas Bridge Circle, Ahmedabad

...First Party

V/s

Shri C.K. Parmar,  
Secretary, Soshit Kamdar Sangh (Gujarat),  
521/3372, JayshriLalimaNivas,  
Ambika Nagar, Gujarat Housing Board,  
Chandkheda, Ahmedabad

...Second Party

For the First Party no's. 1 & 2 : Sh. K.V. Gadhia & Sh. M.K. Patel

For the First Party No. 3 : Absent

For the First Party No. 4 : Sh. Anil Parikh, Advocate

For the Second Party : Sh. C.K. Parmar, Party in Person

### AWARD

The Government of India/ Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L- 30011/10/2011-IR(M) dated:14.02.2012 referred the dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal Ahmedabad in respect of the matter specified in the schedule.

### SCHEDULE

"Whether the action of the contractor of ONGC Ltd., Ahmedabad M/s. Max Vigil Security Pvt. Ltd. in terminating the services of Shri C. K. Parmar (Protected under court order) on the behest of ONGC Ltd., Ahmedabad and decategorising him from Security Supervisor to Security Guard and changing his service condition without following due process of law by the management of ONGC Ltd., Ahmedabad is legal and justified? What relief the workman is entitled to?"

1. The reference dates back to 14.02.2012. After the reference by the Appropriate Government, the Court issued notices vide Ex. 2 to the respective parties and in pursuance to the same, parties to the reference appeared before the Tribunal and filed their pleadings. The second party filed the Statement of Claims Ex. 7. The ONGC has appeared through its Advocate and filed its Written Statement vide Ex. 8. The First party No. 3 has chosen not to appear and the First Party No. 4 appeared through advocate and filed Written Statement vide Ex. 12.

2. The Second party appeared as a party in person and alleged in his Statement of claim that he had been working with ONGC under various contractors continuously since 1992 and worked as Security Guard with Opp. No. 3 till 30.06.2010. It is further alleged that he had been serving as a Security Supervisor since Feb. – 2006. But he was decategorised by the F.P. No. 3 without any rhyme or reason w.e.f. 02.06.2010. It is further alleged that he was then working with F.P. No. 4 and was illegally terminated. It is also alleged that case of regularization of various workers was pending before the Ld. Tribunal and that he was a Union leader fighting with the F.P. for the rights of other employees and therefore he was decategorised despite Interim Relief granted by tribunal in their favour in the main Reference and he was subsequently terminated. Thus the second party has prayed for reinstatement on original post with continuity in service and has also prayed to declare the action of decategorising him from security supervisor to security guard as illegal and also prayed for granting the benefits of Security Supervisor from June – 2010. He has also prayed for declaring the action of the ONGC to change his service condition as illegal and unjust and further prayed for cost of litigation.

3. The First Party No. 1 & 2 ONGC has filed its Written statement vide Ex. 8 and denied the averments made in the statement of claims. The ONGC has stated in true facts that there was no relation of master and servant relationship between the first party and the second party at any point of time. The ONGC has further stated that as per the Statement of Claims itself, the second party was decategorised by F.P. No. 3 and terminated by F.P. No. 4 and hence prayed for rejection of reference qua ONGC. The ONGC has further stated that the reference is barred by principle of res-judicata as the Complaint No. 05/2011 filed by the second party for the same cause of action was dismissed. Hence it is prayed to reject the reference.

4. The First party No. 4 has also filed written statement Ex. 12 and denied the contentions raised in the Statement of Claims. As far as true facts are concerned, it is stated that the second party was working with them and was suspended on 01.07.2010 for serious misconducts and was also served with a charge sheet on 30.07.2010. It is further stated that a departmental inquiry was conducted and sufficient opportunity was given to the second party workman and inquiry officer submitted his report on 01.09.2010 giving finding that the charges were proved. The second party was then served with a second show cause notice dtd: - 03.09.2010 on the aforesaid inquiry report and on the point of

punishment but he did not reply to the said notice, therefore, he was dismissed from service w.e.f. 01.10.2010. Thus in view of the same, the F.P. No. 3 has prayed for rejection of reference.

5. The Second party examined himself in the matter and was also cross examined by first party no. 1, 2 & 4. The first party No. 4 has also examined his witness Mr. Santosh Mojiram Sharma in the matter who was cross examined by second party and all the first parties. The F.P. No. 4 has produced a list of documents including inquiry report. On the other hand the second party also filed number of documents in the matter. During the course of proceedings, the second party has also given various applications/affidavits and also brought on record the previous litigation between the parties and the orders thereof. The Second party and F.P. No. 4 have given written arguments in the matter while the Ld. Advocate for the F.P. Nos. 1 & 2 have made oral submissions in the matter.

6. Considering the materials and evidences on record, the submissions of the parties and the terms of reference as formed by the appropriate government, the issues that fall for consideration are:

- I. Whether the termination of the Second Party by the Contractor M/s. Max Vigil Security Pvt. Ltd. is legal and justified?
- II. Whether the action of ONGC in decategorising the second party from Security Supervisor to Security guard is legal and justified?
- III. If not, what relief the second party is entitled to?

#### 6.1 **Issue I**

The burden of proof of this issues lies on second party, workman. From the terms of reference, the pleadings of the second party in the statement of claims and thereafter as well as pleadings of the ONGC and the contractor, one thing that is clear is that the second party was working with the F.P. No. – 4 herein. Hence, there was a relation of master and servant between the second party and the F.P. No.4. Secondly, the fact that the second party is terminated is also an admitted fact. What is required to be determined here is whether, the said termination is just and legal. In this connection, the second party has stated that he was terminated on 01.07.2010 without following the due process of law. As against this, the witness of F.P. No. 4 Mr. Santosh Mojiram Sharma stated that he was suspended on 01.07.2010 and terminated on 01.10.2010 after a departmental inquiry. The second party has appeared as a party in person and has not taken assistance of any legal counsel in the matter. The F.P. No. 4 has also produced the inquiry proceedings on record to support its case. However, what is borne out from the record is that the F.P. No. 4 has not paid suspension/subsistence allowance to the second party during the pendency of the inquiry. Moreover, the inquiry was for most of the time conducted in absence of the second party. The list of witnesses relied upon by the management was also not provided to the second party. Moreover, the first date of inquiry was kept on 13.08.2010 for which notice was issued on 09.08.2010. The second party on that day gave an application for change in venue of the proceedings. Now this Tribunal cannot decide the venue of the proceedings as it is the discretion of the management alone. However, without deciding the same, the inquiry officer in no time fixed another date of the proceedings at the same place on 18.08.2010. The Second party again did not remain present. On that day, the witnesses of the management were examined. The proceedings are then postponed to 27.08.2010. The second party again chose not to remain present and therefore the inquiry proceeding was concluded on the said date. The Inquiry officer has then on 01.09.2010 submitted inquiry report. Subsequent thereto on 03.09.2010 itself, the management has given a second show cause notice to the second party and directed him to reply to the same within 72 hours on why he should not be dismissed failing which management will take proposed action against him. Thus it is clear from the above dates and proceedings that the inquiry was conducted in a hasty manner and decision of dismissal was also taken in haste. This Tribunal is aware of the fact that the charges are serious in nature wherein the second party has not only abused a superior but also damaged Government property and left without any permission or authorization. However, the principles of natural justice demand that the delinquent be given sufficient opportunity to disprove the charges and prove his innocence. The management has already framed the charges and communicated the same on 30.07.2010 to the second party. The same was not replied by the second party and hence inquiry proceedings were initiated. Thus, this Tribunal is of the opinion that the Second party may be given a chance to reply to the charge sheet and the management may then take a decision on whether to initiate inquiry or not. If the management decides to initiate the inquiry then the second party may be given reasonable opportunity to defend himself. The management may provide the list of witnesses and documents that may be relied upon before hand to the second party and the same is expected from the second party. On conclusion of the inquiry proceedings, reasonable time may be granted to both the sides to submit their briefs and then again to counter the findings of the inquiry officer and further notice, if any. In nut shell, the entire process from the point of reply to the charge sheet is required to be done afresh. Considering the peculiar facts of the case, as well as the fact that the second party appeared as party-in-person and also considering the fact that the first inquiry was conducted virtually in ex-parte manner against the second party workman.

The apex court in Brijbihari Singh V/s Bihar State Financial Corporation, 216(1) CLR 344, held that it is a well settled principle of law where a person/employee was required to answer charges labeled against him should know not only the acquisition against him but also the testimony of the witnesses by which the charges were alleged to be proved. The departure from the aforesaid requirements of principles of law definitely violates the principles of natural justice and therefore, the inquiry held against the delinquent employee is vitiated.

Thus it will be in fitness of things, if the said exercise is carried out in house as far as the present issue is concerned. It is needless to clarify here that any order passed will be subject to rights of the parties to challenge it before the appropriate forum. If the management sticks to its earlier decision, then the question of intervening period will not be of much consequence. However, if the relief is granted, then the disciplinary authority may modify the punishment accordingly.

## 6.2 **Issue II**

As far as the present issue is concerned, from the statement of claims itself, it is clear that the second party was earlier working with the F.P. No. 3 and he was decategorised from security supervisor to security guard by the said party. Moreover, the ONGC has also contended that the second party was never appointed by them. The terms of reference are that whether the action of the ONGC in decategorising the second party is just and legal or not. However, from the pleadings of the second party himself, it is clear that he was decategorised by F.P. No. 3 and not ONGC. Moreover, the Tribunal cannot traverse beyond the terms of reference. Thus no relief can be granted to the second party against ONGC in the present issue.

7. In view of the above, the matter is sent back to the Disciplinary Authority to proceed fresh inquiry and pass a reasoned order after giving full opportunity of hearing to the workman as held by the Hon'ble Apex Court in case of Brij Bihar Singh Vs. Bihar State financial Corporation & Ors. reported in 2016 I CLR 344.

8. The F.P. No. 4 will also be required to pay subsistence allowance from the date of commence of fresh departmental proceedings to till the date of final order if any, to be passed by the F.P. No. 4. Thus the reference is disposed off with above observations.

P. K. CHATURVEDI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2018

**का.आ. 63.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स ओ.एन. जी.सी. लिमिटेड एवं अन्य के प्रबंधन के संबंधित नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, अहमदाबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 67/2010) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 19.12.2017 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-30011/8/2009-आईआर (एम)]

डी. के. हिमांशु, अवर सचिव

New Delhi, the 1st January, 2018

**S.O. 63.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 67/2010) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Ahmedabad now as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. O.N.G.C. Limited and other and their workman, which was received by the Central Government on 19.12.2017.

[No. L-30011/8/2009-IR (M)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

## ANNEXURE

### BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, AHMEDABAD

#### Present :

Pramod Kumar Chaturvedi,  
Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court,  
Ahmedabad,  
Dated 20<sup>th</sup> November, 2017

**Reference: (CGITA) No. 67/2010**

1. The Asset Manager,  
ONGC Ltd., Ankleshwar Asset,  
Ankleshwar (Gujarat)
2. The Chief Manager (Security),  
ONGC Ltd.,  
Ankleshwar
3. M/s Tops Security Ltd.,  
C-I, Hariom Shopping, Nr. Overbridge,  
Opp. Jublee Guest House, Old National Highway,  
Ankleshwar

...First Party

V/s

The General Secretary,  
ONG Mazdoor Sangh, ONGC Office,  
Ankleshwar (Gujarat)

...Second Party

For the First Party : Shri C.S. Naidu

For the Second Party : Shri A.N. Patel

**AWARD**

The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-30011/8/2009-IR(M) dated 29.07.2009 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:

**SCHEDULE**

“The Security Section of ONGC is a “registered establishment” under the Contract Labour (R&A) Act, 1970 and the Contractor had obtained prescribed Labour License under the Act. Hence the dispute raised is not maintainable.”

1. The reference dates back to 29.07.2009. The second party submitted the statement of claim Ex. 8 on 03.04.2010 and the first party submitted the written statement Ex. 16 on 21.04.2010 along with vakalatpatra Ex. 17 of his advocate.
2. Since then the second party union did not lead evidence; however on 05.11.2015, The General Secretary, R.H. Pathan ONG Mazdoor Sangh moved an application Ex. 33 for withdrawal from the reference of 165 workmen named in the application.
3. Since then the second party union has been absent and has not been leading evidence.
4. Thus it appears that the second party union is not willing to prosecute and pursue the matter. Thus the reference is disposed of in the absence of the evidence of the second party workman.

P. K. CHATURVEDI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2018

**का.आ. 64.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स टाटा केमिकल्स लिमिटेड के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, अहमदाबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 101/2010) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 19.12.2017 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-29012/82/2008-आईआर (एम)]

डी. के. हिमांशु, अवर सचिव

New Delhi, the 1st January, 2018

**S.O. 64.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 101/2010) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Ahmedabad now as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Tata Chemicals Limited and their workman, which was received by the Central Government on 19.12.2017.

[No. L-29012/82/2008-IR (M)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

**ANNEXURE****BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,  
AHMEDABAD****Present :**

Pramod Kumar Chaturvedi,  
Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court,  
Ahmedabad,  
Dated 23<sup>rd</sup> November, 2017

**Reference: (CGITA) No. 101/2010**

The Manager,  
Tata Chemicals Limited,  
Ranavav Quarry Office, Ranavav,  
Porbandar (Gujarat)

...First Party

**V/s**

Shri Laxman Devshi Bhuva,  
Navapara, Adityana,  
Ranavav,  
Porbandar (Gujarat)

...Second Party

For the First Party : Shri P.S. Gogia

For the Second Party : Shri Ramsingh Thakor

**AWARD**

The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-29012/82/2008-IR(M) dated 16.09.2008 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:

**SCHEDULE**

“Whether the action of the Manager (Mines)/Mine Agent of M/s Tata Chemicals Limited, Ranavav in not providing employment to Shri Laxman Devshi Bhuva, Ex-workman after 01.10.2006 and whether his termination is legal and justified? What relief the workman is entitled to?”

1. The reference dates back to 16.09.2008. Both the parties submitted and exchanged their statement of claim and written statement along with relevant documents. The reference was fixed for evidence of the second party but today on 23.11.2017, both the parties jointly submitted a settlement Ex. 15 stating that the first party has agreed to pay Rs.1278000/- to the workman subject to deduction of taxes. It has also been said that the payment has been made to the workman. The settlement was read over to the parties and the parties verified the settlement of the award.
2. Thus the reference is finally disposed of in terms of the settlement Ex. 15. The settlement Ex. 15 shall be part of the award.
3. The award is passed accordingly.

P. K. CHATURVEDI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2018

**का.आ. 65.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स टाटा केमिकल्स लिमिटेड के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, अहमदाबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 105/2010) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 19.12.2017 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-29012/81/2008-आईआर (एम)]

डी. के. हिमांशु, अवर सचिव



New Delhi, the 1st January, 2018

**S.O. 65.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 105/2010) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Ahmedabad now as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Tata Chemicals Limited and their workman, which was received by the Central Government on 19.12.2017.

[No. L-29012/81/2008-IR (M)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

**ANNEXURE****BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,  
AHMEDABAD****Present :**

Pramod Kumar Chaturvedi,  
Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court,  
Ahmedabad,  
Dated 23<sup>rd</sup> November, 2017

**Reference: (CGITA) No. 105/2010**

The Manager,  
Tata Chemicals Limited,  
Ranavav Quarry Office, Ranavav,  
Porbandar (Gujarat)

...First Party

**V/s**

Shri Mohan Kana Borichiya,  
Ganesh Oil Centre, Opp. Post Office Station Plot,  
Ranavav -2,  
Porbandar (Gujarat)

...Second Party

For the First Party : Shri P.S. Gogia

For the Second Party : Shri RamsinghThakor

**AWARD**

The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-29012/81/2008-IR(M) dated 16.09.2008 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:

**SCHEDULE**

“Whether the action of the Manager (Mines)/Mine Agent of M/s Tata Chemicals Limited, Ranavav in not providing employment to Shri Mohan Kana Borichiya, Ex-workman after 01.10.2006 and whether his termination is legal and justified? What relief the workman is entitled to?”

1. The reference dates back to 16.09.2008. Both the parties submitted and exchanged their statement of claim and written statement along with relevant documents. The reference was fixed for evidence of the second party but today on 23.11.2017, both the parties jointly submitted a settlement Ex. 16 stating that the first party has agreed to pay Rs.1278000/- to the workman subject to deduction of taxes. It has also been said that the payment has been made to the workman. The settlement was read over to the parties and the parties verified the settlement of the award.
2. Thus the reference is finally disposed of in terms of the settlement Ex. 16. The settlement Ex. 16 shall be part of the award.
3. The award is passed accordingly.

P. K. CHATURVEDI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2018

**का.आ. 66.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स टाटा केमिकल्स लिमिटेड के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार

औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, अहमदाबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 113/2010) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 19.12.2017 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-29012/80/2008-आईआर (एम)]

डी. के. हिमांशु, अवर सचिव

New Delhi, the 1st January, 2018

**S.O. 66.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 113/2010) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Ahmedabad now as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Tata Chemicals Limited and their workman, which was received by the Central Government on 19.12.2017.

[No. L-29012/80/2008-IR (M)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

#### ANNEXURE

#### BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, AHMEDABAD

##### Present :

Pramod Kumar Chaturvedi,  
Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court,  
Ahmedabad,  
Dated 23<sup>rd</sup> November, 2017

##### Reference: (CGITA) No. 113/2010

The Manager,  
Tata Chemicals Limited,  
Ranavav Quarry Office, Ranavav,  
Porbandar (Gujarat)

...First Party

##### V/s

Shri Ali Suleman Ghavda,  
Behind Patel Samaj,  
Adityana, Ranavav,  
Porbandar (Gujarat)

...Second Party

For the First Party : Shri P.S. Gogia

For the Second Party : Shri Ramsingh Thakor

#### AWARD

The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-29012/80/2008-IR(M) dated 16.09.2008 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:

#### SCHEDULE

“Whether the action of the Manager (Mines)/Mine Agent of M/s Tata Chemicals Limited, Ranavav in not providing employment to Shri Ali Suleman Ghavda, Ex-workman after 01.10.2006 and whether his termination is legal and justified? What relief the workman is entitled to?”

1. The reference dates back to 16.09.2008. Both the parties submitted and exchanged their statement of claim and written statement along with relevant documents. The reference was fixed for evidence of the second party but today on 23.11.2017, both the parties jointly submitted a settlement Ex. 16 stating that the first party has agreed to pay Rs.1278000/- to the workman subject to deduction of taxes. It has also been said that the payment has been made to the workman. The settlement was read over to the parties and the parties verified the settlement of the award.
2. Thus the reference is finally disposed of in terms of the settlement Ex. 16. The settlement Ex. 16 shall be part of the award.
3. The award is passed accordingly.

P. K. CHATURVEDI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2018

**का.आ. 67.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स डी.बी.सी. सन्स (गुजरात) प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, अहमदाबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 531/2004) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 19.12.2017 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-37011/17/2002-आईआर (एम)]

डी. के. हिमांशु, अवर सचिव

New Delhi, the 1st January, 2018

**S.O. 67.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 531/2004) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Ahmedabad now as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. D.B.C. Sons (Guj.) Pvt. Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 19.12.2017.

[No. L-37011/17/2002-IR (M)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

**ANNEXURE****BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,  
AHMEDABAD****Present :**

Pramod Kumar Chaturvedi,  
Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court,  
Ahmedabad,  
Dated 21<sup>st</sup> November, 2017

**Reference: (CGITA) No. 531/2004**

The Managing Director,  
M/s Darabshaw B. Cursetjee Sons (Bom) Pvt. Ltd.,  
Darabshaw House, Ballard Pier,  
Mumbai – 400010

...First Party

**V/s**

Shri N.K. Sharma,  
S.D.X. – 50, Kutch,  
Gandhidham (Gujarat) – 370201

...Second Party

For the First Party : Shri L.M. Patil

For the Second Party : Shri D.C. Gandhi

**AWARD**

The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-37011/17/2002-IR(M) dated 10.12.2002 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:

**SCHEDULE**

“Whether the action of the management of M/s D.B.C.’s Sons (Guj.) Pvt. Ltd., Mumbai not to allow on duty after transfer either at Kakinada or at Kandla presuming that he was left the service on his own is justified or legal? If not, what relief the workman is entitled for and since when?”

1. The reference dates back to 10.12.2002. After issuing notice to both the parties, neither of the parties appeared, therefore, Industrial Tribunal, Gujarat vide order dated 10.01.2005 dismissed the reference for non-appearance of the parties.
2. Thereafter, the second party workman moved a Misc. Application No. 07/2009 after a period of 2 years for restoration of the reference and the Industrial Tribunal, Gujarat restored the reference to its original no. for adjudication and issued the notice to the first party which was received by the first party on 13.09.2012.
3. The second party workman submitted the statement of claim Ex. 13 on 23.08.2012 alleging that he was appointed as a temporary employee on the post of Dock Assistant by the first party The Managing Director, M/s Darabshaw B. Cursetjee Sons (Bom) Pvt. Ltd., Darabshaw House, Ballard Pier, Mumbai, hereinafter referred to as first party vide order dated 30.04.1985 for a period of 6 months' probation w.e.f. 01.05.1985 with a monthly salary of Rs.450/- and he was made permanent vide order dated 29.03.1986 w.e.f. 01.04.1986 with a total salary of Rs.5500/- in the grade of permanent service. He served his duties with honesty and diligence at first party office as Gandhidham. During his whole service, he was not showed any show-cause notice, memo, rebuke or charge-sheet. On account of his good and honest service, he was giving 3 special increments with a commendation certificate. Suddenly on 21.06.2001, he was transferred Gandhidham Gujarat to Kakinada Andhra Pradesh. He apprised the first party by way of serving a letter regarding his financial, social conditions and also problems of minor child and wife's illness being suffering with kidney ailment but the first party did not consider his case of change of transfer, therefore, he booked a railway ticket on 08.08.2001 to be present at Kakinada. After reaching Kakinada, he was not permitted to join, so he informed the Labour Commissioner at Kakinada regarding this but those officers did not take cognizance into the matter. He was not subjected to any departmental inquiry and suddenly his services were terminated for not joining at the transfer place. While terminating his services, he was not given any show-cause notice, retrenchment compensation. Thus the action was violative of the provisions of Section 25 F, G and H of the I.D. Act. Thus he has prayed for declaring the termination order as illegal, reinstatement of service along with service benefits with legal expenses of Rs. 10000/-.
4. The first party in his written statement Ex. 15 filed on 18.10.2012 admitted the service appointment of second party workman on probation, thereafter, as a permanent employee but further submitted that the first party did not terminate the services of the second party workman and as per the transfer orders issued by the first party; he was transferred from Gandhidham to Kakinada. He reported to duty at transferred place and thereafter, all of a sudden, he refused to work at the transferred place and started to send representations mentioning seek reports and his wife's ailment. He has also submitted that this tribunal has no jurisdiction to entertain the reference on the ground that the initial appointment letter as a probationer as well as a permanent employee issued to the workman clearly indicated that transfer will be the condition of his service and after making his transfer to Kakinada, the workman admitted that he resume duty at Kakinada and thereafter, he stopped working there. Thus the jurisdiction lies in the Central Government Industrial Tribunal situated in Andhra Pradesh. It has been further submitted that the entire reference is misconceived, legally not tenable as transferring a workman/employee which was a service condition in the appointment letter, cannot also be entertained as an Industrial Dispute.
5. On the basis of the pleadings, the following issues arise:
  - i. Whether the action of the management of M/s D.B.C.'s Sons (Guj.) Pvt. Ltd., Mumbai not to allow on duty after transfer either at Kakinada or at Kandla presuming that he was left the service on his own is justified or legal?
  - ii. To what relief, if any, the workman is entitled for and since when?
6. As both the issues are interconnected, therefore both these issues are discussed and decided together.
7. Issue no. (i & ii): The burden to prove this issue was lying on the second party workman and the second party workman in his affidavit Ex. 16 filed on 28.11.2013 and in his cross-examination, he has admitted that his date of birth is 17.12.1949 with a matric qualification and also admitted that he was transferred to Kakinada vide order dated 20.06.2001, he reached Kakinada after staying for 10 to 15 days at Gandhidham requesting for cancellation of transfer. He further admitted in his cross-examination that he stayed in Kakinada for a month and came back to Gandhidham. Thereafter, he did not turn up at Kakinada.
8. The first party examined Baltazar Fernandez, Senior Manager, vide affidavit Ex. 19 who reiterated the averments made in the written statement and stated in his cross-examination which is as under:

"I have been working as Senior Manager, Finance and Accounts since last 25 years. I am aware of all the facts relating to this case. The workman N.K. Sharma has been a regular employee of first party. The workman was Dock Assistant in the first party organisation. We used to transfer the workman from one branch to another branch of the organisation. Our office is based at Kandla Port. It is true that since joining the workman

continued his service at Kandla Port Branch of first party organisation. The workman was transferred on 21.06.2001 from Kandla Branch to Kakinada Branch of the first party organisation. He was relieved with immediate effect.

The workman moved a representation for cancellation of his transfer order on the ground that his wife was well and long sick. The representation was annexed with the medical certificate regarding Kidney disease.

The workman despite representation for cancellation of transfer, joined at Kakinada on 08.08.2001. But we did not permit him to join and also did not initiate any disciplinary proceeding against the workman for not joining with in time provided in the transfer order.

No action was taken against the officer who has not permitted the workman to join at Kakinada despite the fact that the workman's wife was suffering with Kidney disease.

It is true that the workman moved number of complaints to Collector of the District and other higher authorities regarding denying him to join at Kakinada. It is true that the workman is stayed at Kakinada for 15 days but even then he was not permitted to join. No termination order was served on him. No notice or notice pay was given to the workman. The superannuation age in the first party organisation is 58 years, till date no service or legal dues are paid to him."

9. From the evidence of both the parties, it can be concluded that the service of the workman was transferrable and he was transferred as per the terms and condition of the service despite the admitted fact that his wife was suffering with renal ailment. Workman joined at Kakinada, therefore, it cannot be disputed that the jurisdiction in this dispute was lying in the State of Andhra Pradesh, therefore, in the Central Government Industrial Tribunal situated in the state of Andhra Pradesh. But the case of the workman appears to be inhumane on the part of the first party that despite the renal ailment of the workman's wife, he was deliberately transferred to Kakinada which is against the labour practice and inhumane. Thus transferred made out of a vengeance can be said to be an Industrial Dispute which existed at Gandhidham in Gujarat. It is also noteworthy that the first party witness has admitted that no legal dues or benefits have been paid to him.

10. Therefore, in the light of the aforesaid discussions, it can be said that the jurisdiction lies at both the places that is Gandhidham as well as Kakinada because the workman was transferred out of vengeance without considering the real ailment of the workman's wife but as admitted by the workman that he was born on 17.12.1949, therefore, passed the superannuation age, therefore, he cannot be ordered to be reinstated and he can also not be paid arrears of wages for the period of absence on the principle of 'no work no pay'.

11. Thus both the issues (i & ii) are decided with a direction that the second party workman shall be paid a lump-sum of Rs. 40000/- as compensation along with Rs. 10000/- as legal expenses.

12. The award is passed accordingly.

P. K. CHATURVEDI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2018

**का.आ. 68.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मेसर्स ओ.एन. जी.सी. लिमिटेड एवं अन्य के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, अहमदाबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 734/2004) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 19.12.2017 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-30011/67/2001-आईआर (एम)]

डी. के. हिमांशु, अवर सचिव

New Delhi, the 1st January, 2018

**S.O. 68.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 734/2004) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Ahmedabad now as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. O.N.G.C. Limited and other and their workman, which was received by the Central Government on 19.12.2017.

[No. L-30011/67/2001-IR (M)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

**ANNEXURE**  
**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,**  
**AHMEDABAD**

**Present :**

Pramod Kumar Chaturvedi,  
 Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court,  
 Ahmedabad,  
 Dated 28<sup>th</sup> November, 2017

**Reference: (CGITA) No. 734/2004**

1. The Group General Manager (Project),  
 ONGC Ltd., Ankleshwar Project,  
 Ankleshwar (Gujarat) – 393010
2. M/s Yasodeep and Company,  
 F-32, Raviraj Complex, Nr. Valia Chokdi,  
 Bharuch (Gujarat) – 393010

...First Party

**V/s**

The General Secretary,  
 ONG Mazdoor Sangh C/o Bhartiya Mazdoor Sangh,  
 Nr. Asian Paint Chokdi, GIDC,  
 Ankleshwar (Gujarat)

...Second Party

For the First Party : Shri C.S. Naidu

For the Second Party : Shri Amrish Patel

**AWARD**

The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-30011/67/2001-IR(M) dated 04.07.2001 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:

**SCHEDULE**

“Whether the demand of the union to absorb/regularize the services of Shri Raj Yogendra Sinh Balwant Sinh & 13 others as permanent and direct employee of ONGC Ltd., Ankleshwar from the date of their entry in the service as contractual workmen and all other benefits as enjoyed as the regular employees of the ONGC Ltd., is legal, proper and justified? If so, to what relief the concerned workmen are entitled to and from which date and what other directions are necessary in the matter?”

1. The reference dates back to 04.07.2001. The second party submitted the statement of claim Ex. 7 on 15.02.2002 and the first party submitted the written statement Ex. 14 on 05.05.2002. The workmen namely Mohd Rafik Hussain Shaikh and Mohd Rafik Bdul Karim Shaikh vide Ex. 53 on 11.01.2016 and the workmen namely Raj Yogendrasinh Balvantsinh, Patel Narsangbhai Bhikhabhai, Chasatiya Sandipsinh Prabhatsinh and Vasava Naginbhai Parsottambhai vide Ex. 55 on 30.06.2016, requested to withdraw from the reference by deleting their names. The said applications were allowed. Since then the remaining workmen or the union has been absent and have not been leading evidence. Thus it appears that the remaining workmen or the union are not willing to prosecute the reference.
2. Thus the reference in the absence of the evidence of the second party, is disposed of with the observation as under: “the demand of the union to absorb/regularize the services of remaining 8 workmen as permanent and direct employee of ONGC Ltd., Ankleshwar from the date of their entry in the service as contractual workmen and all other benefits as enjoyed as the regular employees of the ONGC Ltd., is illegal, improper and unjustified.”

P. K. CHATURVEDI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2018

**का.आ. 69.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स ओ.एन. जी.सी. लिमिटेड के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार

औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, अहमदाबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 767/2004) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 19.12.2017 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-30011/57/2001-आईआर (एम)]

डी. के. हिमांशु, अवर सचिव

New Delhi, the 1st January, 2018

**S.O. 69.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 767/2004) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Ahmedabad now as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. O.N.G.C. Limited and their workman, which was received by the Central Government on 19.12.2017.

[No. L-30011/57/2001-IR (M)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

### ANNEXURE

#### BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, AHMEDABAD

#### Present :

Pramod Kumar Chaturvedi,  
Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court,  
Ahmedabad,  
Dated 28<sup>th</sup> November, 2017

#### Reference: (CGITA) No. 767/2004

The Group General Manager (Project),  
ONGC Ltd., Ankleshwar Project,  
Ankleshwar(Gujarat) – 393010

...First Party

#### V/s

The President,  
All Gujarat State Kamdar Union,  
Khadki Faliya, At Vav, Post Kadodara, Taluka Vagra,  
Bharuch (Gujarat)

...Second Party

For the First Party : Shri C.S. Naidu

For the Second Party : Shri Amrish Patel

### AWARD

The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-30011/57/2001-IR(M) dated 13.11.2001 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:

### SCHEDULE

“Whether the action of the management of ONGC Ltd., Ankleshwar Project, Ankleshwar in not considering the demand of Shri Gohil Bharatbhai G. and 30 other workmen for absorption and regularisation is justified? If not, to what relief the concerned workman is entitled?”

1. The reference dates back to 13.11.2001. The second party submitted the statement of claim Ex. 5 on 21.04.2004 and the first party submitted the written statement Ex. 17 on 03.10.2017. The workmen namely Rameshbhai Bheemsang Patel, Chatsangbhai Ranchodbhai Patel, Fuljibhai Bahecharbhai Limbachia, Ganpat MahijiJadav, Ashokbhai N. Solanki and Gohil Vinubhai Ranchhodbhai, vide Ex. 9 on 28.03.2016, the workman Suleman Umerji Patel vide Ex. 12 on 21.06.2016 and the workman Ismail Vali Patel vide Ex. 15 on 29.06.2016, requested to withdraw from the reference by deleting their names. The said applications were allowed. Since then the remaining workmen or the union has been absent and have not been leading evidence. Thus it appears that the remaining workmen or the union are not willing to prosecute the reference.

2. Thus the reference in the absence of the evidence of the second party, is disposed of with the observation as under: “the action of the management of ONGC Ltd., Ankleshwar Project, Ankleshwar in not considering the demand of Shri Gohil Bharatbhai G. and remaining 22 other workmen for absorption and regularisation is justified.”

P. K. CHATURVEDI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2018

**का.आ. 70.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मेसर्स गुजरात अम्बुजा सीमेंट लिमिटेड के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, अहमदाबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 1004/2004) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 19.12.2017 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-29012/51/1994-आईआर (एम)]

डी. के. हिमांशु, अवर सचिव

New Delhi, the 1st January, 2018

**S.O. 70.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 1004/2004) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Ahmedabad now as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Gujarat Ambuja Cement Limited and their workman, which was received by the Central Government on 19.12.2017.

[No. L-29012/51/1994-IR (M)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

#### ANNEXURE

#### BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, AHMEDABAD

##### Present :

Pramod Kumar Chaturvedi,  
Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court,  
Ahmedabad,  
Dated 21<sup>st</sup> November, 2017

##### Reference: (CGITA) No. 1004/2004

The Dy. Manager (Personnel),  
M/s Gujarat Ambuja Cements Ltd.,  
Ambujanagar, P.O. Kodinar,  
Amreli – 362720

...First Party

##### V/s

Shri B.N. Khan,  
C/o Bhartiya Mazdoor Sangh,  
Gayatri Rajaputpara Main Road,  
Lodhwad Police Station,  
Rajkot (Gujarat) -360001

...Second Party

For the First Party : Shri A.S. Parikh

For the Second Party : None

#### AWARD

The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-29012/51/94-IR(M) dated 27.03.1996 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:

#### SCHEDULE

“Whether the action of the management of M/s Gujarat Ambuja Cements Ltd. in terminating the services of Shri B.N. Khan is justified? If not, to what relief the workman is entitled?”



1. The reference dates back to 27.03.1996. The second party submitted the statement of claim Ex. 4 on 15.02.1997 and the first party submitted the written statement Ex. 5 on 08.12.1997. Since then the second party has not leading evidence, therefore, on 21.03.2011, fresh notice was issued to both the parties to lead evidence but the second party neither appeared nor lead his evidence, however, the advocate of the second party appeared and submitted the vakalatpatra Ex. 13 on 27.01.2012.
2. Thus it appears that the second party workman is not willing to prosecute and pursue the matter.
3. Thus the reference is disposed of in the absence of the evidence of the second party workman with the observation as under: “the action of the management of M/s Gujarat Ambuja Cements Ltd. in terminating the services of Shri B.N. Khan is justified.”

P. K. CHATURVEDI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2018

**का.आ. 71.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मेसर्स गुजरात सीधी सीमेन्ट लिमिटेड एवं अन्य के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, अहमदाबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 1134/2004) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 19.12.2017 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-29011/9/1998-आईआर (एम)]

डी. के. हिमांशु, अवर सचिव

New Delhi, the 1st January, 2018

**S.O. 71.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 1134/2004) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Ahmedabad now as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Gujarat Sidhee Cement Ltd. and others and their workman, which was received by the Central Government on 19.12.2017.

[No. L-29011/9/1998-IR (M)]

D. K. HIMANSHU, Under Secy.

#### ANNEXURE

#### BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, AHMEDABAD

##### Present :

Pramod Kumar Chaturvedi,  
Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court,  
Ahmedabad,  
Dated 30<sup>th</sup> November, 2017

##### Reference: (CGITA) No. 1134/2004

1. The Director (Works),  
Gujarat Sidhee Cements Ltd.,  
Veraval Kodinar Highway, Sidheeagram, Veraval,  
Junagadh (Gujarat) – 362276
2. M/s Kavita Constructions Pvt. Ltd.,  
Deevanodi Naharmagra, Udaipur
3. M/s A.M. Enterprises,  
C/o Gujarat Sidhee Cements Ltd.,  
Sidhi Gram, Junagadh (Gujarat)

...First Party

V/s

The Secretary,  
Shree Junagadh Jilla Mazdoor Sangh,  
Ridhi Sidhi Apartment, Office No. 6/7, 2<sup>nd</sup> Floor,  
Veraval (Gujarat)

...Second Party

For the First Party : Shri P.S. Gogia

For the Second Party : Shri L.M. Patil

**AWARD**

The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-29011/9/98-IR(M) dated 29.06.1998 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:

**SCHEDULE**

“Whether the action of the management of M/s Gujarat Sidhee Cements Ltd., and Contractor M/s A.M. Enterprises in terminating the service of 104 employees working in packing plant w.e.f. 12.12.1997 is justified? If not, to what relief these workmen are entitled to?”

1. The reference dates back to 29.06.1998. Both the parties submitted their statement of claim and written statement as the case may be. But on 30.11.2017, both the parties submitted the settlement Ex. 23 for withdrawing the reference unconditionally.
2. Thus the reference is disposed of as withdrawn.

P. K. CHATURVEDI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2018

**का.आ. 72.**—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91-क के साथ पठित धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भिलाई स्टील प्लांट, सेल के कारखानों/स्थापनाओं के नियमित कर्मचारियों को इस अधिनियम के प्रवर्तन से छूट प्रदान करती है। यह छूट, यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगी।

2. उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है; अर्थात्:-

- (1) पूर्वोक्त स्थापना जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं, एक रजिस्टर रखेगी, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदनाम दिखाये जायेंगे;
- (2) इस छूट के होते हुए भी, कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे जिनको पाने के लिए वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व संदत्त अंशदानों के आधार पर हकदार हो जाते हैं;
- (3) छूट प्राप्त अवधि के लिए, यदि कोई अभिदाय पहले ही किए जा चुके हों, तो वे वापस नहीं किए जाएंगे;
- (4) उक्त कारखाने/स्थापना का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने/स्थापना पर उक्त अधिनियम (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है) प्रवर्तमान था ऐसी विवरणियां, ऐसे प्रारूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी अपेक्षित होती थीं;
- (5) निगम द्वारा उक्त कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 45 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी;
  - (i) धारा 44 की उप-धारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरण की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ; अथवा
  - (ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथाअपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गये थे या नहीं; या
  - (iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दिये गए उन फायदों को, जिसके फलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं; या

- (iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबंधों का अनुपालन किया गया था या नहीं, निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा:-
- (क) प्रधान या आसन्न नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है ; अथवा
- (ख) ऐसे प्रधान या आसन्न नियोजक के अधिभोगाधीन, किसी कारखाने, स्थापना, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसे लेखा, बहियां और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दें या ऐसी जानकारी दें जिसे वे आवश्यक समझते हैं; या
- (ग) प्रधान या आसन्न नियोजक की, उसके अभिकर्ता या सेवक की, या ऐसे किसी व्यक्ति को, जो ऐसे कारखाने, स्थापना, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या
- (घ) ऐसे कारखाने, स्थापना, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखा, बही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उद्धरण लेना;
- (ङ) यथानिर्धारित अन्य शक्तियों का प्रयोग करना ।
- (6) विनिवेश/निगमीकरण के मामले में, प्रदत्त छूट स्वतः रद्द हो जाएगी और तब नए प्रतिष्ठान को छूट हेतु समुचित सरकार की अनुमति लेनी होगी।

[सं. एस-38014/07/2013-एस.एस.-I]

एस. के. सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd January, 2018

**S.O. 72.**—In exercise of the power conferred by Section 88 read with Section 91-A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby exempts the regular employees/trainees of factories/establishments of **Bhilai Steel Plant of SAIL** from the operation of the said Act. The exemption shall be effective for a period of one year from the date of issue of notification.

2. The above exemption is subject to the following conditions namely:-

- (1) The aforesaid establishments wherein the employees are employed shall maintain a register showing the name and designations of the exempted employees';
- (2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates;
- (3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refundable;
- (4) The employer of the said factory/establishment shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred as the said period), such returns in such forms and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;
- (5) Any Social Security Officer appointed by the Corporation under Sub-Section (1) of Section 45 of the said ESI Act or other official of the Corporation authorized in this behalf by it, shall, for the purpose of :-
  - (i) Verifying the particulars contained in any returned submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or
  - (ii) Ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or
  - (iii) Ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

- (iv) Ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory to be empowered to:
  - (a) require the principal or immediate employer to him such information as he may consider necessary for the purpose of this Act; or
  - (b) at any reasonable time enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found in charge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine accounts, books and other documents relating to the employment of personal and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or
  - (c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or
  - (d) make copies of or take extracts from any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises,
  - (e) exercise such other powers as may be prescribed.
- (6) In case of disinvestment/corporatization, the exemption granted shall become automatically cancelled and then the new entity will have to approach the appropriate Government for exemption.

[No. S-38014/07/2013-SS-I]

S. K. SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2018

**का.आ. 73.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार कांडला पोर्ट ट्रस्ट के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, अहमदाबाद (गुजरात) के पंचाट (संदर्भ सं. 121/2010) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 03.01.2018 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-37011/13/2008-आईआर (बी-II)]

रवि कुमार, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 3rd January, 2018

**S.O. 73.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 121/2010) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Ahmedabad (Gujarat) as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of Kandla Port Trust and their workmen, received by the Central Government on 03.01.2018.

[No. L-37011/13/2008-IR (B-II)]

RAVI KUMAR, Section Officer

**ANNEXURE****BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,  
AHMEDABAD****Present :**

Pramod Kumar Chaturvedi,  
Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court,  
Ahmedabad,  
Dated 07<sup>th</sup> December, 2017

**Reference: (CGITA) No. 121/2010**

The Chairman,  
Kandla Port Trust,  
P.O. Box No. 50,  
Gandhidham, Kutch (Gujarat)

...First Party

V/s

The General Secretary,  
Transport & Dock Workers Union,  
Kandla, 21, Yogesh Building, Plot No. 586,  
12-C, Gandhidham,  
Kutch (Gujarat)

...Second Party

For the First Party : Shri K.V. Gadhia

For the Second Party : None

**AWARD**

The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-37011/13/2008-IR(B-II) dated 25.03.2009 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:

**SCHEDULE**

“Whether the action of the chairman, Kandla Port Trust, P.O. Box No. 50, Gandhidham, Kutch in not providing higher grade salary to Shri Sajan Karvadira, Parmar Sandeep, Smt. Sunita Punjwani, Junior Engineer Civil Gr. I w.e.f. 01.08.2007 to 09.09.2007 is legal and justified? What relief the concerned workmen is entitled to?”

1. The reference dates back to 25.03.2009. Despite service of notice to both the party, the second party does not prefer to submit the statement of claim despite giving dozen of opportunities. The reference is approximately 9 years old and the first party filed the vakalatpatra of his advocate. The second party advocate failed to explain as to why the statement of claim has not been filed. Thus it appears that the second party is not willing to prosecute the reference.

2. Thus the reference is disposed of in the absence of the statement of claim of the second party with the observation as under: “the action of the chairman, Kandla Port Trust, P.O. Box No. 50, Gandhidham, Kutch in not providing higher grade salary to Shri Sajan Karvadira, Parmar Sandeep, Smt. Sunita Punjwani, Junior Engineer Civil Gr. I w.e.f. 01.08.2007 to 09.09.2007 is legal and justified.”

P. K. CHATURVEDI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2018

**का.आ. 74.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार कांडला पोर्ट ट्रस्ट के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, अहमदाबाद (गुजरात) के पंचाट (संदर्भ सं. 128/2010) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 03.01.2018 को प्राप्त हुआ था।

[ सं. एल-37011/6/2009-आईआर (बी-II) ]

रवि कुमार, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 3rd January, 2018

**S.O. 74.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 128/2010) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Ahmedabad (Gujarat) as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of Kandla Port Trust and their workmen, received by the Central Government on 03.01.2018.

[No. L-37011/6/2009-IR (B-II)]

RAVI KUMAR, Section Officer

**ANNEXURE**

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,  
AHMEDABAD**

**Present :**

Pramod Kumar Chaturvedi,  
Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court,  
Ahmedabad,  
Dated 07<sup>th</sup> December, 2017

**Reference: (CGITA) No. 128/2010**

The Chairman,  
Kandla Port Trust,  
P.O. Box No. 50,  
Gandhidham, Kutch (Gujarat)

...First Party

V/s

The General Secretary,  
Transport & Dock Workers Union,  
Kandla, 21, Yogesh Building, Plot No. 586,  
12-C, Gandhidham,  
Kutch (Gujarat)

...Second Party

For the First Party : Shri K.V. Gadhia

For the Second Party : None

**AWARD**

The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-37011/6/2009-IR(B-II) dated 31.12.2009 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:

**SCHEDULE**

“Whether the action of the chairman, Kandla Port Trust, Kandla, Gandhidham in not regularizing Shri Hadiya Bhupendra Jetha as regular Mistry against the vacant post is legal and justified? What relief the workman is entitled?”

1. The reference dates back to 31.12.2009. Despite service of notice to both the party, the second party does not prefer to submit the statement of claim despite giving dozen of opportunities. The reference is approximately 9 years old and the first party filed the vakalatpatra of his advocate. The second party advocate failed to explain as to why the statement of claim has not been filed.
2. Thus it appears that the second party is not willing to prosecute the reference.
3. Thus the reference is disposed of in the absence of the statement of claim of the second party with the observation as under: “the action of the chairman, Kandla Port Trust, Kandla, Gandhidham in not regularizing Shri Hadiya Bhupendra Jetha as regular Mistry against the vacant post is legal and justified.”

P. K. CHATURVEDI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2018

**का.आ. 75.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार कांडला पोर्ट ट्रस्ट के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, अहमदाबाद (गुजरात) के पंचाट (संदर्भ सं. 194/2013) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 03.01.2018 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-37011/13/2013-आईआर (बी-II)]

रवि कुमार, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 3rd January, 2018

**S.O. 75.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 194/2013) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Ahmedabad (Gujarat) as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of Kandla Port Trust and their workmen, received by the Central Government on 03.01.2018.

[No. L-37011/13/2013-IR (B-II)]

RAVI KUMAR, Section Officer

**ANNEXURE****BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,  
AHMEDABAD****Present :**

Pramod Kumar Chaturvedi,  
Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court,  
Ahmedabad,  
Dated 07<sup>th</sup> December, 2017

**Reference: (CGITA) No. 194/2013**

The Secretary,  
Kandla Port Trust, Administrative Office,  
P.O. Box No. 50,  
Gandhidham, Kutch (Gujarat)

...First Party

**V/s**

The General Secretary,  
Transport & Dock Workers Union,  
Kandla, 21, Yogesh Building, Plot No. 586,  
12-C, Gandhidham,  
Kutch (Gujarat)

...Second Party

For the First Party : Shri K.V. Gadhia

For the Second Party : None

**AWARD**

The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-37011/13/2013-IR(B-II) dated 19.11.2013 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:

**SCHEDULE**

“Whether the action of the management of M/s Golden Horn Containers Service, Gandhidham in terminating the services of 35 workmen without due process is justified? What relief these 35 workman are entitled to?”

1. The reference dates back to 19.11.2013. Despite service of notice to both the party, the second party does not prefer to submit the statement of claim despite giving dozen of opportunities. The reference is more than 4 years old and the first party filed the vakalatpatra of his advocate. The second party advocate failed to explain as to why the statement of claim has not been filed.

2. Thus it appears that the second party is not willing to prosecute the reference.

3. Thus the reference is disposed of in the absence of the statement of claim of the second party with the observation as under: “the action of the management of M/s Golden Horn Containers Service, Gandhidham in terminating the services of 35 workmen without due process is justified.”

P. K. CHATURVEDI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2018

**का.आ. 76.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, अहमदाबाद (गुजरात) के पंचाट (संदर्भ सं. 344/2004) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 03.01.2018 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12011/128/2000-आईआर (बी-II)]

रवि कुमार, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 3rd January, 2018

**S.O. 76.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 344/2004) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Ahmedabad (Gujarat) as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of United Bank of India and their workmen, received by the Central Government on 03.01.2018.

[No. L-12011/128/2000-IR (B-II)]

RAVI KUMAR, Section Officer

### ANNEXURE

#### BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, AHMEDABAD

##### Present :

Pramod Kumar Chaturvedi,  
Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court,  
Ahmedabad,  
Dated 07<sup>th</sup> December, 2017

##### Reference: (CGITA) No. 344/2004

The Chief Regional Manager,  
United Bank of India,  
Western Region, 5<sup>th</sup> Floor, 25, sir Pheroz Shah Mehta Road,  
Mumbai – 400001

...First Party

##### V/s

The Joint Secretary,  
United Bank of India Sramik Karmachari Samity,  
C/o UBI, Manekchawk Branch, Manekchawk,  
Ahmedabad (Gujarat) – 380001

...Second Party

For the First Party : Shri K.V. Gadhia

For the Second Party : Shri B.M. Joshi

### MODIFIED AWARD

The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-12011/128/2000-IR(B-II) dated 29.09.2000 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:

### SCHEDULE

“Whether the action of the management of United Bank of India in denying pensionary benefits to Shri B.H. Chaudhary employed as permanent part-time Sweeper by rejecting his option for pension dated 29.09.1994 is legal and justified? If not then to what relief the concerned workman is entitled to?”

1. The reference dates back to 29.09.2000. The second party submitted the statement of claim Ex. 4 on 20.11.2000 along with number of documents and Solicitor Firm K.V. Gadhia Associates submitted the vakalatpatra Ex. 8 on 19.02.2011 but did not prefer to submit the written statement. Since the submission of vakalatpatra Ex. 8 by the first party, the second party union failed to appear in person to lead his evidence. The advocate of the second party stated in the court on 23.08.2017 that he tried to contact his client by writing a letter but he has not responded. It is also noteworthy that on 06.02.2017, a notice was issued to the second party union to appear and lead evidence on 21.03.2017 but on 21.03.2017 and thereafter on 11.05.2017, 07.06.2017 and 23.08.2017, the second party union did not appear. Thus in the light of the statement of the advocate and non-appearance of the second party union on aforesaid dates, indicates that the second party union is not willing to prosecute the case.

2. Thus the reference in the absence of the evidence of the second party, is finally disposed of with the observation as under: “the action of the management of United Bank of India in denying pensionary benefits to Shri B.H. Chaudhary employed as permanent part-time Sweeper by rejecting his option for pension dated 29.09.1994 is legal and justified.”

P. K. CHATURVEDI, Presiding Officer



नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2018

**का.आ. 77.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, अहमदाबाद (गुजरात) के पंचाट (संदर्भ सं. 60/2005) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 03.01.2018 को प्राप्त हुआ था।

[ सं. एल-12012/41/2005-आईआर (बी-II) ]

रवि कुमार, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 3rd January, 2018

**S.O. 77.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 60/2005) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Ahmedabad (Gujarat) as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of Bank of India and their workmen, received by the Central Government on 03.01.2018.

[No. L-12012/41/2005-IR (B-II)]

RAVI KUMAR, Section Officer

**ANNEXURE****BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,  
AHMEDABAD****Present :**

Pramod Kumar Chaturvedi,  
Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court,  
Ahmedabad,  
Dated 06<sup>th</sup> December, 2017

**Reference: (CGITA) No. 60/2005**

The Zonal Manager,  
Bank of India,  
Ahmedabad Zone, Bhadra,  
Ahmedabad (Gujarat)

...First Party

**V/s**

The General Secretary,  
Bank of India Staff Co-op. Housing Society,  
No. 2, Near H.L. Commerce College,  
Opp. Choice Restaurant Gali, Navrangpura,  
Ahmedabad (Gujarat)

...Second Party

For the First Party : Shri D.C. Gandhi

For the Second Party : Shri Hemal K. Acharya

**AWARD**

The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-12012/41/2005-IR(B-II) dated 20.07.2005 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:

**SCHEDULE**

“Whether the action of the management of Bank of India in terminating the services of Shri D.M. Baxi from the post of Cashier from its Relief Road Branch, Ahmedabad by imposing the punishment of compulsory retirement is legal and justified? If not to what relief is the workman is entitled to and what extent?”

1. The reference dates back to 20.07.2005. The second party workman in his statement of claim Ex. 4 has alleged that he was appointed as Cash-cum-Accounts Clerk by the first party The Zonal Manager, Bank of India, Ahmedabad

Zone, Bhadra, Ahmedabad, hereinafter referred to as first party on 15.12.1972. He had been working in various branches of the first party with a record of satisfactory work and conduct and later on, he was promoted as Cashier and Head Cashier in the category of C and E respectively. He has further alleged that on 31.05.2000, while he was working as Head Cashier category E at Relief Road Branch of Ahmedabad, the Sepoy attached to the cash department of the branch came late, therefore, cash operation of the bank could not commence in time and he himself managed the cash from the cash safety to the various co-cashiers for the commencement of the work. But the manager of the branch desired that he should hand over the charge of the cash to another cashier which he refused to do so unless the procedure as required by manual of instructions is followed. Disregarding the said laid down procedure, the manager insisted to his aforesaid decision. Consequently, the workman lost his control and resultantly he misbehaved with the branch manager. He has further alleged that the branch manager reported the said incidence in a strict manner to the competent authority, therefore, he was put under suspension on 01.06.2000 and a charge-sheet dated 20.07.2000 was served on him, inter alia with following charges:

- i. Reporting late for duties on 31.05.2000, leaving the cash cabin endangering the safety and security of cash, refusing to discharge the duties allotted and halting the functioning of the branch affecting customer service;
- ii. Refusing to handover charge of the cash and throwing away the keys;
- iii. Abusing the manager using filthy language and shouting at him at the top of the voice, insulting him and challenging his authority and exhibiting riotous disorderly and indecent behaviour in the branch premises;
- iv. Assaulting the manager and creating bas scene/nuisance in the branch premises.

He has further alleged that the charge-sheet is itself a conspiracy. He is a member of minority union; therefore, there was no one to represent him in the department enquiry. He has further alleged that he went under depression and has undergone a treatment of a psychiatrist. He was not given proper opportunity to defend himself as being conducted in a flagrant violation of the principles of natural justice because he submitted his defence on 23.10.2000 and the enquiry office submitted the report on 24.10.2000. The deputy chief general manager of the first party issued a show cause notice on the same day with a pre-determined mind to terminate his services. The workman submitted his reply on 27.10.2000 w.r.t. the proposed punishment of compulsory retirement and the workman raised no. of issues in the personal hearing but to no result and he was ordered to be compulsory retirement.

2. The first party submitted the written statement Ex. 11 denying all the allegations made in the statement of claim regarding mala-fide and flagrant violation of principles of natural justice in conducting the departmental enquiry and proposed punishment. The first party has submitted no. of documents regarding department enquiry.

3. The second party workman challenged the legality of the enquiry and submitted his affidavit Ex. 10 reiterating the averments made in the statement of claim but in his cross-examination, he has stated that the department enquiry was concluded on 18.10.2002 but he has not said anything which may create doubt regarding the enquiry.

4. Later the record reveals that the workman has expired on 03.03.2014, vide application Ex. 13, his legal heirs is substituted but he did not pursue the case. Since then, they have not been appearing. The charges levelled in the charge-sheet are serious one and the punishment of compulsory retirement was imposed and I do not find any illegality in the department enquiry and the punishment imposed. It is also noteworthy that the compulsory retirement does not deprive the workman or his family from the gratuity, provident fund and pension. Therefore, no interference is required.

5. The award is passed accordingly.

P. K. CHATURVEDI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2018

**का.आ. 78.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार कांडला पोर्ट ट्रस्ट के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, अहमदाबाद (गुजरात) के पंचाट (संदर्भ सं. 119/2010) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 03.01.2018 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-37011/9/2008-आईआर (बी-II)]

रवि कुमार, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 3rd January, 2018

**S.O. 78.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 119/2010) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Ahmedabad (Gujarat) as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of Kandla Port Trust and their workmen, received by the Central Government on 03.01.2018.

[No. L-37011/9/2008-IR (B-II)]

RAVI KUMAR, Section Officer

**ANNEXURE**

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,  
AHMEDABAD**

**Present :**

Pramod Kumar Chaturvedi,  
Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court,  
Ahmedabad,  
Dated 07<sup>th</sup> December, 2017

**Reference: (CGITA) No. 119/2010**

The Chairman,  
Kandla Port Trust,  
P.O. Box No. 50,  
Gandhidham, Kutch (Gujarat)

...First Party

**V/s**

The General Secretary,  
Transport & Dock Workers Union,  
Kandla, 21, Yogesh Building, Plot No. 586,  
12-C, Gandhidham,  
Kutch (Gujarat)

...Second Party

For the First Party : Shri K.V. Gadhia

For the Second Party : None

**AWARD**

The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-37011/9/2008-IR(B-II) dated 10.02.2009 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:

**SCHEDULE**

“Whether the action of the management of Kandla Port Trust, P.O. Box No. 50, Gandhidham, Kutch in posting of Dresser in place of First Aider after retirement of Shri Shobnath Tiwari, First Aider, is legal and justified? What relief the workman concerned is entitled to?”

1. The reference dates back to 10.02.2009. Despite service of notice to both the party, the second party does not prefer to submit the statement of claim despite giving dozen of opportunities. The reference is approximately 9 years old and the first party filed the vakalatpatra of his advocate. The second party advocate failed to explain as to why the statement of claim has not been filed. Thus it appears that the second party is not willing to prosecute the reference.

2. Thus the reference is disposed of in the absence of the statement of claim of the second party with the observation as under: “the action of the management of Kandla Port Trust, P.O. Box No. 50, Gandhidham, Kutch in posting of Dresser in place of First Aider after retirement of Shri Shobnath Tiwari, First Aider, is legal and justified.”

P. K. CHATURVEDI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2018

**का.आ. 79.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार विजया बैंक के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक

अधिकरण/श्रम न्यायालय, अहमदाबाद (गुजरात) के पंचाट (संदर्भ सं. 377/2004) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 03.01.2018 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12011/241/2000-आईआर (बी-II)]

रवि कुमार, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 3rd January, 2018

**S.O. 79.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 377/2004) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Ahmedabad (Gujarat) as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of Vijaya Bank and their workmen, received by the Central Government on 03.01.2018.

[No. L-12011/241/2000-IR (B-II)]

RAVI KUMAR, Section Officer

### ANNEXURE

#### BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, AHMEDABAD

##### Present :

Pramod Kumar Chaturvedi,  
Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court,  
Ahmedabad,  
Dated 08<sup>th</sup> December, 2017

##### Reference: (CGITA) No. 377/2004

The Branch Manager,  
Vijaya Bank, Regional Office,  
Kamdhenu Complex, Near Polytechnic, Ambawadi,  
Ahmedabad (Gujarat)

...First Party

##### V/s

The General Secretary,  
Vijaya Bank Workers Organisation,  
C/o Vijaya Bank, Navarangpura Branch,  
Ahmedabad (Gujarat)

...Second Party

For the First Party : Shri Sanjay Kurian

For the Second Party : Shri K.R. Mishra

### AWARD

The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-12011/241/2000-IR(B-II) dated 29.01.2001 referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:

### SCHEDULE

“Whether the action of the management of Vijaya Bank, Regional Office, Ahmedabad in terminating/discontinuing the services of temporary/casual employees Shri Vithalbhai Veljibhai Leeva and 23 others w.e.f. 15.11.1995 without complying the provisions of Section 25 F, G and H of the Industrial Dispute Act, 1947 is legal and justified? If not, then to what relief the concerned employees are entitled to?”

1. The reference dates back to 29.01.2001. The second party submitted the statement of claim on 17.09.2004 enclosed with the list of workmen along with application Ex. 10 for staying the recruitment process likely to be followed by the management violating the due process of law. The then Presiding Officer vide order Ex. 17 dated 14.06.2011 stayed the recruitment process as prayed by the second party union/workmen.

2. The first party submitted the written statement Ex. 26 on 18.11.2011. Thereafter, the second party submitted the affidavits Ex. 28, 29, 30, 31 and 32 of the workmen Manojkumar Deepaji Mahabhar, Govind Mangalsinh Devda, Amit

Ambalal Raval, Shailesh Bhagchandra Bhrambhatt and Chetan Bhikhabhai Solanki respectively. None of the witness was cross-examined by the first party despite giving number of opportunities. Thereafter, the second party advocate moved an application Ex. 33 on 21.01.2013 for closing the right of first party to cross-examine the aforesaid witnesses. Since then, the second party and his witnesses have been absent and have not been appearing despite giving number of opportunities. Today on 08.12.2017, the advocate for the second party union Shri K.R. Mishra orally stated that the matter has been settled between the parties and the second party union and its workmen have not been in his contact, therefore, the second party has not been appearing. The advocate for the first party is present for cross-examining the aforesaid second party witness.

3. Thus it appears that second party union or the workmen are not willing to prosecute the case.

4. Thus the reference is disposed of in the absence of the evidence of the second party union/workmen with the observation as under: “the action of the management of Vijaya Bank, Regional Office, Ahmedabad in terminating/discontinuing the services of temporary/casual employees Shri Vithalbhai Veljibhai Leeva and 23 others w.e.f. 15.11.1995 without complying the provisions of Section 25 F, G and H of the Industrial Dispute Act, 1947 is legal and justified.”

P. K. CHATURVEDI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2018

**का.आ. 80.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, भुवनेश्वर के पंचाट (संदर्भ सं. 15/2017) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 03.01.2018 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-38011/03/2016-आईआर (बी-II)]

रवि कुमार, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 3rd January, 2018

**S.O. 80.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 15/2017) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Bhubaneswar as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of Paradip Port Trust and their workmen, received by the Central Government on 03.01.2018.

[No. L-38011/03/2016-IR (B-II)]

RAVI KUMAR, Section Officer

#### ANNEXURE

#### CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, BHUBANESWAR

##### Present:

Shri B.C. Rath,  
Presiding Officer, C.G.I.T.-cum-Labour  
Court, Bhubaneswar

#### INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 15/2017

No. L-38011/03/2016-IR(B-II), dated 13.02.2017

**Date of Passing Order – 15<sup>th</sup> November, 2017**

##### Between:

The Chairman,  
Paradip Port Trust, Paradip,  
Dist. Jagatsinghpur, Odisha

...1<sup>st</sup> Party-Management

##### (And)

The General Secretary,  
Paradip Port Workers Union,  
Badapadia, Paradip Port, Jagatsinghpur,  
Odisha

...2<sup>nd</sup> Party-Union

**Appearances:**

None	...	For the 1 <sup>st</sup> Party-Management
None	...	For the 2 <sup>nd</sup> Party-Union

**ORDER**

Case taken up. Parties are absent. The 2<sup>nd</sup> Party-Union has not filed any statement of claim despite notice through regd. post. As such, it seems that the 2<sup>nd</sup> party-Union is not interested in prosecuting its case. However the dispute cannot be adjudicated upon for want of pleadings on behalf of the parties. As such there is no alternative except to return the reference to the Government for necessary action at its end.

- Accordingly the reference is returned to the Government unanswered for necessary action at its end.

Dictated & Corrected by me.

B. C. RATH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2018

**का.आ. 81.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार कोरपोरेशन बैंक के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. 1, दिल्ली के पंचाट (संदर्भ सं. 70/2017) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 03.01.2018 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/09/2017-आईआर (बी-II)]

रवि कुमार, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 3rd January, 2018

**S.O. 81.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 70/2017) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Delhi as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of Corporation Bank and their workmen, received by the Central Government on 03.01.2018.

[No. L-12012/09/2017-IR (B-II)]

RAVI KUMAR, Section Officer

**ANNEXURE**

**IN THE COURT OF SHRI AVTAR CHAND DOGRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO.1, ROOM NO. 511, DWARKA COURT COMPLEX, SECTOR-10 DWARKA, DELHI-110075**

**ID. No. 70/2017**

Shri Nirmal Prasad, C/o Corporation Bank,  
Safai Karmachari Sangh, Office: 6054,  
Gali Mandir Satya Naryana, Nabi Karim,  
Paharganj  
New Delhi-110055

...Claimant

**Versus**

- General Manager,  
Personnel Administrative Division,  
Industrial Relations Wing, Head Office,  
Mangala Devi Temple Road,  
Mangalore-575001
- The General Manager,  
TAD, Corporation Bank,  
Deshbhandu, Gupta Road, Karol Bagh,  
New Delhi-110005

...Managements

**AWARD**

In the present case, a reference was received from the appropriate Government vide letter No.L-12012/09/2017(IR(B-II)) dated 20.03.2017 under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Act, for adjudication of a dispute, terms of which are as under:

“Whether the workman Shri Nirmal Prasad, M.No. 1685, Part Time Sweeper is entitled for the difference of salary for the period of suspension from the Management of Corporation Bank after conclusion of proceedings and order by the Appellate Authority? If not, then what relief the workman is entitled to?”

2. In the reference order, the appropriate Government commanded the party/ies raising the dispute to file statement of claim, complete with relevant documents, list of reliance and witnesses with this Tribunal within 15 days of receipt of the reference order and to forward a copy of such statement of claim to the opposite parties involved in the dispute. Despite directions so given, Claimant opted not to file his claim statement with the Tribunal.

3. On receipt of the above reference, notice was sent to the workman as well as the managements. Neither the postal article sent to the claimant, referred above, was received back nor was it observed by the Tribunal that postal services remained affected during the period, referred above. Therefore, every presumption lies in favour of the fact that the above notice was served upon the claimant. Despite service of the notice, claimant opted to abstain away from the proceedings. No claim statement was filed on his behalf. Thus, it is clear that the claimant is not interested in adjudication of the reference on merits.

4. Since the claimant has neither put in his appearance nor has he led any evidence so as to prove his cause against the management, as such, this Tribunal is left with no choice, except to pass a ‘No Dispute/Claim’ award. Let this award be sent to the appropriate Government, as required under Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, for publication.

Date : December 14, 2017

A. C. DOGRA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2018

**का.आ. 82.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, हैदराबाद के पंचाट (संदर्भ सं. 30/2007) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 03.01.2018 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/115/2006-आईआर (बी-II)]

रवि कुमार, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 3rd January, 2018

**S.O. 82.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 30/2007) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of Oriental Bank of Commerce and their workmen, received by the Central Government on 03.01.2018.

[No. L-12012/115/2006-IR (B-II)]

RAVI KUMAR, Section Officer

**ANNEXURE****BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT HYDERABAD**

**Present :** Sri Muralidhar Pradhan, Presiding Officer

Dated the 27<sup>th</sup> day of October, 2017

**INDUSTRIAL DISPUTE No. 30/2007**

**Between :**

Sri T. Rajender Singh,  
8-3-228/606/1, Rahmath Nagar,  
Yousufguda,  
Hyderabad -45

...Petitioner

**AND**

The General Manager (HRD),  
Oriental Bank of Commerce,  
S.B.U., Ashoka My Home Chambers,  
1-8-303, Sardar Patel Road,  
Secunderabad – 500 003

...Respondent

**Appearances :**

For the Petitioner : Sri William Burra, Advocate  
For the Respondent : M/s. K. Raghuram Reddy & M. Subramanya Sastry, Advocates

**AWARD**

The Government of India, Ministry of Labour by its order No. L-12012/115/2006-IR(B-II) dated 5.6.2007 referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 requiring this forum to decide the question:

**SCHEDULE**

“Whether the action of the management of Oriental Bank of Commerce by regularising the services of some of the workmen of erstwhile Global Trust Bank and not regularising the services of Shri T. Rajender Singh, Ex-runner is legal and/or justified? If not, what relief the workman is entitled to?”

On receipt of the reference this Tribunal has registered and numbered the reference as I.D. No. 30/2007 and issued notices to both the workman and the management. They both appeared before the court and engaged their respective counsels with the leave of the court and consent of either party.

**2. The averments made in the claim statement in brief are as follows:**

It is submitted that the Petitioner worked as Runner from 1.2.1997 to 30.11.2005 in erstwhile Global Trust Bank and later in the Oriental Bank of Commerce, Secunderabad. Initially, he worked as Runner through M/s. Agile and Suraksha Security Services from 1.2.1997 to 31.1.2001 and through Global Corporate Services from 1.2.2001 to 14.8.2004 and thereafter worked through the same agency from 14.8.2004 onwards for Oriental Bank of Commerce, Secunderabad. The Petitioner submits that other workmen who worked with him in similar capacity in the erstwhile Global Trust Bank are absorbed in the Oriental Bank of Commerce, whereas he was not considered on the grounds of eligibility criteria. The Petitioner's total service was more than 8 years and he has worked for more than 300 days in each year. He studied upto 8<sup>th</sup> class and also able to read and write, three languages, viz., Telugu, English and Hindi. It is further stated that the Respondent management has entered into an agreement with the representatives of the Federation, New Delhi on 30.9.2005, wherein it was agreed to absorb the erstwhile runners working through agencies as Peons in subordinate cadre with minimum educational qualification of 8<sup>th</sup> standard. Even though the Petitioner has fulfilled all the conditions laid down for absorption his application was not considered. The details of attendance shows that during the year 2004-2005, the Petitioner worked for more than 240 days in a year. Provisions of Sec.25-F were not observed in terminating the services of the Petitioner. He prayed to direct the Respondent bank for his absorption/reinstatement with back wages, continuity of service and other attendant benefits.

**3. Respondents filed their counter with the averments in brief as follows:**

There is no employer-employee relationship between the Respondent bank and the Petitioner as he was engaged as Runner through M/s Agile and Suraksha Security Services for some time and thereafter through M/s Global Corporate Services, as admitted by him. It can not be said that the Petitioner was ever a workman as no appointment letter was issued to him by the erstwhile Global Trust Bank or by the Oriental Bank of Commerce. After merger of Global Trust Bank with Oriental Bank of Commerce the Respondent bank was under no obligation to absorb the employee of outsourcing agency who was working on their behalf for Global Trust Bank. However, as per the guidelines approved by the Board of Directors of the Bank, a circular dated 28.10.2005 was issued which provides that only those persons who were working through the outsourcing agencies with erstwhile Global Trust Bank as on the date of amalgamation i.e., 14.8.2004 will be eligible for consideration for absorption subject to fulfilling other conditions of eligibility criteria. The Petitioner does not possess the required educational qualification is pass in VIII standard as per the said circular, thus, he was not considered for absorption and he was informed accordingly. Therefore, the present reference is not maintainable in law and liable to be rejected.

4. The Petitioner has examined himself as WW1 and has also exhibited the photostat copies of four documents which are marked as i.e., Ex.W1 to W4. The Respondent has examined Sri J.P. Sarma, the Chief Manager of the Bank as MW1 and Sri Dr. Vijay Kumar, the Senior Manager of the Bank as MW2 on their behalf and also relied on eight documents which have been marked as exhibits Ex.M1 to M8.



5. I have already heard from both the sides in this matter.

6. **In view of the pleadings of both the sides, the points for consideration are as follows:**

I. Whether the action of the management of Oriental Bank of Commerce by regularising the services of some of the workmen of erstwhile Global Trust Bank and not regularising the services of Shri T. Rajender Singh, Ex-runner is legal and/or justified?

II. If not, what relief the workman is entitled to?

7. The Learned Counsel appearing on behalf of the Petitioner contended that the Petitioner worked as a Runner from 1.2.1997 to 30.11.2005 in the erstwhile Global Trust Bank and later in the Oriental Bank of Commerce at Secunderabad. Initially, the Petitioner worked as a Runner through M/s. Agile and Suraksha Security Services from 1.2.1997 to 31.1.2001 and through Global Corporate Services from 1.2.2001 to 14.8.2004 and thereafter worked through the same agency from 15.8.2004 onwards for the Respondent (Oriental Bank of Commerce, Secunderabad). In all the Petitioner has rendered more than 8 years of service, out of which, six years through the aforesaid agencies and about more than two years directly under the Respondent during the period from 22.8.2002 to 30.11.2005. Finally on 30.11.2005 his services were terminated. It is contended that the Petitioner worked as a Runner and he used to work from 1997 to 2005 not less than 300 days in any calendar year. The duties of a Runner as admitted by the management witnesses are – carrying instruments like cheques, DDs from branches to service centre, and in case runners are posted in the administrative offices, they used to take care distribution of dispatch within the office/Department and related filing works. It is further contended that the nature of work of Runner as admitted by the management witness is perennial in nature. The engagement of contract labour in such work through outsourcing agency is only “Sham” contract. Therefore, the Petitioner is deemed to be an employee directly employed by the Respondent bank during the period from 1.2.1997 to 30.11.2005. Thus, the services rendered by the Petitioner through outsourcing agencies firstly with the erstwhile Global Trust Bank and secondly with the Oriental Bank of Commerce is a “sham” contract. Hence, the Petitioner is deemed to be an employee directly by the bank and hence in this case master and servant relationship or employer and employee relationship is clearly established. It is also contended that the other workmen who worked with the Petitioner in similar capacity in the erstwhile Global Trust Bank are absorbed in the Oriental Bank of Commerce whereas, the Petitioner was not considered on the ground of eligibility criteria. The Petitioner’s total service was more than 8 years and he has worked for more than 300 days in each year. He has studied upto class VIII and also able to read and write three languages, i.e., Telugu, English and Hindi. It is also contended that the Respondent management has entered into an agreement with the representatives of the Federation, New Delhi on 30.9.2005 wherein it had been agreed to absorb, the erstwhile Global Trust Bank Runners working through agencies as Peons in subordinate cadres with minimum educational qualification of 8<sup>th</sup> standard. Even though the Petitioner has fulfilled all the conditions laid down for absorption, his application was not considered. The details of attendance shows that during the year 2004-2005 the Petitioner has worked for more than 240 days in a year. The Respondent bank while terminating the Petitioner from service has not followed the provisions of Sec.25-F of the Industrial Disputes Act, 1947. The Petitioner is required to be absorbed as a permanent employee in the Respondent bank with back wages, continuity of service and other attendant benefits.

8. On the other hand, the Learned Counsel appearing on behalf of the Respondent contended that there is no employer and employee relationship between the Respondent bank and the Petitioner as he was engaged as a Runner through M/s. Agile and Suraksha Security Services for some time and thereafter through Global Corporate Services as admitted by him. As per his contention, no appointment letter was issued to the Petitioner either by the erstwhile Global Trust Bank or by the Oriental Bank of Commerce. After merger of Global Trust Bank with the Oriental Bank of Commerce the Respondent bank was under no obligation to absorb the employees of outsourcing agencies, who were working on their behalf for Global Trust Bank. He further contended that as per the guidelines approved by the Board of Directors of the Bank on 20.8.2005. One circular was issued by the Respondent, wherein it had been provided that only those persons who were working through outsourcing agencies with the erstwhile Global Trust Bank as on the date of amalgamation i.e., 14.8.2004 will be eligible for absorption subject to fulfilling other conditions of eligibility criteria. As admitted by the Petitioner he does not possess the required educational qualification as required in the guidelines. As per his contention the documents relied on by the Petitioner vide Ex.W2 clearly states that “only those Runners/office boys who were working in the erstwhile Global Trust Bank branches/offices as on the date of amalgamation i.e., 14.8.2004 would be eligible to apply, minimum qualification required should be 8<sup>th</sup> standard pass. Admittedly, the Petitioner had applied for the post of Runner but Ex.W1, the Photostat copy of the form of transfer certificate goes to show that at the time of leaving the school, the Petitioner was studying in Class VIII which clearly indicates that he has not passed VIII standard which shows that on the own admission of the Petitioner he has not passed VIII standard and has not fulfilled the required criteria to be absorbed as a Runner in the Respondent’s bank at the time of its amalgamation, and for this reason the case of the Petitioner was not considered, and he had been informed accordingly. Further more, the Petitioner has not impleaded the contractors/outsourcing agencies as parties in this case under whom he was working and in absence of the contractors the case of as such the Petitioner is liable to

be dismissed and the Petitioner is not entitled to get any relief. Therefore, the claim of the Petitioner is not tenable in the eye of Law, and is liable to be rejected.

9. On consideration of the rival contentions of the Advocates of both the sides as well as the evidence adduced by the parties and the materials available on record it is seen that no documents have been filed from the side of the Petitioner to show that, which workmen worked with the Petitioner in similar capacity in the erstwhile Global Trust Bank are absorbed in the Oriental Bank of Commerce. Admittedly, the Petitioner was not considered to be absorbed in the Respondent's bank on the ground of eligibility criteria. Pursuant to the guidelines, vide Ex.W2, the Petitioner has applied for absorption as Runner, wherein minimum criteria to be eligible for the post was passing of class VIII. Ex.W1 clearly indicates that the Petitioner has not passed class VIII at the time of filing of the application. When he has not fulfilled the required criteria to be absorbed as a Runner, his case was not considered and the Respondent bank has not regularized his services as Runner and the same has been intimated to the Petitioner. In such a circumstances, it can safely be stated that the action of the Respondent bank in not regularising the service of Sri T. Rajendar Singh, Ex.Runner is not legal and justified.

Thus, Point No.I is answered accordingly.

10. **Point No.II:** Admittedly, the Petitioner was working as a Runner through M/s. Agile and Suraksha Security Services from 1.2.1997 to 31.1.2001 and through Global Corporate Services from 1.2.2001 to 14.8.2004 and thereafter worked through the same agency from 14.8.2004 onwards for the Respondent. The Respondent has utilized the services of the Petitioner for a long period. MW2 in his cross examination has clearly admitted that the contract agreement entered between the erstwhile Global Trust Bank and Global Corporate Services, Ex.M5 came into force on 22.8.2000 and expired after completion of 24 months for a period of two years which was directly with the erstwhile Global Trust Bank. Therefore the service rendered by the Petitioner though through outsourcing agency, but it was taken directly under the Respondent from 22.8.2000 to 14.8.2004, similarly when the Global Trust Bank was amalgamated with Oriental Bank of Commerce, from 14.8.2004 onwards, the Petitioner rendered service directly under the Oriental Bank of Commerce, and he was terminated after lapse of one year of the amalgamation, i.e., from 14.8.2004 to 30.11.2005, which clearly shows that the Petitioner has rendered his services to Respondent during the aforesaid period. It is also not known how the Respondent was utilizing the services of the Petitioner from 22.8.2002 onwards when admittedly there was no agreement between the Respondent and the outsourcing agencies. This shows that the Respondent was well aware of the fact that the Petitioner is working under its establishment as a workman and the Respondent has utilized the services of the Petitioner like an employee of the establishment and as such, employer and employee relationship was existing between the Respondent and the Petitioner, and the plea of the Respondent that they were utilizing the services of the Petitioner only through outsourcing agency i.e., the contractors, is not acceptable. Moreover, the Respondent has failed either to produce any document or to show any reason in which way he has engaged the Petitioner in his establishment after its amalgamation. Further more, the Respondent has admitted that bank has considered the application of the Petitioner for his absorption as Runner but as the Petitioner failed to fulfill the required criteria for the post of Runner. It was not considered. This shows that when the case of the Petitioner was not considered and the Respondent has failed to absorb him in the bank, he terminated the services of the Petitioner. But Before termination of the Petitioner from service the Respondent bank had to see the plight of the workman, when workman had worked for more than 8 years under its establishment through outsourcing agency as well as directly and was also acquainted with the work culture. In such a circumstances the Respondent should have engaged the workman atleast as a daily rated labour. But the Respondent has not considered the case of the workman. More over, while terminating the services of the Petitioner the Respondent has to comply with the provisions required under Sec.25-F of the Industrial Disputes Act, 1947, but in this case, it has not been done. Admittedly, the Petitioner has worked for more than 8 years under the Respondent, through different agencies continuously as a Runner and also out of which, for one year and four months directly under the Respondent and as such, the Petitioner comes under the definition of a workman under Industrial Disputes Act, 1947. When the Petitioner was retrenched from service the Respondent was expected to retrench the workman as per the provisions contained under Sec.25.F of the Industrial Disputes Act, 1947. But in this case the Respondent has not complied it. Therefore, the termination/retrenchment of the Petitioner workman is in violation of Sec.25F of the Industrial Disputes Act, 1947. Since the Respondent has not shown the reasons for the retrenchment of the workman and even the workman is not in receipt of any notice of termination or notice or notice pay/one month pay and if the workman was not paid any retrenchment compensation of 15 days average pay for every completed year of service; the retrenchment or termination of the Petitioner workman is illegal, and the Petitioner is entitled to get benefit under Sec.25-F of the Industrial Disputes Act, 1947.

Thus, Point No.II is answered accordingly.

11. In view of the findings given under Point Nos. I & II, the Petitioner is entitled to get a chance to work under the Respondent atleast as a daily rated workman and is also entitled to get the terminal benefits as required under Sec.25-F of the Industrial Disputes Act, 1947.

**Result:**

In view of the findings given in Point No.I, the reference is answered as follows:

The action of the management of Oriental Bank of Commerce of regularising the services of some of the workmen erstwhile Global Trust Bank and not regularising the services of Shri T. Rajender Singh, Ex-runner is legal and justified. But, in view of the findings given Point No.II, as the workman has not been retrenched by following due procedure of Law, the Respondent should consider the Petitioner for his absorption as a daily rated worker, if he is eligible to work. If the Petitioner is not eligible to work under any rules, the Respondent is at liberty to retrench the Petitioner only by following the procedure laid down under Sec.25-F of the Industrial Disputes Act, 1947.

Award is passed accordingly. Transmit.

Typed to my dictation by Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant transcribed by her and corrected by me on this the 27<sup>th</sup> day of October, 2017.

MURALIDHAR PRADHAN, Presiding Officer

**Appendix of evidence**

Witnesses examined for the  
Petitioner

WW1: Sri T Rajender Singh

Witnesses examined for the  
Respondent

MW1: Sri J.P. Sarma  
MW2: Sri Dr. Vijay Kumar Joseph

**Documents marked for the Petitioner**

- Ex.W1 : Photostat of Copy of school leaving certificate  
Ex.W2 : Photostat of circular dated 28.10.2005 issued by the Respondent bank erstwhile Global Trust Bank  
Ex.W3 : Photostat of representation dt.28.7.2004 of WW1  
Ex.W4 : Photostat of application dt. 13.8.2004 of WW1

**Documents marked for the Respondent**

- Ex.M1 : Photostat of Ir.No.Q&O/CMR/LET/732/2005 dt.30.11.2005  
Ex.M2 : Agreement between Globla Trust Bank and M/s Global Corporate Services  
Ex.M3 : Attendance register for the period from 1.4.2005 to 31.3.2007  
Ex.M4 : Attendance register for the period from January 2005 to January, 2006  
Ex.M5 : Agreement dt. 20.3.2002 relating to record keeping services  
Ex.M6 : Agreement relating to house keeping etc..  
Ex.M7 : Photostat copy of payment particulars of the Petitioner to the Global Corporate Services Pvt. Ltd., for the month of October 2005  
Ex.M8 : Photostat copy of bank statement of account of M/s Global Corporate Services Pvt. Ltd for the period from 31.3.2000 to 6.1.2006

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2018

**का.आ. 83.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स मिड्हा इंटरप्राइजेज के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय, जयपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या 23/2017) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27.12.2017 को प्राप्त हुआ था।

[ सं. एल-22012/15/2017-आईआर (सीएम-II) ]

राजेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 8th January, 2018

**S.O. 83.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 23/2017) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s. Middha Enterprises and their workmen, received by the Central Government on 27.12.2017.

[No. L-22012/15/2017-IR (CM-II)]

RAJENDER SINGH, Section Officer

#### ANNEXURE

#### CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JAIPUR

Presiding Officer, Bharat Pandey

**I.D. 23/2017**

Reference No.L-22012/15/2017[IR(CM-2)] dated: 19.7.2017

Shri Ram Kumar  
S/o Sh. Hanuman Prasad Saraswat  
R/o Binani Chowk, Bikaner

**V/s**

1. Project Head  
Neyveli Lignite Corporation  
India Limited, Barsingsar,  
Tehsil & District : Bikaner.
2. Proprietor, M/s Middha Enterprises  
Bikaner Road, Suratgarh – 335804.

#### AWARD

Dated: 28.11.2017

1. The Central Government in exercise of the powers under clause (d) of Sub Section 1 & 2(A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act 1947 has referred the following Industrial dispute to this tribunal for adjudication:-

“क्या प्रबंधन, मै0 नेयवली लिगनाईट कार्पोरेशन इण्डिया लि0, बीकानेर के ठेकेदार फर्म मै0 मिड्डहा एन्टरप्राइजेज सूरतगढ का कर्मकार श्री राम कुमार सुपरवाइजर को दिनांक 06.01.2016 से नौकरी से पृथक किया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत है? यदि नहीं तो कर्मकार क्या अनुतोष पाने का अधिकारी है ?”

2. Pursuant to the receipt of the reference order, registered notices were issued to the parties as per the order of the tribunal fixing. 26.10.2017 for filing statement of claim.

3. On 26.10.17 Sh. Sunil Kumar Pareek, CPF No.36598, Manager/Geology, NLC. India Ltd., Barsingsar Project, appeared on behalf of non-applicant. None appeared on behalf of applicant. Sh. Sunil Kumar Pareek alleged that both the parties have entered into compromise. Next date 16.11.17 was fixed for both the parties to appear for filing compromise or statement of claim.

4. Sh. Sunil Kumar Pareek on 26.10.2017 filed photocopy of notice sent to non-applicant by tribunal, photocopy of authority dated 23.10.2007 by non-applicant to Sh. Sunil Kumar Pareek to appear in tribunal on 26.10.17 for representing the non-applicant, photocopy of minutes of meeting dated 9.6.17 about conciliation held at R.L.C., Jaipur. The content shows that parties have agreed during conciliation to settle their dispute outside the court & withdraw the complaint against Biharilal, Proprietor, Middha Enterprises, Bikaner Road, Suratgarh & NLC India Ltd. before the R.L.C., Jaipur.

5. On 30.10.2017 registered letter sent by applicant Sh. Ramkumar was received by tribunal which was taken on record. The content of the letter says that all the parties of the case have entered into compromise & there is no outstanding dispute between the parties which is required to be settled & applicant does not want to pursue the matter further hence, further proceeding in the matter may be dropped. The letter has been attached with photocopy of an undated compromise.

6. On 16.11.2017 applicant Sh. Ramkumar personally appeared. Sh. Sunil Kumar Pareek appeared on behalf of non-applicant. Sh. Ramkumar applicant was identified by Sh. Sunil Kumar Pareek. Both applicant & Sh. Sunil Kumar Pareek on behalf of non-applicant filed undated original compromise which was taken on record. Content of the compromise was read over & explained to both the parties & they admitted to have entered into the compromise supporting the recitals of the compromise deed. Applicant Sh. Ramkumar further file an applicant to decide the case on

the basis of compromise. This application was endorsed by Sh. Sunil Kumar Pareek contending that he is not having any objection in disposal of the matter as alleged by Sh. Ramkumar. Accordingly, matter was fixed for disposal of the case in Lok-Adalat on 28.11.2017.

7. The application of the applicant Sh. Ramkumar dated 16.11.2017 to dispose the case on the basis of compromise & compromise filed on 16.11.17 read as under:-

श्रीमान् न्यायालय केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, जयपुर

मु. संख्या 23/2017

ता. पे. 16.11.2017

रामकुमार बनाम मै. नेयवेली लिग्नाइट का. लि.

श्रीमानजी,

उक्त उनवान शीर्षक प्रकरण में आज दि: 16.11.2017 को तारीख पेशी नियत है। निवेदन है कि प्रकरण में प्रतिपक्ष सं. 1 व 2 व प्रतिपक्षी सं. 3 के बीच में आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है तथा निस्तारण योग्य कोई विवाद शेष नहीं है। राजीनामे की प्रति संलग्न है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि मैं रामकुमार प्रतिपक्षी सं. 3 आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता न ही कोई क्लेम चाहता हूँ।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रकरण में राजीनामा हो जाने के आधार पर मामले को निस्तारित कर आदेश फरमाया जावे।

दि: 16.11.2017

प्रार्थी

उपरोक्त प्रकार से मामले  
के निस्तारण से मैं  
पूर्णतया सहमत हूँ।

हस्ताक्षर पठनीय  
रामकुमार पुत्र श्री हनुमान प्रसाद  
जाति सारस्वत निवासी  
बिन्नाणी चौक बीकानेर  
Identified Mr. Ram kumar  
हस्ताक्षर अपठनीय

हस्ताक्षर अपठनी

(S.K. Pareek)

(S.K. Pareek/NLCIL)

NLC IL on behalf of Project Head / NLC IL

#### संलग्नक - 1

#### राजीनामा

- (1) रामकुमार पुत्र श्री हनुमान प्रसाद सारस्वत, जाति-सारस्वत  
निवासी बिनाणी चौक, बीकानेर, हाल डी-608,  
मुरलीधर व्यास नगर बीकानेर .....प्रथम पक्ष
- (1) प्रोजेक्ट हेड, नेयवेली लिग्नाइट को. लि., बरसिंहसर,  
तहसील व जिला-बीकानेर
- (2) बिहारीलाल, प्रोपराईटर, मिठा इन्टरप्राइजेज, बीकानेर रोड,  
सूरतगढ़, जिला- श्रीगंगानगर .....द्वितीय पक्ष

यह राजीनामा उभय पक्षों द्वारा आज दिनांक 9.6.2017 को निष्पादित किया जा रहा है।

1. यह कि प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के यहां विधुत सुपरवाइजर के पद पर सेवारत रहा है जिसको छंटनी के दौरान पद मुक्त करने को लेकर दोनों पक्षकारों के मध्य विवाद रहा है। उक्त विवाद को लेकर प्रथम पक्ष के द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के समक्ष परिवेदन पेश किया गया था जिसका निर्णय दिनांक 24.01.2017 को पारित किया जा चुका है।
2. यह कि दोनों पक्षकारान के मध्य प्रोजेक्ट हेड व कोरपोरेशन के अधिकारियों के द्वारा मध्यस्थता व वार्ता के परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया है।
3. यह कि प्रथम पक्ष की छंटनी बाबत द्वितीय पक्षकारान ने प्रतिकर (मुआवजा) राशि प्रथम पक्ष को अदा कर दी गयी है जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सभी कानूनी व न्यायिक कार्यवाही द्वाप कर देगा व पूर्व के विवाद सम्बन्धित कोई कार्यवाही नहीं करेगा।
4. यह कि प्रथम पक्ष वर्तमान में द्वितीय पक्ष (नेयवेली लिग्नाइट को. लि.) में कार्यरत है जिसको पूर्व के विवाद को लेकर तंग व परेशान नहीं किया जायेगा।

5. यह कि उक्त राजीनामा कि सभी शर्तों से दोनों पक्ष पाबंद रहेंगे।

उपरोक्त राजीनामा दोनों पक्षों द्वारा राजी खुशी व स्वतन्त्र सहमति से निष्पादित किया गया है।

निष्पादनकर्ता

हस्ताक्षर पठनीय

(1) (रामकुमार)

प्रथम पक्ष

(1) हस्ताक्षर अपठनीय (गोल रबर सील विपक्षी)

(2) हस्ताक्षर अपठनीय

रबर स्टैम्प (मिढ़ा इन्टरप्राइजेज)

द्वितीय पक्षकार

8. On 28.11.17 in Lok-Adalat case was taken up for disposal on the basis of application dated 16.11.17 to dispose the case on the basis of compromise filed by them. None appeared from either side in the Lok-Adalat on 28.11.17, however, the case was disposed on the basis of compromise allowing the application of the parties to dispose the case on the basis of compromise. The order passed in Lok-Adalat on 28.11.17 is read as under:-

28.11.2017

**लोक अदालत**

पत्रावली आज लोक अदालत में प्रस्तुत हुई। पुकार की गयी। पक्षकार अनुपस्थित है। सुलहनामा के आधार पर मुकदमें को निस्तारित करने की आवेदन दिनांकित 16.11.17 का अवलोकन किया।

पक्षकारों द्वारा सुलहनामों की तसदीक दिनांक 16.11.17 को की जा चुकी है, अतः पक्षकारों की सुलहनामा के आधार पर मामले को निस्तारित करने की आवेदन स्वीकार की जाती है। इस मामले को पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सुलहनामा दिनांकित 16.11.17 के आधार पर निस्तारित किया जाता है। संलग्नक-1 सुलहनामा एवार्ड का अंश होगा।

हस्ताक्षर अपठनीय

पीठासीन अधिकारी

9. Award as above.

BHARAT PANDEY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2018

**का.आ. 84.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स बी.सी. सी.एल. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. 1, धनबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 05/1998) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 08.01.2018 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/400/1996-आईआर (सी-1)]

एम. के. सिंह, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 9th January, 2018

**S.O. 84.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Dhanbad (Ref. No. 05 of 1998) as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. BCCL and their workmen, which was received by the Central Government on 08.01.2018.

[No. L-20012/400/1996-IR (C-I)]

M. K. SINGH, Section Officer

**ANNEXURE****BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD**

In the matter of reference U/S 10 (1) (d) (2A) of I.D. Act, 1947

**Reference : No. 05/1998**

Employer in relation to the management of Govindpur Area of M/s. BCCL

**AND**

Their workman

**Present :** Shri R. K. Saran, Presiding Officer**Appearances:**

For the Employers : None

For the workman : None

State : Jharkhand

Industry : Coal

Dated- 16.11.2017

**AWARD**

By order No. L-20012/400/1996-IR(C-I) dated 31.12.1997 the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 referred the following dispute for adjudication to this Tribunal:

**SCHEDULE**

**“Whether the action of the management of Govindpur Area of M/s. BCCL in dismissing Sh. Baldeo Das, Miner/Loader w.e.f. 06/08/1993 is justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled?”**

2. After receipt of the reference, both parties are noticed. But appearing for certain dates none appears subsequently. Case remains pending. It is felt that the disputes between the parties have been resolved in the meantime. Hence No Dispute Award is passed. Communicate.

R. K. SARAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2018

**का.आ. 85.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स बी.सी. सी.एल. के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. 1, धनबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 25/2010) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 29.12.2017 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/101/2009-आईआर (सीएम-1)]

एम. के. सिंह, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 9th January, 2018

**S.O. 85.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Dhanbad (Ref. No. 25 of 2010) as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. BCCL and their workmen, which was received by the Central Government on 29.12.2017.

[No. L-20012/101/2009-IR (CM-I)]

M. K. SINGH, Section Officer

**ANNEXURE****BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD**

In the matter of reference U/S 10 (1) (d) (2A) of I.D. Act, 1947

**Reference No. 25 of 2010**

Employer in relation to the management of C.V. Area of M/s. BCCL

**AND**

Their workman

**Present :** Shri R. K. Saran, Presiding Officer**Appearances:**

For the Employers : Shri S.N.Ghosh, Advocate

For the workman : Shri R.R. Ram, Rep.

State : Jharkhand

Industry : Coal

Dated- 6.12.2017

**AWARD**

By order No.-L-20012/101/2009 IR-(CM-I), dated.19.02.2010 the Central Govt. in the Ministry of Labour has, in exercise of powers conferred by clause (d) of Sub-Section (1) and Sub-Section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act.1947, referred the following disputes for adjudication to this Tribunal:

**SCHEDULE**

**“Whether the action of the management of Basantimata Colliery under C.V.Area of M/s. BCCL in dismissing Shri Khiru Bhuia UG Loader from the service of the company is justified and legal? To what relief is the workman concerned entitled ?”**

2. The case is received from the Ministry of Labour on 08.03.2010. After receipt of reference , both parties are noticed, but after long delay the Sponsoring Union files their written statement on 15.05.2017. And the management files their written statement -cum-rejoinder on 03.08.2017. The point involved in the reference is that the workman has been dismissed from his services on 12.08.2005.
3. During preliminary hearing of this case, domestic enquiry held by the management is accepted by the Sponsoring Union/workman as Fair & Proper .
4. The point involved in the reference is that the workman has been dismissed from his services on the ground of long absence. But he has already out of service since last 12 years. It is felt to give another chance to the workman concerned to serve.
5. Considering the facts and circumstances of this case, I hold that he be taken into job as a fresh employee in cat-I. But the workman be kept under probation for a period of two year. Therefore the question of back wages does not arise at all.

This is my award.

R. K. SARAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2018

**का.आ. 86.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स बी.सी. सी.एल. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. 2, धनबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 30/2016) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 11.12.2017 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/164/2015-आईआर (सीएम-I)]

एम. के. सिंह, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 9th January, 2018

**S.O. 86.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 2, Dhanbad (Ref. No. 30 of 2016) as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. BCCL and their workmen, which was received by the Central Government on 11.12.2017.

[No. L-20012/164/2015-IR (CM-I)]

M. K. SINGH, Section Officer



**ANNEXURE****BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO.2), AT DHANBAD****PRESENT : Shri R.K.Saran, Presiding Officer**

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1) (d) of the I.D. Act, 1947

**REFERENCE No. 30 OF 2016**

**PARTIES :** The Secretary,  
Janta Mazdoor Sangh,  
Old Rajagarh, Bakri Hat,, PO: Jharia,; Dhanbad-828111

**Vs.**

The General Manager,  
Kusunda Area of M/s. BCCL,  
P.O. Kusunda,, Distt: Dhanbad.828116.

**Order No. L-20012/164/2015-IR(CM-I) dt. 10.02.2016****APPEARANCES :**

On behalf of the workman/Union : Mr.Vivek Kumar Ld. Representative

n behalf of the Management : Mr.Gopal Tiwari Management Representative

State : Jharkhand

Industry : Coal

Dated, Dhanbad, the 27<sup>th</sup> October, 2017**AWARD**

The Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Sec.10(1)(d) of the I.D. Act.,1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No.L-20012/164/2015-IR(CM-I) dt. 10.02.2016.

**SCHEDULE**

**Whether the action of the Management of Burragarh Colliery under P.B. Area of M/s BCCL in dismissing Sri Chandradeo, M/Loader vide letter dated 27.12.2002 is fair and justified? To what relief the concerned workman is entitled to**

On receipt of the Order No. **L-20012/164/2015-IR(CM-I) dt. 10.02.2016** mentioned reference from the Government of India, Ministry of Labour & Employment, New Delhi for adjudication of the dispute, the Reference Case No. 30 of 2016 was registered on 04.03.2016 and accordingly an order to that effect was passed to issue notices through the Registered Posts to the parties concerned, directing them to appear in the Court on the date fixed, and to file their written statements along with the relevant documents. In pursuance of the said order, notices by the Registered Posts were sent to the parties concerned.

Both the parties made their appearances and filed their pleadings and photocopies of their documents. The Union and the O.P./Management through their own Representatives respectively appeared, and contested the case to the extent the case was reserved for Award.

2. This Reference case of all about of workman Sri Chndadeo Singh a permanent employee of Burragarh Colliery under P.B. Area of M/s. BCCL being his Pers. No 02983146 was posted as M/Loader in the Colliery. The workman had been successful in keeping his unblemished service track record, very sincere and efficient in the Company till he had proceeded his native place on some emergence work since 03.01.2002 with prior information from the Management .After having returned from the native place when he went to join duty the Management abruptly came out the dismissal letter and handed it over to the workman citing unauthorized absence as reason behind it. Though prior to dismissal, there was no knowledge the workman had about any charge sheet and the enquiry notices whatsoever ever sent to the delinquent workman but the alleged order/ Notices itself contained all about at lengths, he came across with dismissal letter. As per the principle of the natural justice equal opportunity is a pre-requisite condition to be provided to the delinquent workman against whom an enquiry is being constituted ,so long as Shri Chandradeo Singh, no such proceedings had been followed as stated in WS. Whereas it is a well settled law that before dismissal of anybody the enquiry proceedings as well as notice of enquiry should be made available to the charge sheeted workman, but in this case the Management neither did supply the enquiry proceedings nor did publish the enquiry in local daily which is mandatory. As workers are worst hit of all, though there is absolute unanimity on

the move doubting dismissal being beneficial in the long run to Industrial Relations so the dismissal for committing petty misconduct had shockingly a serious blow and disproportionate. The workman was worst hit being rubbed off his livelihood in days of hardship. The Management of P.B. Area in bluntly violating the rules & regulations and the principle of the Natural justice dismissed the workman Chandradeo Singh so the alleged act of the dismissal is unlawful unfair and unjustified and thus is liable to be set aside, as stated in WS.

3. Whereas categorically denying all the allegations brought in by the Sponsoring Union/petitioner, the Management argued by raising question over maintainability of Industrial Dispute either in law and facts as neither the Sponsoring Union nor the workman ever came up during these long span of time, i.e. thirteen years, with any explanations of maintaining deep rooted silence and, on that score the Reference does not qualify to stand as Industrial Dispute rather liable to be rejected. Management further asserted that the workman concerned started absenting from duty since 03.01.2002 unauthorizedly. Since the aforesaid conduct of the workman was a misconduct under clause 26.1.1 of the Certified Standing Order of the Management thereby he deserved for alleged charge-sheet issued on 17.1.2002. Against which the workman submitted his reply which did not found satisfactory at all prompting Management of setting up an Enquiry Committee under Enquiry Officer Sri B.R.Shukla the then Sr. Personnel Officer as Enquiry Officer to conduct the enquiry in accordance with principle of natural justice and to ascertain to the extent the workman committed misconduct, and to offer ample opportunity to the charge sheeted workman to defend himself but deliberately evading for appearance turned the enquiry to declare ex-parte. The findings of the said enquiry were also sent to the workman on his home address by Registered post. It is an extreme example of gross negligence on the part of the workman who later on turned habitual absentee that got rooted leading to his dismissal from service.

Since the workman concerned kept on indulging himself in absentism and turned it into habitual practice with no sign of abating in spite of full force with which the Management did its best not to let the efforts go in vain by slapping with stoppage of one SPRA in earlier occasion also on the same ground before resumption of duty. Thus, neither there was any short of violation of the principle of natural justice, nor did it get mired at any stage as alleged by the petitioner/Union rather the alleged action of dismissal against the workman stands as fair, legal and justified.

4. So long as in relation to Group of the Collieries under the Management of M/s BCCL, a part of the Coal India Ltd., cases like this seldom get significant where numerous cases on same footing might have been pouring in slowly but steadily and the matter never gets more complicated when the labour forces are involved. Moreover this is not a case of day one or two and has turned a regular feature for the years together because they are sometimes subjected to work beyond safety norms. The workmen mostly belonging to illiteracy back ground are usually scared of stepping into the underground Mines due to safety hazards and unhealthy conditions, surrendering in and around the site despite best of safety mechanism/technique in place. However safety related issues have never carved out a permanent niche in the hearts of workers. The Management and its set ups associated in such matter presents an added dimensions and have practice to ignore the move of the such loopholes vulnerable on slightest safety omissions. Workers of the colliery have early adopted safety norms and other safety platforms since they are simple, clean and accurate. Governments too have made every effort to stem usage of safety norms of latest technology in collaboration with their leading Institutions in a bid to facilitate accident free zone and to thwart accident or mishap.

There is nothing adverse report against the workman barring this one. Though alleged absentism had cost him employment. The punishment of dismissal imposed to the misconduct against the workman shielding under the name of penalty on ground of absentism appears to be disproportionate and a harsher to bear, and what needs above all, a fresh outlook in view of easing out of strain in Industrial relationship.

5. The workman concerned who was stripped of his livelihood, needs a little with breather, be provided one more opportunity by offering him fresh appointment in the lowest Grade with two- year probation. Therefore it is ordered that the worker concerned be appointed as fresher in the lowest Cat-I with two-year period on probation by detecting his actual date of birth with the Service Excerpt of the Colliery before providing employment, So long as back wages, it does not arise at all.

R. K. SARAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2018

**का.आ.** .—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स टिस्को लिमिटेड के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. 1, धनबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 53/1997) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 08.01.2018 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/476/1995-आईआर (सी-1)]

एम. के. सिंह, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 9th January, 2018

**S.O. 87.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Dhanbad (Ref. No. 53 of 1997) as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. TISCO Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 08.01.2018.

[No. L-20012/476/1995-IR (C-I)]

M. K. SINGH, Section Officer

**ANNEXURE****BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD**

In the matter of reference U/S 10 (1) (d) (2A) of I.D. Act, 1947

**Reference : No. 53/1997**

Employer in relation to the management of M/s. TISCO

**AND**

Their workman

**Present :** Shri R. K. Saran, Presiding Officer**Appearances:**

For the Employers : Shri D.K. Verma, Advocate

For the workman : None

State : Jharkhand

Industry : Coal

Dated- 15/11/2017

**AWARD**

By order No. L-20012/476/1995-IR(C-I) dated 11/02/1997 the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 referred the following dispute for adjudication to this Tribunal:

**SCHEDULE**

**“Whether the action of the management of M/S. TISCO in denial of employment to the dependent of workman Shri Basudeo Turi, SDL Crew, 6 & 7 Pits Colliery is justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled?”**

2. After receipt of the reference, both parties are noticed. But appearing for certain dates by the workman none appears subsequently. Case remains pending. It is felt that the disputes between the parties have been resolved in the meantime. Hence No Dispute Award is passed. Communicate.

R. K. SARAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2018

**का.आ. 88.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स ई.सी. एल. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. 1, धनबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 66/1992) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 29.12.2017 को प्राप्त हुआ था।

[ सं. एल-20012/225/1991-आईआर (सीम-1) ]

एम. के. सिंह, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 9th January, 2018

**S.O. 88.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1,

Dhanbad (Ref. No. 66 of 1992) as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. ECL and their workmen, which was received by the Central Government on 29.12.2017.

[No. L-20012/225/1991-IR (CM-I)]

M. K. SINGH, Section Officer

### ANNEXURE

#### BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of reference U/S 10 (1) (d) (2A) of I.D. Act, 1947

#### Reference : No. 66/1992

Employer in relation to the management of Kapasara Area of M/s. ECL

#### AND

Their workmen

**Present :** Shri R. K. Saran, Presiding Officer

#### Appearances:

For the Employers : Shri D.K. Verma, Advocate

For the workman : Shri D. Mukherjee, Advocate

State : Jharkhand

Industry : Coal

Dated- 4/12/2017

#### AWARD

By order no . L- 20012 /225/1991 /IR (CM-1) dated 06/ 08/1992, the Central Government in the Ministry of Labour has in exercise of the power conferred by clause (d) of sub – section ( 1) and sub – section ( 2A) of section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

#### SCHEDULE

**“Whether the demand of Colliery Mazdoor Sabha of India that S/Shri Radhashyam Banerjee and others 174 being the contract Labour are required to be regularised by the Eastern Coalfields Ltd in their establishment as well as these workers are also entitled for the benefits of NCWA-IV is justified? If not, to what relief the workmen concerned are entitled?”**

#### ANNEXURE

#### List of workmen

- |                             |                              |                               |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Sri Radha Shyam Banerjee | 2. Sri Sanat Kumar Das       | 3. Sri Babesh Chandra         |
| 4. Bhubneshwar Saw          | 5. Dhaneshwar Saw            | 6. Seo Prasad Saw             |
| 7. Raj Kumar Saw            | 8. Brahma Murari Mahato      | 9. Janta Pd. Ram              |
| 10. Sukumar Das             | 11. Ashok Kumar              | 12. Balai Chakraborty         |
| 13. Sh. Niranjana Ruj       | 14. Utpal Rai                | 15. Sukant Chatterjee         |
| 16. Kanai Lal Bandopadhyay  | 17. Uttam Kr. Chattopadhyay  | 18. Jaidev Chatterjee         |
| 19. Nirmal Bhattcharjee     | 20. Kartik Choudhary         | 21. Nirmal Chatterjee         |
| 22. Hital Nag               | 23. Dipankar Ghosh           | 24. Ashim Mallick             |
| 25. Rajesh Srivastav        | 26. Prayag Paswan            | 27. Goutam Banerjee           |
| 28. Asit Chatterjee         | 29. Rajnath Ram              | 30. Alok Kr. Chakravorty      |
| 31. Asim Chakravorty        | 32. Ram Krishna Bhattcharjee | 33. Krishna Chandra Mukherjee |
| 34. Yusuf Hasan             | 35. Tapas Chandra Ghoshal    | 36. Tapan Kumar Mukherjee     |
| 37. Pritish Chakravorty     | 38. Salim Kr. Ghoshal        | 39. Khoku/Murli Ram Bouri     |
| 40. Satish Choudhary        | 41. B. Madhushudan           | 42. Pramod Choudhary          |

43. Anil Kumar	44. Parmeshwar	45. Basant Chakravorty
46. Suresh Chatterjee	47. Sish Kumar	48. Gopal Bhandari
49. Ganpat Mahto	50. Basim Murtin	51. Tapan Kr. Dutta
52. Durga Karmakar	53. Raj Kumar Lohar	54. Ranjit Lohar
55. Basudeo Mandal	56. Basant Kr. Mondal	57. Mukul Mondal
58. Subhendu Mondal	59. Rohit Kr. Mondal	60. Subhash Mondal
61. Dasrath Chandra	62. Basant Kr. Das	63. Dilip Kr. Mahato
64. Anadi Prasad Mistri	65. Ramashish Prasad	66. Krishnandu Chatterjee
67. Kajal Kr. Dey	68. Alok Banerjee	69. Kalyan Kumar Ghosal
70. Ashok Kr. Ganguly	71. Pradip Chakraborty	72. Sandip Chakraborty
73. Partha Banerjee	74. Dulal Chatterjee	75. Harsha Mazumdar
76. Ashok Kr. Chakraborty	77. Jagbandhu Banerjee	78. Dilip Kr. Roy
79. Hari Krishna Dey	80. Ravindra Nath Saha	81. Ajay Kr. Jha
82. Ashok Kr. Singh	83. Madhai Rawani	84. Bhabhotosh Bouri
85. Somnath Mukherjee	86. Probir Kumar	87. Kartik ch. Bandhopadhyay
88. Tarak Nath Chattopadhyay	89. Gunomoy Bandhopadhyay	90. Surya Roy
91. Ajit Kumar Sinha	92. Ranjit Lohar	93. Dhiren Roy
94. Anjay roy	95. Naresh Pd. Saw	96. Ganesh Chandra Gourai
97. Sasti Badyakar	98. Ashish Chandra Mallick	99. Mirinmoy Saha
100. Sadhan Pal	101. Saffiuddin Ansari	102. Subhamay Chakarvorty
103. Arvind Kumar Rawani	104. Sanjay Kr. Das Gupta	105. Parmanand Nayak
106. Pradut Kumar Das	107. Md. Salim Ansari	108. Md. Kalim Ansari
109. Mohammad Allauddin	110. Mohammed Halim Ansari	111. Subhash Kr. Dutta
112. Birendra Kr. Singh	113. Anil Kr. Singh	114. Sudam Prasad Singh
115. Ram Sanmukh singh	116. Sudhir Kr. Singh	117. Randhir Kr. Singh
118. Triloki Pandey	119. Rajiv Kumar	120. Ranjit Kr. Dutta
121. Prakash Mitra	122. Anup Mitra	123. Asit Mondal
124. Siddhanath Nirala	125. Swapn Chakravorty	126. Addyamay Dasgupta
127. Bishwanath Dasgupta	128. Madhu Bakshi	129. Salim Ansari
130. Rakesh Kr. Sinha	131. Shital Chandra Ganguly	132. Rajen Kr. Saw
133. Uday Kr. Saw	134. Suresh Kumar	135. Sadanand Bouri
136. Dip Narayan Bouri	137. Basudeo Mondal	138. Janardan Kumar
139. Narendra Pd. Singh	140. R. B. Barat	141. Ashok Kr. Singh
142. Dipak Kumar	143. Baijnath Prasad	144. Ajit Kumar Singh
145. Surendra Kr. Singh	146. Algu Ram	147. Surendra Kr. Singh
148. Manoj Kr. Singh	149. Indu Bhushan Singh	150. Rabi Shankar singh
151. Kamleshwar Upadhyay	152. Binay Kr. Singh	153. Narendra Singh
154. Ajay Singh	155. Sant lal Choudhary	156. Sunil Kr. Singh
157. Prakash Chandra Singh	158. Raj Kumar Singh	159. Ranjit Singh
160. Nagendra Pd. Singh	161. Jitendra Kumar Singh	162. Binay Kr. Upadhyay

163. Manoj Kr. Singh	164. Kailash Singh	165. Surendra Ram
166. Buchkum Singh	167. Shiv Nath Banerjee	168. Gopal Singh
169. Asim Banerjee	170. Dinesh Yadav	171. . Bijay Manjhi
172. Himanshu Chakraborty	173. Shyam Sundar Roy	174. Manas Mukherjee
175. Manas Chandra Gorai		

2. The case is received from Ministry of Labour on 12.08.1992. The Sponsoring Union files their written statement on 01.10.1992. But after long delay the management files their written statement on 23.02.2000. Thereafter rejoinder and document filed by the parties. Three witnesses examined on behalf of the Sponsoring Union as well as two witness examined on behalf of the management. Documents of the management marked as M-1 to M-1/2 but no document marked by the workman.

3. The case of the Sponsoring Union is that the management of Kapasara Area of M/S ECL which is a public Sector Enterprises have employed contract labour in their works for raising of Coal and overburden removal of earth cutting, stone cutting and loading and unloading through hired heavy earth moving machineries are deployed through the above contract Labour.

4. It is further submitted by the Sponsoring Union is that the above action of the management of Kapasara Area of M/S BCCL in their deployment of their workmen as contract Labour is a cloak for suppressing the facts that these workmen under contract Labour were really the workmen of the management concerned. In order to deprive them from the status of direct employment of the management and thereby to deny them the proper wages as stipulated and prescribed for them in the NCWA- III & IV.

5. It is further submitted by the sponsoring union that since these workmen under the said contract labour were receiving less wages even than an unskilled workman on the muster Roll of the management, and they were not having paid any other benefits and emenities like provident fund, Gratuity, bonus, Privilage leave etc, they made regular representation for their regularisation as the direct workmen of the said management which were of no avail. The union also took up the case of these workmen for their regularisation as direct workman of the said management in consideration of their continous employments as such so that they could get even the minium wages as prescribed for similar nature of jobs performed by the regular workmen on the muster roll of the management. To which the management turned a deaf ear.

6. On the other hand the case of the management is that there is no valid Industrial dispute in the present case in the eye of law or within the meaning of section 2 K of the I.D Act. The said persons do not come under the defination of sec 2 (K) of I.D.Act . As a matter of fact there is no dispute and the same is fit to be dismissed. As the reference order is vague and suffers from the vice of total non application of mind by the Govt. and it is therefore vitiated the particulars of the persons & details thereof are also lacking . A vague reference order is no reference order and is rendered null & void.

7. It is further submits that the management specifically clerarly and categorically states and submits that none of the persons named in the list have ever been engaged by the management.

8. It is stated by the management that the persons allotted work through open tender to supply such small number of persons for a timited period to meet the exigency of work. It is respectfully submitted that the persons who supplies such persons for a limited period is paid agreed amount of the work. The method of recruitment, the conditions of service , the scale of pay & conduct Rules regulating the service conditions are governed by the statutes laid down therein . It is settled principle of law that the employees of the management are workmen under the I.D Act.

9. It is further submitted by the management that the petitioner have wrongly stated that the persons working under the contract system are required to work under the management. And the management has its own regular employee and the work through the contractor is taken casually whenever required & the same is not continuous.

10. It is further submitted by the management that it is wholly based on misrepresentation and it represent deliberate bid to exploit this organisation and to induct into employment illegally some outsiders through back door method. Such prayer is also without any substance or merit quit apart from inherent legal and infirmities in the reference order itself. The prayer of the so-called union is therefore lable to be rejected.

11. This is the case of regularisation of 175 workmen . The case of the workmen is that they were engaged under the management, as coal cutter in the mines. Through contractor.

12. The dispute of regularisation was raised, more than twentyfive years ago. During that time, reference received written statement and counter filed. Evidence of the parties also recorded long back. Purused the evidence, the

workman stated that they were contract worker under Khalsa Brothers. But the contractor has not been examined in the case nor the contractor identified any of the workmen.

13. In the meantime 25 years or more elapsed. It is not known as to how many workmen now alive and how many persons crossed the age of 60 years i.e the age of superannuation. As per evidence of WW-1 he say that he was working from 1982. In 1995 the witness of WW-2 Sri Asim Kr. Banerjee is 41 years old it means now he was 63 years old.

14. On purusal of the case it is found that No Identity Card, age proof, Pay slip etc filed in this case. Since the concerned workman are not identified at this stage, this Tribunal constrained to pass award infavour of the workman. Therefore the Tribunal is not in a position to regularise the workmen due to want of identification of the workmen. Upon this one judgment of constitution Bench of Hon'ble Supreme Court rendered in case of **SAIL- Vs National Union Waterfront Workers reported in (2001) 7 SCC-1** says that the engagement of the contractor in the instant work was not prohibited category of work.

15. Considering the facts and circumstance of this case, I hold that the demand of Colliery Mazdoor Sabha of India that S/Shri Radhashyam Banderjee and others 174 being the contract Labour are required to be regularised by the Eastern Coalfields Ltd in their establishment as well as these workers are also entitled for the benefits of NCWA-IV is not justified. Hence they were not entitled to get any relief.

This is my award.

R. K. SARAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2018

**का.आ. 89.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स इंडियन एयरलाइंस के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. 1, दिल्ली के पंचाट (संदर्भ संख्या 275/2011) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21.12.2017 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-11012/59/2000-आईआर (सी-I)]

एम. के. सिंह, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 9th January, 2018

**S.O. 89.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, New Delhi (Ref. No. 275 of 2011) as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Indian Airlines and their workmen, which was received by the Central Government on 21.12.2017.

[No. L-11012/59/2000-IR (C-I)]

M. K. SINGH, Section Officer

#### ANNEXURE

**BEFORE PRESIDING OFFICER: CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT No. 1: ROOM No. 511, DWARKA COURT COMPLEX, SECTOR 10, DWARKA, DELHI – 110 075**

**ID No. 275/2011**

Smt. Kulbir Bedi,  
59/124, Ajit Nagar, VIP Road,  
Agra, Uttar Pradesh 282 001

...Workman

#### Versus

The General Manager (IR),  
Indian Airlines .  
IGI Airport,  
New Delhi

...Management

### AWARD

In the present case a reference was received vide letter No.L.11012/59/2000 (C-I) dated 29.08.2000 under clause (d) of sub-section (1) and Section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (in short the Act) for adjudication of an industrial disputes, terms of which are as under:

Whether the action of the management of Indian Airlines, Northern Region, New Delhi in terminating the services of Mrs. Kulbir Bedi, Air Hostess with effect from 07.02.1995 is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled?

2. Thereafter, a corrigendum was received vide letter No.11012/59/2000-IR(C-I) dated 19.01.2015, wherein the date of termination of the workman was to be read as '12.03.1996' instead of '07.02.1995'.

3. Brief facts giving rise to the present case are that Smt. Kulbir Bedi (hereinafter referred to as the claimant) was appointed as Air Hostess with Indian Airlines (hereinafter referred to as the management) with effect from 01.11.1976. She has been discharging her duties sincerely and diligently and there was no complaint against her at any time and the claimant had not availed any kind of leave except as authorized under the law and never remained absent from her duties in an unauthorized manner.

4. It is alleged in para 3 of the statement of claim that she fell sick on 06.09.1993 and was examined by panel doctor of the management. She was advised complete bed rest by the doctor and intimation in this regard was sent by way of an application, alongwith the medical certificate, to the Operations department of the management, in which the claimant was working. Her salary was later on sanctioned by the management. The claimant was advised further medical rest and she from time to time sent requisite applications supported by medical certificates for sanction of her leave but the management did not convey any sanction of leave for reasons best known to them despite the fact that medical certificate was also furnished to the management. It is further alleged that on 27.02.1994 the aged mother of the claimant who was living with her expired and the claimant was under a social obligation to perform her last rites. When the claimant was declared fit, she reported for duties in 1994 but was not allowed to join duties on the pretext that some disciplinary proceedings were being initiated against her. No show cause notice or memo was served on her. She again on 07.02.1995 reported for duties but she was intimated that her services have been terminated and an attempt was also made to hand over a cheque of Rs.7439.55 towards the alleged dues, which were not received by the claimant earlier. No letter of termination of service was served upon the claimant. Thereafter the claimant made a representation to the various authorities. She was highly mentally disturbed and due to family circumstances there was nobody to look after her small children.

5. Thereafter, claimant received a notice from National Industrial Tribunal regarding approval of her application NTB 16 of 96 dated 05.06.1996. The claimant also filed reply to the said application under Section 33-2 of the Act and she has objected for grant of approval of the said application of the management. However, the Tribunal vide letter order dated 04.11.1996 while granting approval to the application of the management also permitted the claimant to raise appropriate industrial dispute before the appropriate authority. Thereafter, she represented to the management and conciliation also took place between the parties which virtually failed and finally reference was received in the manner stated above from the appropriate Government for adjudication of the present dispute.

6. Claim was contested by the management who filed reply thereto wherein certain preliminary objections were taken. However, it was admitted that the claimant herein was removed from service vide memo dated 12.03.1996 and appropriate Government has made reference presuming termination of the claimant from service with effect from 07.02.1995. The claimant was absent from duties with effect from 06.05.1993 on the pretext of being sick and on 06.09.1993, as stated in the statement of claimant. However, she did not get any leave sanctioned in accordance with the relevant rules and regulations and thereafter her absence from duty which was irregular and without any sufficient explanation was treated as misconduct. She has filed fake medical certificates. She was also asked by the management to appear before the medical officer of the management but she did not comply with the directions. She was also charge sheeted in terms of charge sheet dated 22.12.1993/10.01.1994 Ex.MW5/12. Claimant has not sent any reply to the charge sheet nor participate in the domestic enquiry. Thereafter, ex-parte enquiry was conducted against the claimant. Claimant was duly informed vide memo dated 29.07.1993 that the medical certificate furnished by her has not been accepted by the management. Resultantly, on the basis of enquiry conducted by the Enquiry Officer, claimant herein was removed from service and a cheque of Rs.7439.55 pertaining to her past arrears/dues was handed over to her.

7. Vide letter no.Z-22019/6/2007-IR-(C-II) dated 22.12.2008, the case was transferred to CGIT cum Labour Court No.II, New Delhi for adjudication. Again vide order No.Z-22019/6/2007-IR(C-II) dated 30.03.2010 transferred the case back to this Tribunal for adjudication.

8. Against this factual background, my learned predecessor vide order dated 13.04.2009, framed the following preliminary issue:



‘Whether the enquiry conducted by the management is just, fair and legal?’. If not, what orders have to be passed in the case?’

9. Record also shows that additional issues were also framed on 08.09.2011, as under:

- (i) Whether punishment dismissal commensurate to the misconduct of the claimant?
- (ii) In terms of reference
- (iii) Relief

10. Both parties adduced evidence on the preliminary issue and it is clear from the record that this Tribunal vide order dated 07.02.2013 held that the enquiry conducted by the management is not legal and fair and the same is in violation of principles of natural justice. It was also observed that the documents filed by the management have also not been proved during the enquiry before this Tribunal. Resultantly, this issue was decided in favour of the claimant and against the management.

11. Thereafter opportunity was granted to the management to adduce evidence afresh on the charge sheet/misconduct committed by the claimant. Thereafter, management examined Ms. Prabha Devi, Dr. Kirti Suri Verma and Shri Rajesh Seth, whose affidavits are Ex.MW3/A, Ex.MW4/A and Ex.MW5/A respectively. All these witnesses have tendered in evidence various documents and I would be referring to these documents while drawing my conclusions. Claimant in order to rebut the case of the management examined herself as WW1 whose affidavit is Ex.WW1/B and also tendered in evidence certain documents.

#### **Finding of Additional Issue No. (i), (ii) and (iii)**

12. All these issues are being taken up together for the purpose of discussion as they are interrelated and can be conveniently disposed of. Before I proceed to consider the comparative merits of the submissions made on behalf of either of the parties, it is necessary to delineate the charges mentioned in the charge sheet Ex.MW5/12 (also marked as Ex.MW1/1) and the same is as under:

‘You reported sick on 06.05.1993 and since then you have neither reported back for duties nor sent any intimation in regard to your sickness. You were advised by OM vide his letters dated 12.07.1993 and 29.07.1993 to report back for duties and advised to see the IA Medical Officer which you failed to do so. You were also advised by IM’s letters dated 12.09.1993 and 06.10.1993 that medical certificates submitted by you have not been accepted by our IA Medical officer, therefore, advised to see the IA Medical Officer, failing which disciplinary action will be initiated against you. However, you failed to do so.

You are, therefore, absenting unauthorizedly with effect from 06.05.1993.

The above, if proved, would constitute an act of misconduct under the Standing Orders applicable to you, such as:

Clause 16(6)      Absence without leave for more than 8 consecutive days or overstaying the sanctioned leave without sufficient grounds or proper or satisfactory explanation within a week from the date of termination of leave sanctioned.

Clause 16(8)      Breach of any Standing Order or any law or rules applicable to the establishment.

13. Evidence of the management regarding proof of misconduct is testimony of MW3 and that of MW5. It is clear from the overall examination of the charge sheet that the case of the management is primarily based upon the allegation that the claimant herein has remained absent from duties without any sanction of leave and the so called medical certificates filed by the claimant as proof of her illness were fake documents so as to avail leave. Admittedly onus of proof of unauthorized absence of the claimant from duties is upon the management who is required to adduce cogent and reliable evidence to prove the said charges against the claimant who has also furnished various documents in the form of applications as well as medical certificates so as to show that she was really suffering from illness.

14. It is further clear that the claimant has reported sick on 06.09.1993 and case of the management is that no intimation was sent by the claimant to the management regarding her sickness and she was asked vide letter dated 12.07.1993 and 19.07.1994 to report back for duties. However, she has submitted medical certificate which were not accepted by the medical officer of the management.

15. It is also necessary to point out here that when domestic enquiry has been held by the Tribunal to be unfair and against the principles of natural justice, in that eventuality management is required to adduce fresh evidence so as to prove charges of misconduct against an employee. Hon’ble Apex Court in the case of Neeta Kaplish vs. Presiding Officer (1999) Lab.IC 44 while considering the question of power of Labour Court to permit adducing fresh evidence held that under section 11-A of the Act when opportunity has been availed by the management to adduce evidence on

the charges of misconduct made against an employee, in that eventuality, evidence recorded during the course of domestic enquiry or record pertaining to domestic enquiry would not constitute fresh evidence as all these documents have been found by the labour court to be defective and such record would also not constitute 'material on record' within the meaning of Section 11A of the Act as the enquiry proceedings have now been ignored altogether.

16. Management examined Ms. Prabha Rani as MW3 who has stated that she was working in the Operations Department where the claimant was earlier serving from 1993 to 96. She was working as Deputy Chief Airhostess with the management and the claimant Ms. Kulbir Bedi was working under her supervision. She has also conversant with the signature and handwriting of the claimant. She is not aware as to who was the Operations Manager in the year 1993 and she is not competent to recommend disciplinary action against the claimant. She has further deposed that airhostesses have to report for duties as and when she has to fly and she had to remain standby at her residence also as in case of emergency she may be called for duties. She has deposed that the claimant has submitted leave application in 1993 and her leave record for the year 1993 was in her possession, copy of which is Ex.MW3/W1. As per this document, claimant remained on sick leave for the period 06.05.1993 to 30.09.1995. She has further deposed to a court question that no leave in the period mentioned above was sanctioned in favour of the claimant, as such, she was on unauthorized absence. However, she has clarified that the claimant has been sending leave applications supported by medical certificates. Management has also doctors who attended to the employees, but she did not recollect whether Dr. Aruna Chaudhary was one of such doctors on the panel of the management. She has further stated in her cross examination that here medical certificate was considered by the management and her medical certificate was considered by the management and her leave application was refused. However, she had not brought the record pertaining to refusal of the leave application of the relevant period for the year 1992 to 1994 as well as list of panel of doctors. She has further clarified that she is not aware as to how letter Ex.MW3/13 was sent to the claimant as matter is more than 20 years old. She has denied Ex.ME3/2 to Ex.MW3/7 are fabricated documents. Ex.MW3/2 is letter dated 07.05.1993 written by Manager Operations and copy of the same is alleged to have been sent to Ms. Kulbir Bedi, the claimant herein. Similarly Ex.MW3/5 dated 26.08.1993 is written by Operations Manager to Operations IANR(D) which contains details of medical certificates sent by the claimant to the management. This letter again shows that the medical certificate in fact was sent by the claimant regarding her illness in the year 1993 to the management. Otherwise, there would not have been such specific mention of the same in this letter. Ex.MW3/6 is also regarding medical certificate in respect of claimant Ms. Kulbir Bedi and the same is issued by Dr. Aruna Chaudhary. This again shows that the claimant was sick from September 93 to 18.09.1993. There is another document Ex.MW3/7 filed by the management regarding fitness of the claimant.

17. MW4 Ms. Kirti Suri Verma was Senior Manager during the year 1992-95 in Indian Airlines. She has tried to prove various documents issued under her signatures. She has admitted that there were more than 100 doctors on the panel meant for treatment of regular employees and employees were supposed to visit the doctors on the panel for the treatment. However, she was not in a position to produce the panel of doctors of the relevant period who were engaged for the medical examination of the regular employees. She has clarified that Dr. Aruna Chaudhary was not competent for long term treatment. However, she has competent to treat for short term treatment. The witness has not shown any document as to how Dr. Aruna Chaudhary was not competent and empanelled to provide long term treatment for ailments. She was also given time by the court to produce original of specialized doctors for treatment of its regular employees who are suffering from such illness. However, she was not in a position to produce any record. She has admitted that the claimant never appeared before her. She has made remarks on the backside of the medical certificate Ex.MW4/W1 who appeared before her. She is also not aware whether the department has sent this communication to the claimant or not as the doctors do not directly deal with the employees. She further could not recall whether after 02.02.1993 she examined the medical certificates of the claimant or not. The claimant was informed to report as per submission of this witness vide Ex.MW3/3. However, she has admitted that Ex.MW3/3 does not mention that her medical certificates have been rejected for want of supporting documents. Moreover, evidence on record regarding this communication was not sent to the claimant by the management.

18. MW5 Shri Sanjiv Seth has also tried to support the case of the management. His deposition is broadly based on official record. He has admitted that Ex.MW1/1 letter Ex.MW5/5, Ex.MW3/6, letter Ex.MW5/7 and Ex.MW5/6 were never sent to the claimant. He has further deposed that Ex.MW5/4 was not sent through post to the claimant and the same was placed in the pigeon hole/locker. He further admitted that the claimant was on sick leave with effect from 07.05.1993. A bare perusal of Ex.MW5/4 would show that Operations Manager has clearly mentioned that period of sick leave from 29.11.1992 to 06.01.1993 and 05.10.1993 to 23.11.1993 to be treated as leave on loss of pay. However, it is clear from the testimony of this witness that these letters were never sent/conveyed to the claimant. It is further clear from the statement of Shri Seth MW5 that there is no proof of dispatch of any of the letters mentioned above and competent authority in respect of the claimant herein was Operations Management, as is clear from Standing Orders Ex.MW5/16. He also stated that Ex.MW5/9 that the claimant Ms. Kulbir Bedi has signed the medical certificate issued by Dr. Aruna Chaudhary, Dr. Vijay Verma and Shri Vijay Mehta as proof of her illness. There is nothing on record to show that the management had rejected the aforesaid medical certificates submitted by the

claimant to the management as proof of her illness. No communication was sent to the claimant regarding rejection of these medical certificates by the competent authority, i.e Manager Operations.

19. At this stage, it is also appropriate to refer to the statement of MW1 Ms.Kulbir Bedi. She has filed a detailed affidavit Ex.WW1/B in support of the stand taken in her pleadings and she has made reference to the medical certificates Ex.WW1/1 to Ex/WW1/17. She has clearly deposed that she was on leave from 06.05.1993 to 26.02.1993 when her mother expired. She has also submitted various medical certificates to the management. She has specifically deposed that she never received Ex.MW5/9. She had communicated to the management in the prescribed form that she is sick from 06.05.1993. She has also furnished postal receipts regarding sending of medical certificates and other application when she reported sick and was advised medical rest by the doctors whereas management in the present case has not proved that any of the communication regarding rejection of her leave was either sent by post or in any other manner to the claimant. Letter Ex.MW5/5 dated 12.07.1993 was admittedly not sent to the claimant. Similarly, letter Ex.MW5/10 was also not sent to the claimant. Evidence regarding rejection of leave of the claimant and asking her to report for duties has not been proved by the management. In such circumstances, it cannot be said that the claimant was willfully and intentionally absenting from duties or that she was unauthorizedly absent from duties for the period mentioned above. The court cannot ignore the fact that the claimant has got herself examined by Dr. Aruna Chaudhary who is a competent doctor and on panel of the management, a fact which was not disputed even during the course of arguments and she was initially advised rest by her. Management could not cite any rules or regulations or show any document regarding panel of doctors from whom the claimant was legally required to get herself examined for long term treatment. Moreover, there is no positive evidence on record tht management has not accepted medical certificates Ex.MW4/1, Ex.MW4/2, Ex.MW4/3, Ex.MW4/4 and submitted by the claimants as proof of her illness. In fact, evidence is suggestive of the fact that no communication in this regard was sent to the claimant. Resultantly, absence of the claimant cannot be said to be willful or unauthorized when as per MW5 Shri Sanjeev Seth, she was on sick leave with effect from 07.05.1993. Even this was not conveyed to the claimant.

20. I have also gone through the various authorities relied upon by the management, i.e. Delhi Transport Corporation Vs. Sardar Singh (AIR (2004) SC 4161). It was a case of long term absence of a conductor who remained on leave for more than 272 days. Even in the domestic enquiry, he could not adduce any evidence so as to prove the case of his absence. It was against this background that Hon'ble Apex Court took a view that long term absence of such an employee is fatal. As such, his removal/dismissal from the job was held to be justified. In the case on hand, as discussed above, the claimant has admittedly applied for leave and medical certificate was also sent regarding her ailment by the claimant from time to time, which fact has also been admitted by the management. Moreover, management has nowhere conveyed to the claimant that her medical certificates have not been accepted. In such circumstances, there was no occasion for the claimant to be under the impression that she is on leave unauthorizedly, whereas in the case relied upon by the management, notice was sent to the claimant to join duties, to which he had not responded. This case relied upon is distinguishable and is not application to the controversy on hand.

21. Similarly, in the case of Delhi Transport Corporation Vs Narain Singh (MANU/DE/24143/2013), the workman was absent from duties and his absence was treated as leave without pay. However, later on also workman remained on unauthorized leave for very long period, which showed lack of interest of the workman in the job and he was found to be a habitual absentee. Workman in the said case even did not participate in the domestic enquiry, which was held ex-parte against him. Accordingly, he was held guilty of misconduct and order of 'removal from service' was passed against the workman. Since in the above case also, circumstances are clear that the workman, who was a conductor, remained absent for more than 211 days and he neither filed any reply to the charge sheet nor did he participate in the domestic enquiry. In such a situation, there was no escape from the conclusion that the workman was guilty.

22. As a sequel to the above discussion, it is held that the management has failed to prove that the claimant herein was willfully or unauthorizedly absent for the period mentioned in the charge sheet. As such, she is held to be not guilty of the misconduct under the law. As a necessary corollary, it is held that the action of the management of Indian Airlines, Northern Region in terminating the services of Ms.Kulbir Bedi, Air Hostess is totally illegal and unjustified. The claimant is entitled to full back wages till the date of her retirement, i.e. 31.08.2002 and she is also entitled to all the consequential benefits to which she was otherwise entitled had she been in the job till the date of her retirement i.e. 31.08.2012. Further, the claimant would be entitled to all retirral benefits. An award is, accordingly, passed. Let this award be sent to the appropriate Government, as required under Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, for publication.

Dated : December 13, 2017

A. C. DOGRA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2018

**का.आ. 90.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स बी.सी. सी.एल. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. 2, धनबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 108/2004) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10.01.2018 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/96/2004-आई.आर. (सी-1)]

एम. के. सिंह, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 10th January, 2018

**S.O. 90.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 2, Dhanbad (Ref. No. 108 of 2004) as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. BCCL and their workmen, which was received by the Central Government on 10.01.2018.

[No. L-20012/96/2004-IR (C-I)]

M. K. SINGH, Section Officer

### ANNEXURE

#### BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO.2), AT DHANBAD

**PRESENT :** Shri R.K.Saran, Presiding Officer

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1) (d) of the I.D. Act, 1947.

#### REFERENCE NO. 108 OF 2004

**PARTIES :** The Vice President,  
Janta Mazdoor Sangh,  
Dugda Coal Washery,  
PO Dugda, Distt: Bokaro-829116

**Vs.**

The General Manager,  
Western Washery Zone of M/s BCCL,  
PO: Mahuda, Dhanbad-826001.

Order No. L-20012/96/2004-IR (C-I) dt.02.09.2004.

#### APPEARANCES :

On behalf of the workman/Union : None

On behalf of the Management : Mr D. K.Verma, Ld. Advocate

State : Jharkhand

Industry : Coal

Dated, Dhanbad, the 16<sup>th</sup> October, 2017

#### AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Sec.10(1)(d) of the I.D. Act.,1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012/96/2004-IR (C-I) dt.02.09.2004.

#### SCHEDULE

Whether the demand of the Janta Mazdoor Sangh from the Management of BCCL, Western Washery Zone to regularize Sri Hari Narayan Chouhan and Megha Lal Gope as supervisor is fair and proper? If so, to what relief/benefit are Shri Hari Naryan Chouhan and Megha Lal Gope entitled and from what date?"

2. Neither the Union Representative nor the workmen concerned are reported to be present on date nor let the evidence of the workman be completed despite a fresh notice dt 12.09.2017 was sent at the address of the Union referred in Order of the Reference itself.Mr.D.K.Verma, Ld. Advocate registered his appearance on the date not for this time but all along since its inception and rolling out as Reference Case .The case is all about denial of the regularization

to the workmen concerned to the posts of supervisors by the Management seeking reliefs there under by staking claim.

On perusal and close scrutiny of the case and materials on record, it has been apparently clear that the Sponsoring Union /workmen seem to be in no hurry to produce the witness to let complete the chapter of evidence of workman even after having availed more than six adjournments or so. The tardy pace of case over evidence of witness appears to have paid off its own purpose as it stayed rolling out over status of producing witness since long time back. The way, the Union Representative /petitioners walk drops points to extract the real conclusion that they are least interested to get to finality of the case through adjudication rather appear much more inclined only for adjournments over the times, Simultaneously the Tribunal also do not see violation of the natural justice to let the case be wrapped up rather rolling over infinity. This also signifies status of the case, as of now, stands crawling over evidence of the workman since 14.12.2005 with no headway in sight. As such proceedings have abruptly stalled over completion of evidence of workman. The case appears to have lost its merits. On this count, it has been viewed not to be a mute spectator to let the situation crawl for a long spell of time rather pushing it for final closure in the line of the principle of natural interest on presumption of non-existent of issue in real sense. So the case is wrapped up as "No Industrial Dispute". Accordingly an 'Award of No Dispute' is passed.

R. K. SARAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2018

**का.आ. 91.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स बी.सी. सी.एल. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. 2, धनबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 82/2015) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10.01.2018 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/100/2015-आई.आर. (सीएम-1)]

एम. के. सिंह, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 10th January, 2018

**S.O. 91.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 2, Dhanbad (Ref. No. 82 of 2015) as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. BCCL and their workmen, which was received by the Central Government on 10.01.2018.

[No. L-20012/100/2015-IR (CM-I)]

M. K. SINGH, Section Officer

## ANNEXURE

### BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO.2), AT DHANBAD

**PRESENT :** Shri R.K.Saran, Presiding Officer

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1) (d) of the I.D. Act, 1947.

#### REFERENCE NO. 82 OF 2015

#### The Secretary

**PARTIES :** Jharkhand Janta Mazdoor Union,  
Vishwakarma Colony, Nutundih  
PO: Jagjivan Nagar, Dhanbad

**Vs.**

The General Manager,  
Western Washery Zone, of M/s BCCL,  
PO: Mahuda, Dhanbad.

**L-20012/100/2015-IR (CM-I) dt 09.10.2015**

#### APPEARANCES :

On behalf of the workman/Union : Mr. P. Mandal, Ld. Rep.  
On behalf of the Management : Mr. Ganesh Pd., Ld. Adv.

State : Jharkhand

Industry : Coal

Dated, Dhanbad, the 25<sup>th</sup> September, 2017**AWARD**

The Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Sec.10(1)(d) of the I.D. Act.,1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. **L-20012/100/2015-IR(CM-I) dt 09.10.2015**.

**SCHEDULE**

“Whether the action of the Management of Western Washery Zone of M/s BCCL in dismissing Sri Somar Chouhan from the services vide office order dated 7/11.12.1997 is fair and justified? To what relief the concerned workman is entitled to?”

On receipt of the Order No. **L-20012/100/2015-IR(CM-I) dt 09.10.2015** of the above mentioned reference from the Government of India, Ministry of Labour & Employment, New Delhi for adjudication of the dispute, the Reference Case No. 82 of 2015 was registered on 26.10.2015 and accordingly an order to that effect was passed to issue notices through the Registered Posts to the parties concerned, directing them to appear in the Court on the date fixed, and to file their written statements along with the relevant documents. In pursuance of the said order, notices by the Registered Posts were sent to the parties concerned.

Both the parties made their appearances and filed their pleadings and photocopies of their documents. The Union/Petitioner and the O.P./Management through their own Ld. Representative / Counsel appeared, and contested the case to the extent the Reference case stands reserved .

2. Here is the case of Ref. No. 82 of 2015 related to the workman Sri Somar Chouhan a permanent employee of Moonidih Coal Washery of M/s BCCL by designation Driver having personnel no. 01298983 had been keeping unblemished track record of service till he had fallen in illness due to which he could not be able to perform his duty w.e.f. 27.1.1996 .After recovery from illness the workman concerned reported for duty to the Management with Medical Certificate but the Management turned down his request and did not allow him to join the duty as the workman was absent due to sickness .However the Management went one step ahead by issuing the charge sheet to the workman on the ground of absentism on 12.03.1997, as the workman do not see misconduct being on absetism under the provisions of the Certified Standing Order an by-laws of the Group of the Collieries of the M/s BCCL exclusively based at Dhanbad .Though the workman submitted his reply against the said alleged charge sheet that led to formation of Enquiry to go the bottom of the facts and, to ascertain the misconduct to the extent the workman had committed .The Enquiry Officer in a biased and prejudiced manner conducted the whole enquiry proceedings which may be termed unfair ,illegal and unjustified and not in the line of principle of natural justice rather came out with guilty of the charges which culminated into much harsher punishment as dismissal by the Disciplinary Authority throwing the workman on the verge of starvation for not fault of his own in view of the petty misconduct of absentism which do not seem rational rather disproportionate to the alleged misconduct of absetism, as stated by the workman in WS .This is certainly not the kind of penalty the worker would expect from the Management. In the enquiry the workman was held guilty of the charge for petty misconduct which is shockingly disproportionate as the dismissal amounts to capital punishment in service arena. Post dismissal the workman made appeal to the Management to dispose of the appeal of the workman in accordance with the provision of the Certified Standing Orders. But arbitrarily and illegally stand the Management had so far, did not yield any consideration. The contention of the Workman was never taken into consideration either by the Enquiry Officer or by the Disciplinary authority. The enquiry outcome is not fair and proper and in accordance of with the principle of the natural justice as alleged by the Workman. The workman was handed out the dismissal letter by the Project Officer of Moonidih Coal Washery on dated 7/11-12-1997. Post dismissal the workman made an fervent appeal to the management for reinstatement but to no avail which is dubbed a violation of the provision of the Certified Standing Order itself. The allegation - misconduct , as came out by the Management was not established during the enquiry nor did workman's petition for prayer take into consideration before imposing harsher punishment of dismissal .So the alleged act of the Management about dismissal stands unjustified and arbitrary, thereby seeking reinstatement into service with full back wages summarily.

3. Contrary to the fact, by categorically denying and brushing aside all allegations of the Union , the OP/Management asserted that the case is not maintainable either in law or in fact as the dispute has been fabricated to twisty suppression and non disclosure of material facts admitting that the workman Sri Somar Chouhan was a permanent employee of Munidih Coal Washery designated as Driver (T),as stated by the Management in its W.S., The workman had started absenting from his duty without information, prior permission or reasonable cause since 27.01.1996,thereby committing a misconduct. The Management asserted that upon framing the said charge sheet dt. 12.03.1997 the workman was asked to reply which was received by the Management on 02.07.1997. After examining

the properly, the reply was not found satisfactory leading to formation of domestic enquiry under Shr B.K.Choubey, then Personnel Officer and Sri T. Chakraborty as Enquiry Officer and Management Representative respectively. The Enquiry Officer issued notice of Enquiry to both the parties to participate in Enquiry proceedings. Though the workman had choice by his side to keep co-worker in his defence but his denial had nothing to do with the option. During the course of enquiry the workman was held guilty of the charges brought in against him. After conducting enquiry the Enquiry Officer submitted report holding the workman guilty under clause 26.1.1. of the Certified Standing Orders of the Company as the charges have been fully established without any doubt. During the course of enquiry proceedings so long his past habitual offender on absentism had been corroborated not by Management Representative but witness also. Further assertion that the dismissal order of the workman had not been merely singled out to one incident alone engulfing therein the whole past track of his service record especially the poor attendances in the past couple of years. as the workman an permanent employee under the Employer had been in the habit of remaining absent without leave and no satisfactory cause. He had turned a habitual offender slowly but steadily. The Said act of absentism as quoted by workman's saying attributed to workman's poor mental state that led to keep the Management grappling in darkness. The Competent Authority having gone through the enquiry proceedings and its findings and related papers fully agreed in principle and thus viewing the past conduct of his attendances and proper application of mind, inflicted the punishment of dismissal from service which is absolutely right, the workman deserved for. So the conduct and manner in which enquiry held never got mired at any stage. And, the dismissal of Sri Somar Chouhan is legally justified and proportionate to the misconduct committed by him. Overall the whole the domestic enquiry conducted by Enquiry officer is fair, proper and in accordance with the principle of natural justice. There is nothing sort of violation of natural justice in the said enquiry.

Not surprisingly, cases of absentism get insignificant, unprecedented and nothing unusual in times so long as Groups of the Collieries under the BCCL Management are concerned as hailing illiteracy backgrounds of workmen, mostly intent to move on prolonged leave. The Misconduct of worker in this regard often run the risk of adversely impacting the morale of the other Workers but matter becomes much more complicated with their involvement. The work nature seems obviously arduous and tedious apart from all time being in hale & hearty in physical structure too to work in the hazardous atmospheres under beneath of several feet or more from the surface. The exodus of the workers from site of working has become a major humanitarian crisis and sparked widely dissent before the Management fraternity that still to realize that they are also part of the production and regards them an indispensable pillar for generations. Summing up, quantum of the punishment as dismissal inflicted upon the workman concerned against the misconduct of absentism appears a little bit harsher and not in proportionate too. So a fresh look on the issue cannot be ruled out.

So, there is nothing improper, unlawful and wrong-doings if the workman be provided a little bit breather. Ultimately in the light of the above, it is ordered for fresh appointment of the workman concerned as Cat. -I with probation up to two years but no back wages, whatsoever.

R. K. SARAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2018

**का.आ. 92.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स बी.सी. सी.एल. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. 2, धनबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 55/2014) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10.01.2018 को प्राप्त हुआ था।

[ सं. एल-20012/104/2014-आईआर (सीएम-1) ]

एम. के. सिंह, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 10th January, 2018

**S.O. 92.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 2, Dhanbad (Ref. No. 55 of 2014) as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. BCCL and their workmen, which was received by the Central Government on 10.01.2018.

[No. L-20012/104/2014-IR (CM-I)]

M. K. SINGH, Section Officer

**ANNEXURE****BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO.2), AT DHANBAD****PRESENT :** Shri R.K.Saran, Presiding Officer

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1) (d) of the I.D. Act, 1947.

**REFERENCE NO 55 OF 2014**

**PARTIES :** The Jt. Gen. Secretary,  
Bahujan Mazdoor Union,  
Mines Rescue Station,  
PO Dhansar, Dhanbad. 828106

**Vs.**

The General Manager,  
E.J.Area of M/s BCCL,  
PO: Bhowra, Dhanbad.828302

Order No. L-20012/104/2014-IR (CM-I) dt.09.10.2014**APPEARANCES :**

On behalf of the workman/Union : None

On behalf of the Management : Mr. U.N. Lal, Ld. Advocate

State : Jharkhand

Industry : Coal

Dated, Dhanbad, the 27<sup>th</sup> October, 2017**AWARD**

The Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Sec.10(1)(d) of the I.D. Act.,1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. **L-20012/104/2014-IR (CM-I) dt.09.10.2014.**

**SCHEDULE**

Whether the action of the Management of Sudamdih Incline Mine of M/s BCCL in dismissing Sri Narayan Lohar , Ex.M .Loader from the services of the Company vide office order dated 07.04.2010 is fair and justified ? To what relief the concerned workman is entitled to?"

2. Neither the workmen concerned nor any one from the Sponsoring Union appeared on date, nor did file the long awaited W.S despite issuance of formal notices dt. 10.11.2014 ,09.03.2015 and ,29.06.2015 at the addresses of both the parties concerned referred in the Order of the Reference itself barring 29.06.2015 which was sent to the Union alone. None came out as Representative of the Management on date but was represented all along by the Ld. Adv. Mr. U.N. Lal. The case deals with dismissal of the workmen by the Management seeking reliefs by challenging it.

On meticulously study of the record concerned it has been absolutely clear the case dates back to the year of 2014 and it has been more than two years or so since it stands to where it was crawling one stage over the years despite adjournment over more than ten times . It appears that the workmen's own initiatives seem to have paid off as the case stayed rolling out over one stage over years .This also signifies to gesture and conduct of the workman concerned that he is no longer interested to contest to the instant case to finality through adjudication rather bent upon to get adjournments .In real sense the case do not seem to have merits as of now , and the very existence Industrial Dispute indeed any more appears to have ceased just because prolonged silence maintained on their part ,Usually, the Tribunal also do share the opinion of let it rolling further will be proved mere wastage of precious time and energy and a hindrance in tackling the backlog of cases. Under these circumstances it would not amount to be unfair, unjust and in line of violation of the natural justice if the instant case is closed on presumption of non-existent of any Industrial Dispute as of now, between the parties concerned. Under such circumstance and facts, the case should be closed as no-existent Industrial Dispute any longer owing to sheer disinterestedness of the Union/workman. Accordingly "No Industrial Dispute" Award is passed.

R. K. SARAN, Presiding Officer



नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2018

**का.आ. 93.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स सेल के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. 2, धनबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 68/2015) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10.01.2018 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-26012/23/2015-आईआर (सीम-1)]

एम. के. सिंह, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 10th January, 2018

**S.O. 93.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 2, Dhanbad (Ref. No. 68 of 2015) as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. SAIL and their workmen, which was received by the Central Government on 10.01.2018.

[No. L-26012/23/2015-IR (CM-I)]

M. K. SINGH, Section Officer

**ANNEXURE****BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO.2), AT DHANBAD****PRESENT :** Shri R.K.Saran, Presiding Officer

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1) (d) of the I.D. Act, 1947.

**REFERENCE NO. 68 OF 2015**

**PARTIES :** Sri R.C. Ram,  
Qr. No. 1099, Sector IX-B,  
PO: Bokaro Steel City, Distt: Bokaro

**Vs.**

The General Manager (P & A)  
SAIL, Bokaro Steel Plant,  
P.O. Bokaro Steel City  
Distt. Bokaro-827001.

Order No. L-26012/23/2015-IR(MI) dt. 23.09.2015**APPEARANCES :**

On behalf of the workman/Union : None

On behalf of the Management : Mr. D. K. Verma, Ld. Advocate

State : Jharkhand

Industry : Steel

Dated, Dhanbad, the 3<sup>rd</sup> October, 2017**AWARD**

The Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Sec.10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. **L-26012/23/2015-IR(M) dt.23.09.2015**

**SCHEDULE**

**“Whether the action of the Management of SAIL /Bokaro Steel Plant in dismissing Sri R.C.Ram from the services of the Company w.e.f. 20/11.8.2011 is fair and justified? If not, to what relief the concerned workman entitled?”**

2. Neither the workman nor any one on behalf of the workman/petitioner is reported to be present on date nor did file the much-awaited WS due on his part on date since long even after serving a fresh notice; whereas Mr. D.K.Verma, LD Advocate for the Management is present. Though Notices dt.5. 9.16, and the last one posting date on 06.01.2016

were mailed to the address of the Sponsoring Union referred in the Order of the Reference itself but all went in vain even. The Management side was also kept informed. The case is related to dismissal from the service of the workman by the Management thereby seeking relief by challenging it.

A through and emphatically scrutiny of the case record, it transpires that the case seems to be stalled over filing the W.S. rest with the workman for over more than two years or so. Even after stepping over the first stage, there seems to be no urgency on the part of the workman to file the much awaited WS despite providing sufficient times as much as more than ten times since 24.02.2016. This indicates to gesture that the workman is no more interested to get the instant case to final adjudication fuelling speculation that the case either must have been resolved out of Court or an issue of non-existent, as of now. Simultaneously the Tribunal do not differ over of the view of keeping the case rolling merely for dates, is of no use rather wastage of time and energy even after adjournments for more than seven times, finally extract the conclusion of closing down for the end of the natural justice. Under these circumstances the case is closed; and an order of the “No Dispute Award” is passed.

R. K. SARAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2018

**का.आ. 94.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स बी.सी.सी.एल. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. 2, धनबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 35/2016) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10.01.2018 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/13/2016-आईआर (सीएम-1)]

एम. के. सिंह, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 10th January, 2018

**S.O. 94.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 2, Dhanbad (Ref. No. 35 of 2016) as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. BCCL and their workmen, which was received by the Central Government on 10.01.2018.

[No. L-20012/13/2016-IR (CM-I)]

M. K. SINGH, Section Officer

#### ANNEXURE

#### BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO.2), AT DHANBAD

**PRESENT :** Shri R.K.Saran, Presiding Officer

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1) (d) of the I.D. Act, 1947.

#### REFERENCE NO 35 OF 2016

**PARTIES :** The Secretary,  
Jharkhand Janta Mazdoor Union,  
Vishwakarma Colony, Nutundih  
PO: Jagjivan Nagar Dhanbad-826003

**Vs.**

The General Manager,  
Lodna Area of M/s BCCL  
PO : Khas Jeengora Dhanbad.

Ministry 's Order No L-20012/13/2016-IR(CM-I) dt 17.06.2016

#### APPEARANCES :

On behalf of the workman/Union : Mr. P. Mandal, Ld. Rep. of the Union

On behalf of the Management : Mr. N.M. Kumar, Ld. Adv.

State : Jharkhand

Industry : Coal

Dated, Dhanbad, the 18<sup>th</sup> September, 2016

**AWARD**

The Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Sec.10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. **20012/13/2016-IR (CM-I) dt 17.06.2016**

**SCHEDULE**

“Whether the action of the Management of Bararee Colliery of M/s BCCL in dismissing Shri Dasrath Ravidas, Prs. No. 101837, Ex-Miner Loader from the services of the Company vide letter No. BBC/95/4450 dated 20.11.1995 is fair and justified? If not, to what relief the concerned workman is entitled?

On receipt of the Order No. **L-20012/13/2016-IR(CM-I) dt 17.06.2016** of the above mentioned reference from the Government of India, Ministry of Labour & Employment, New Delhi for adjudication of the dispute, the Reference Case No. 35 of 2016 was registered on 22.06.2016 and accordingly an order to that effect was passed to issue notices through the Registered Posts to the parties concerned, directing them to appear in the Court on the date fixed, and to file their written statements along with the relevant documents. In pursuance of the said order, notices by the Registered Posts were sent to the parties concerned.

Both the parties made their appearances and filed their pleadings and photocopies of their documents. The Union/Petitioner and the O.P./Management through their own Ld. Rep. /Counsel appeared, and contested the case.

2. This is an another case based on footing of dismissal of the workman of Dasrath Ravidas who was a permanent employee bearing P. No. 101837 designated as the Ex. M/Loader of Bararee Colliery under Lodna Area under the Management of M/s BCCL, a Group of Collieries exclusively based at Dhanbad keeping unblemished track record of service record had abruptly become sick since 16.03.1994 and started absenting but under reported it to the Management accordingly. After recovery when from illness when the workman reported to the Management for resumption of duty, the Management deliberately and illegally did not let him join the duty rather went one step ahead by issuing a charge sheet to the workman on 20.07.1995 against the commission of misconduct as per the provision under the clause of 26.1.1. of the Certified Standing Orders to which the workman replied categorically. The absent itself is not a misconduct as stated by the workman in the WS. The workman was asked to appear before the Enquiry Committees set up to ascertain the root cause of the absence and to go to the bottom of the fact and to the extent of the alleged misconduct committed by the workman in which the workman concerned neither given opportunity to defend his case nor did allow him to give full facts before the Committee as stated by the workman. Thus the enquiry itself had been marred with violation of the natural justice and illegal. The contention of the Workman was never taken into consideration either by the Enquiry Officer or by the Disciplinary authority. The enquiry outcome is not fair and proper and in accordance of with the principle of the natural justice. At last the workman handed out the dismissal letter dated 20.11.1995 by the Competent Authority of the Bararee Colliery of M/s BCCL without giving an option of Second Show Cause Notice and providing a copy of the concluded enquiry report to the workman concerned. Post dismissal the workman made an fervent appeal to the management for reinstatement but to no avail which itself apparently a violation of the provision of the clause 30 the Certified Standing Order. The allegations, as came out by the Management were not established during the enquiry nor did workman's petition for prayer take into consideration before imposing harsher punishment of dismissal. So the alleged act of the Management about dismissal stands unjustified and arbitrary, thereby seeking reinstatement into service summarily.

3. It stands against the contrary to the fact that asserting by the Management at very beginning, “as the I.D. is slate one, so the Union do not have locus-standi of raising the dispute after lapse of twenty years as of now, so the Reference is prime facie not maintainable in-law or facts without any cause of action as claimed by the Management categorically in its W.S. The workman concerned namely Dasrath Rabidas a permanent employee of Bararee Colliery under Lodna Area of M/s BCCL was absenting from duty since 16.03.1994 without any information and permission of the Management which constitutes a grave misconduct on his part of the workman. Though the workman was framed charge sheet against his misconduct asking for reply which was not found satisfactory leading to formation of Domestic Enquiry by Shri Lalan Pandey Dy. Personnel Manager Bararee Colliery as Enquiry Officer. The Committee held the workman guilty of the charges brought in against him as the workman hopelessly had been failure to prove innocence and the cause why he remained absent from duty since long without prior information and permission of the Management. So long as second Show Cause notice was issued to the concerned workman but reply was more or less unsatisfactory. Ultimately with the approval of the competent authority a dismissal letter had been issued to the workman and sent at his home address but the workman knowingly and deliberately refused to receive the same.

4. The said act on absentism on the part of the workman is attracted and termed as misconduct in accordance with clause 26.1.1. of the Certified Standing Order, an by-laws of the Management of the M/s BCCL. Though the Management came out with charge sheet of alleged being remained absentism for prolong period. Since reply remained unsatisfactory, leading to formation of Departmental Enquiry to go to bottom of the fact by the Disciplinary Authority solely in the line of the principle of natural justice. As the workman appeared before the

enquiry and submitted his reply to the said charge sheet. The issue, in quest, was referred the Domestic Enquiry to go to the bottom of the facts and the workman was held guilty of the charges brought against him during the enquiry proceedings. It is an extreme example of gross negligence on the part of the workman who later on turned habitual absentee that got deep rooted leading to his dismissal from service. The alleged act of dismissal from service by the Competent authority has been based on not merely singling out to a specific incident but taking into account the whole aspect of past attendances during his service career and other service relevant matters, too.

Finally, the Competent Authority came forward with handing out the dismissal letter dt. 20.11.1995 only after going through his past history of cases on absentism inclusive this one. Since the workman concerned kept on indulging himself in absentism and turned it into habitual practice with no sign of abating in spite of full force with which the Management did its best not to let the efforts and cohesion go in vain. Thus, neither there was any short of violation of the principle of natural justice, nor did it get mired at any stage as alleged by the petitioner/Union rather the alleged action of dismissal against the workman stands as fair, legal and justified.

5. Though there is nothing unusual and unprecedented event like this one grabbing the headlines since past of couple years as several hundred cases on the same footing happened in the Collieries earlier under the management of BCCL, opened up the whole fiasco between Management and workers over harsher punishment inflicted upon the workers. The work nature of the M/Loader is obviously arduous and tedious apart from the all time being in hale & hearty in physical structure too to work in the hazardous atmospheres under beneath of several fetes or more from the surface where quantum of oxygen sometimes reduces to drastically leading to causality or suffocation. So workman do not hesitate to proceed on prolonged leave even on slightest pretext of reasons on one score or another before stepping into the underground Mines despite safety mechanism in place by the Management. Notwithstanding so much so there was no deterrent to avert the tragic accident in the Mines, and for which mostly workmen are still afraid of. As such the move will not be called unjust and wrong-doings if the workman be provided one more opportunity to reform himself by way of a little breather of fresh appointment.

So it is ordered for fresh appointment of the workman concerned in the lowest grade on proof of his actual identity only with probation rolling over to two years and no back wages whatsoever.

R. K. SARAN, Presiding Officer